



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1984

सूचना

का० आ० 2368—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रामेश्वर दास आलुवालिया, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अम्बाला सिटी (हरियाणा) ने उक्त प्राधिकारी का उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे अम्बाला सिटी में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप हम सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(41)/84-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 5th July, 1984

NOTICE

S.O. 2368.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules,

1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Rameshwar Das Ahluwalia, Advocate, District Courts, Ambala City (Haryana) for appointment as a Notary to practise in Ambala City.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(41)/84-Judl.]

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1984

सूचना

का० आ० 2369—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दत्त सिंह राजपुत एडवोकेट एफ-350, मयूर ब्रिहार, पोस्ट-II दिल्ली-110091 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप हम सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(51)/84-न्या०]

एस० गुप्त, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi the 6th July, 1984

NOTICE

S.O. 2369.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Chhatar Singh Rajput, Advocate, F-350, Mayur Vihar, Pocket II, Delhi-110091 for appointment as a Notary to practise in New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(51)/84-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

चित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1983

(आयकर)

का० आ० 2370.—हम कार्यालय की दिनांक 14-10-82 की अधिसूचना सं० 4949 (फा० सं० 203/211/81-आ०क०नि०-II) के सिमिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

1. यह कि फाउण्डेशन फॉर आर्गेनाइजेशन रिसर्च, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उस द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए, और उससे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों से से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

फाउण्डेशन फॉर आर्गेनाइजेशन रिसर्च नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 16-9-83 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स० 5566/फा० सं० 203/158/83-आ०क०नि०-II]

पी० सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st December, 1983

INCOME TAX

MINISTRY OF FINANCE

S.O. 2370.—In continuation of this office Notification No. 4949 (F. No. 203/211/81-ITA. II) dated 14-10-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the

Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

- (i) That the Foundation for Organisational Research, New Delhi, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Foundation will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Foundation for Organisational Research, New Delhi.

This notification is effective for a period from 16-9-1983 to 31-3-1986.

[No. 5966/F. No. 203/158/83-ITA-II]

P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1984

(आयकर)

का. आ. 2371.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (11) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि शिजोफोनिया रिसर्च फाउण्डेशन (इंडिया), मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरिक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

शिजाफोनिया रिसर्च फाउंडेशन (इंडिया) मद्रास
यह अधिसूचना 26-3-84 से 31-3-86 तक वर्ष
की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं 5838 /फा० सं० 203/75/84-आ० क० नि०-II)]

गिरीश दवे, अवसर सचिव

New Delhi, the 29th May, 1984

INCOME-TAX

S.O. 2371.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Schizophrenia Research Foundation (India), Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said foundation will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Schizophrenia Research Foundation (India), Madras.

This notification is effective for a period from 26-3-84 to 31-3-1986.

[Fo. 5838/F. No. 203/75/84-ITA-II]
GIRISH DAVE, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

का० आ० 2372.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (V) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० कृष्णामूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, मासुति उद्योग लि० 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 को 7 जुलाई, 1984 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एफ० 9/22/84-बी०.ओ०-I)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 7th July, 1984

S.O. 2372.—In pursuance of sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Develop-

ment Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri V. Krishnamurthy, Chairman and Managing Director, Maruti Udyog Ltd., 15, Barakhamba Road, New Delhi-110001, as a Director of the Industrial Development Bank of India with effect from July 7, 1984.

[No. F. 9/22/84-BO. I]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1984

का.आ. 2373.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पाठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री ए. कृष्ण राव को 10 जुलाई, 1984 से आरम्भ होने वाली और 4 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/9/84-बी०.ओ०.-I(1)]

New Delhi, the 9th July, 1984

S.O. 2373.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri A. Krishna Rao as the Managing Director of the Syndicate Bank for a period commencing on July 10, 1984 and ending with September 4, 1986.

[No. F. 9/9/84-BO.I(1)]

का.आ. 2374.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री ए० कृष्ण राव का, जिन्हें 10 जुलाई, 1984 से सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सिंडिकेट बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/9/84-बी०.आ०.-I(2)]

S.O. 2374.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby, appoints Shri A. Krishna Rao who has been appointed as Managing Director of the Syndicate Bank with effect from July 10, 1984 to be the Chairman of the Board of Directors of the Syndicate Bank with effect from the same date.

[F. No 9/9/84-BO.I(2)]

का.आ. 2375.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की उप सचिव कुमारी रंजना राय को श्री अहमद फरीद के स्थान पर स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ.-9/46/83-बी०.ओ०.-I(1)]

S.O. 2375.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, in consultation with the State Bank of India, hereby nominates Kumari Ranjana Ray, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi to be a Director of the State Bank of Hyderabad vice Shri Ahmed Fareed.

[No. F. 9/46/83-BO.I(1)]

का.आ. 2376—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से, एतद्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की उप निचव कुमारी रंजना राय को श्री अहमद फरीद के स्थान पर स्टेट बैंक आफ ट्रावन्कोर के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एफ. 9/46/83-बी.ओ.-I(2)]

ज०ब० मोरचन्दानी, निदेशक

S.O. 2376.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government, in consultation with the State Bank of India, hereby nominates Kumari Ranjana Ray, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi to be a Director of the State Bank of Travancore vice Shri Ahmed Fareed.

[No. F. 9/46/83-BO.I(2)]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

का.आ. 2377—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारीश पर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) के उपबंध 17 सितम्बर, 1984 तक बैंक आफ काचीन, एर्नाकुलम, पर लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/7/84-बी.ओ.-III]

New Delhi, the 11th July, 1984

S.O. 2377.—In exercise of powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 10-B of the said Act shall not apply to the Bank of Cochin Limited, Ernakulam, till the 17th September, 1984.

[No. 15/7/84-B.O. III]

का. आ. 2378—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारीश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि 1 जुलाई, 1984 से प्रारम्भ

होकर 30 जून, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान —

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) और (2) के उपबंध नीचे लिखे बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध बैंकों का प्रबंध उन व्यक्तियों द्वारा किये जाने का प्रतिषेध करते हैं जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का, 1) के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी "कृषिक वित्त निगम लि०" के निदेशक है, और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध नीचे लिखे बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबंध उक्त बैंकों को उपर्युक्त "कृषिक वित्त निगम लि०" के शेयर धारण का प्रतिषेध करते हैं।

क्रम	संख्या	बैंक का नाम
1.		भारतीय स्टेट बैंक
2.		सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
3.		बैंक आफ इंडिया
4.		पंजाब नेशनल बैंक
5.		बैंक आफ बड़ौदा
6.		यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
7.		यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
8.		यूनिफन बैंक आफ इंडिया
9.		बैंक आफ महाराष्ट्र
10.		मिडीकेट बैंक
11.		देना बैंक
12.		केनरा बैंक
13.		इंडियन बैंक
14.		इंडियन ओवरसिज बैंक
15.		ग्राम बैंक

[सं० 15/19/84-बी. ओ. III(1)]

S.O. 2378.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that, during the period commencing on the 1st July, 1984 and ending with the 30th June, 1989—

(a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (C) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to the undernoted banks insofar as the said provisions prohibit the said banks from being managed by persons who are directors of the Agricultural Finance Corporation Ltd., a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and ;

(b) the provisions of sub-section (3) of Section 19 of the said Act shall not apply to the undernoted banks, insofar as the said provisions prohibit the said banks from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Ltd.

Sr No. Name of the bank

1. State Bank of India
2. Central Bank of India
3. Bank of India
4. Punjab National Bank
5. Bank of Baroda
6. United Commercial Bank
7. United Bank of India
8. Union Bank of India
9. Bank of Maharashtra
10. Syndicate Bank
11. Dena Bank
12. Canara Bank
13. Indian Bank
14. Indian Overseas Bank
15. Andhra Bank.

[No. 15/19/84-B.O. III (i)]

का० आ० 2379 बैंककारी विनियम, अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि 1 जुलाई, 1984 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, —

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) और (II) तथा धारा (10) (ख) की उपधारा 2 और (4) के उपखंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि० और बैंक आफ राजस्थान लि० के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबन्ध बैंकों का प्रबंध उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने का प्रतिषेध करते हैं, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी "कृषिक वित्त निगम लि०" के निदेशक हैं, और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध उक्त बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबन्ध उक्त बैंकों को उपर्युक्त "कृषिक वित्त निगम लि०" के शेयर धारण का प्रतिषेध करते हैं।

[संख्या 15/19/84-बी० ओ० -III (ii)]

माधव वैद्य, अवसर सचिव

S.O. 2379.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that, during the period commencing on the 1st July, 1984 and ending with the 30th June, 1989—

(a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (C) of sub-section (1) of section 10 and sub-sections (2) and (4) of section 10-B of the said Act shall not apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd. and the Bank of Rajasthan Ltd., insofar as the said provisions prohibit the said banks from being managed by their chairman by reason of their being the directors of the Agricultural Finance

Corporation Ltd., a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to the said banks insofar as the said provisions prohibit the said banks from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Ltd.

[No. 15/19/84-B.O. III(ii)]

M. R. VAIDYA, Under Secy

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1984

सं० 200/84-सीमाशुल्क

का. आ. 2380 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर जिले के अवनानी तालुक में तेक्कलूर ग्राम को, शतप्रतिशत निर्यात-मुख्य उपकरण बनाने के प्रयोजन के लिए भाण्डागार स्टेसन के रूप में घोषित करता है।

[का० सं० 473/52/84-सीमा 7]

टी० एच० के० गिहारी, अवसर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 21st July, 1984

No. 200/84-CUSTOMS

S.O. 2380.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Thekkalur Village situated in Avanaani Taluk of Coimbatore District in the State of Tamil Nadu to be a warehousing station for the purpose of setting up hundred per cent export-oriented undertaking.

[F No. 473/62/84-CUS. VII]

T. H. K. GHAI, Under Secy.

समाहित विद्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

कलकत्ता, 29 मई, 1984

अधिसूचना सं० 3/के० उ०/1984

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2381 — केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन (जिसमें इसके बाद उक्त नियमावली उल्लिखित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलकत्ता, इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता, के क्षेत्राधिकार में कार्यरत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता के सहायक समाहर्ताओं को अपने मजबूत फाइल में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 196 खख के अधीन समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

[सी० सं० IV (8) 1-के० उ०/82]

नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE

Calcutta, the 29th May, 1984

CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 3/CE/1984.

S.O. 2381.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as "the said Rules"), I, N. K. Bhatnagar, Col-

lector of Central Excise, Calcutta hereby authorise the Assistant Collectors of Central Excise, Calcutta working within the jurisdiction of the collectorate of Central Excise, Calcutta to exercise in their respective jurisdictions the powers of Collector under Rule 196BB of the Central Excise Rules, 1944.

[C. No. IV(8)-1-CE/82]
N. K. BAJPAI, Collector

समाहर्तव्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मध्य प्रदेश
इन्दौर, 3 जुलाई, 1984
अधिसूचना सं० 5/84

का.आ. 2382:—अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (च अ) ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों का अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिये है।

क. अधिकारी का नाम तैनाती स्थान कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

सर्वश्री

- (1) एम०एच०देशमुख अधीक्षक, रेंज-III, 30-5-84
आर०बी०सी०, (पूर्वाह्न)
भिलाई
- (2) एच.डी.सक्सेना अधीक्षक, रेंज-I, 28-5-84
रतलाम (पूर्वाह्न)

[फ०सं० II (3) 5-गोप/84/2966]
एम०के० धर, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M.P.

Indore, the 3rd July, 1984

NOTIFICATION NO. 5/84

S.O. 2382.—Consequent upon their promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B' the following Inspectors of Central Excise (S G) have assumed their charges as Superintendents, Central Excise, Group 'B' with effect from the dates as shown in the table below —

S.No.	Name of the Officer	Place of Posting	Date of Assumption of charge
S/Shri			
1	M.H. Deshmukh	Superintendent, Range-III, R.B.C., Bhilai.	30-5-84(F.N.)
2.	H.D. Saxena	Superintendent, Range-I, Ratlam.	28-5-84(F.N.)

[C. No. II(3)5-Con/84/ 2966]
S. K. DHAR, Collector

ऊर्जा संचालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

का० आ० 2383—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 274(अ) तारीख 20-4-1982 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और अब सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त

भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

उरान टर्मिनल से एम०एच०इन्डि गैस टर्बाइन प्रोजेक्ट भेड़खल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

महाराष्ट्र—राज्य	जिला—रायगढ़	तालुका—उराना			
गांव	सर्वेक्षण नंबर	हेक्टेयर	एअरई	सेटेयर	
भेड़खल	162	3	0	00	1
	161	4	0	01	4
	160	3	0	00	1
	158	3	0	00	1

[स० O-12016/12/82-प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 7th July, 1984

S.O. 2383.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S. O. No. 274(E) dated 20-4-1982 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Uran Terminal to MSEB Gas Turbine Project Bhendkhal.

State-Maharashtra	District-Raigad	Taluka-Uran	
Village	Survey No.	H.No.	Area Hectare-Centare
Bhendkhal	162	3	0-00.1
	161	4	0-01.4
	160	3	0-01.1
	158	3	0-00.1

[No. O-12016/12/82-Prod.]

का०प्रा० 2384—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये पतनपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अद्य पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय पतनपावद्ध घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विश्व व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात	जिला-वडोदरा	तालुका-डमोड	
गांव	प्लॉट नं०	हेक्टेयर	आर सेंटीयर
टीकरीया	77	0	28 32
	64	0	04 32
	74	0	04 48
	65	0	20 80
	66	0	18 76
	67	0	19 20
	58	0	02 40
	57	0	17 76
	56	0	41 62
	56/p	0	24 96
	51	0	00 16
	110	0	21 44
	50	0	36 00
	111	0	11 36
	112	0	24 32
	166	0	22 24
	165	0	21 22
	164	0	26 72
	171	0	28 96

[म० O-12016/65/84-प्रो० एन० जी० डी०-4]

S.O. 2384.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Thukarva	77	0	23	32
	64	0	04	32
	71	0	04	48
	65	0	20	80
	66	0	17	76
	67	0	19	20
	58	0	02	40
	57	0	17	76
	56	0	41	62
	56/P	0	24	96
	51	0	00	16
	110	0	21	44
	50	0	36	00
	111	0	11	36
	112	0	24	32
	166	0	22	24
	165	0	21	22
	164	0	26	72
	171	0	28	96

[No. O-12016/65/84-ONGD-4]

का.प्रा. 3145—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा से वरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आप्रयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों का बिछाने के प्रयोजन के लिये पट्टापावत अनुमोचों में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1952 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उभरे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय पट्टापावत घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उक्त भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आदेश मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आप्रयोग, निर्माण और रखरखाव प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस सविस्तरता की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह गहता है कि उसकी मृतवाह्य व्यक्तिगत हो या किसी निधि वावसायी की मालिक।

अनुमोचों

हजिरा से वरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य	गजरात	जिला	वडोदरा	तालुका	डभोई
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	गजरात	सेन्टीयर	
सुलतानपुरा	11	0	06	56	
	27	0	38	04	

1	2	3	4	5
	28	0	05	28
	26/B	0	10	88
	25	0	11	52
	24	0	05	60
	23	0	00	32
	41	0	16	32
	42	0	03	20
	43	0	15	52
	40	0	03	04
	46	0	65	00
	45	0	00	48
	47	0	38	88
	48	0	02	40
	49	0	08	64
		0	03	76

[सं. O-12016/55/84-ओ.एन.डी.ओ.-4]

S.O. 2385.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District-Vadodra Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sultanpura	11	0	06	56
	27	0	38	04
	28	0	05	28
	26/B	0	10	88
	25	0	11	52
	24	0	05	60
	23	0	00	32
	41	0	16	32
	42	0	03	20
	43	0	15	52
	40	0	03	04
	46	0	65	00

1	2	3	4	5
	45	0	00	48
	47	0	38	88
	48	0	02	40
	49	0	08	64
Cart Track		0	03	76

[No. O-12016/55/84-ONGD-4]

का० प्रा० 2386—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्डोवाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अन्य सब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्डोवाबद्ध घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल, प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिमूर्चना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुताबाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य . गुजरात	जिला . बड़ोदरा	तालुका . वागोडीया		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एकर्स	सेन्टीयर
सांगदोल	168/1	0	17	76
	169/1	0	23	52
	170	0	60	00
	171	0	52	00

[सं० O-12016/64/84-प्रो० एन० जी० सी०-4].

S.O. 2386.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to 486 GI/84-2.

the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vaghodiya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sangdol	168/1	0	17	76
	169/1	0	23	52
	170	0	60	00
	171	0	52	00

[No. O-12016/64/84-ONGD-4]

का० प्रा० 2387—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्डोवाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अन्य सब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्डोवाबद्ध घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिमूर्चना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुताबाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—वेगोडी

गांव	प्लॉट नं०	हेक्टेयर	एकर	सेन्टीयर
बरेली	24	0	14	88
	25	0	32	96
	26	0	36	96
	35	0	11	52
	36	0	33	82
	34	0	06	40
	100	0	43	74

[सं० O-12016/72/84-प्रो. एन जी. सी-4]

S.O.2387.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly—Jagdishpur
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Banaiya	24	0	34	88
	25	0	32	96
	26	0	36	96
	35	0	11	52
	36	0	33	82
	34	0	06	40
	100	0	43	74

[No. O-12016/72/84-ONG-D-4]

का० प्रा० सं० 2388 :—यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्विषयक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और अनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की अपेक्षार (1) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशातः कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर बर भकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विशिष्ट व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची				
हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।				
राज्य—गुजरात	जिला :—बड़ोदरा	तालुका :—डभोई		
गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
बणावरा	965	0	60	00
	964	0	06	08
	952	1	59	16
	काटे ट्रेक	0	04	32
	1150	0	05	12
	1152	0	61	12
	1180	0	12	48
	941	0	42	88
	938	0	46	88
	937	0	09	60
	936	0	37	44
	935	0	06	08
	934	0	00	40
	930 1	0	30	56
	931	0	06	56
	932	0	00	72
	909	0	40	72
	829	0	00	56
	910	0	36	80
	911	0	06	72
	914	0	52	16
	काटे ट्रेक	0	05	76
	879	0	06	56
	878	0	32	32
	872	0	38	08
	873	0	19	52
	काटे ट्रेक	0	04	80
	788	0	20	32
	787	0	00	48
	786/1	0	31	04
	786	0	21	44
	काटे ट्रेक	0	04	76
	760/1	0	44	32
	761	0	04	80
	760/3	0	50	76
	762	0	03	48
	763	0	51	84
	763/1	0	05	76
	756	0	21	76
	676, 677			
	678, 679	0	50	03
	672	0	47	94
	671	0	20	16
	662	0	16	00
	660	0	03	04
	661	0	20	16
	659	0	14	80
	658	0	06	40
	657	"	18	24
	काटे ट्रेक	0	03	30

	1	2	3	4	5
645	0	26			56
646	0	01			80
644	0	31			72
643	0	27			16

[सं० O-12016/68/84-आ. एन. जी. सी-4]

S.O. 2388.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vanadara	965	0	60	00
	964	0	06	08
	952	1	59	16
	Cart Track	0	04	32
	1150	0	05	12
	1152	0	61	12
	1180	0	12	48
	941	0	42	88
	938	0	46	88
	937	0	09	60
	936	0	37	44
	935	0	06	08
	934	0	00	40
	930/1	0	30	56
	93/1	0	06	56
	932	0	00	72
	909	0	40	72

829	0	00	56
910	0	36	80
911	0	06	72
914	0	52	16
Cart Track	0	05	76
879	0	06	56
878	0	32	32
872	0	38	08
873	0	19	52
Cart Track	0	04	80
788	0	20	32
787	0	00	48
786/1	0	31	04
786	0	21	44
Cart Track	0	04	76
760/1	0	44	32
761	0	04	80
760/3	0	50	76
762	0	03	46
763	0	51	84
763/1	0	05	76
756	0	21	76
676, 677,			
678, 679	0	50	03
672	0	47	94
671	0	20	16
662	0	16	00
660	0	03	04
661	0	20	16
659	0	24	80
658	0	06	40
657	0	18	24
Cart Track	0	03	30
645	0	26	26
646	0	01	76
644	0	31	36
643	0	27	04

[No. O-12016/68/84-ONG-D4]

का० आ० 2389...—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वस्तुतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मध्यम प्राधिकारी, नैल तथा प्राकृतिक

गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुर रोड, वडोदरा-७ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति निर्दिष्टित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विश्विष्ट व्यक्तियों की मार्फत।

हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

जन्तुसूची

राज्य—गुजरात	जिला—वडोदरा	तालुका—करजन
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर घार सेन्टीयर
1	2	3 4 5
छछवा	73	0 31 52
	78	0 00 16
	74	0 36 44
	75	0 19 04
	72	0 17 18
	69/3	0 37 66
	89	0 00 24
	89/1	0 13 92
	90	0 32 80
	88/2	0 02 08
	111/2	0 53 12
	112/1	0 05 28
	111/1	0 26 22
	109	0 28 00
	106/1	0 04 80
	106	0 00 18
	110	0 11 52
	103/2	0 20 18
	103/3	0 25 60
	103/1	0 23 52
	103/4	0 26 40
	104	0 02 56
	140	0 17 28
	141	0 14 88
	143/2	0 01 60
	113	0 34 40
	166/2	0 00 48
	166/1	0 21 12
	165	0 13 16
	164	0 18 08
	177	0 45 60
	171	0 00 16
	176	0 18 80
	182/2	0 08 16
	182/1	0 34 24
	184	0 11 68
	181/1/ए	0 00 20
	185	0 10 88
	186	0 13 12
	187	0 00 10
	187/1	0 32 16
	188	0 16 40
	199/2	0 01 60
	306	0 20 16
	226	0 00 16

S.O. 2389.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Karjan

Village	Survey No	Hectara	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chanchava	73	0	31	52
	78	0	00	16
	74	0	36	44
	75	0	19	04
	72	0	17	18
	69/3	0	37	66
	89	0	00	24
	89/1	0	13	92
	90	0	32	80
	88/2	0	02	08
	111/2	0	53	12
	112/1	0	05	28
	111/1	0	26	22
	109	0	28	00
	106/1	0	04	80
	106	0	00	48
	110	0	11	52
	103/2	0	20	48
	103/3	0	25	60
	103/1	0	23	52
	103/4	0	26	40
	104	0	02	56
	140	0	17	28
	141	0	14	88
	143/2	0	01	60
	143	0	34	40
	166/2	0	00	48
	166/1	0	21	12
	165	0	13	16
	164	0	18	08
	177	0	45	60
	174	0	00	16

1	2	3	4	5
	176	0	18	80
	182/2	0	08	16
	182/1	0	34	24
	184	0	11	68
	181/1/A	0	00	20
	185	0	10	88
	186	0	13	12
	187	0	00	10
	187/1	0	32	16
	188	0	16	40
	199/2	0	01	60
	306	0	20	16
	266	0	00	16

[No O-12016/59/84-ONG-D-4]

का० प्रा० 3390.—यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—वडोदरा	तालुका—डबोई		
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
राजली	311	0	05	46
	313	0	27	68
	318	0	12	16
	316	0	17	28
	315	0	17	12
	331	0	41	62
	332	0	26	56
	333	0	17	04
	334	0	22	88
	335	0	01	44

S.O. 2390.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiar
Rajali	311	0	05	46
	313	0	27	68
	318	0	12	16
	316	0	17	28
	315	0	17	12
	331	0	41	62
	332	0	26	56
	333	0	17	04
	334	0	22	88
	335	0	01	44

[No. O-12016/59/84-ONG-D-4]

का० प्रा० 3391.—यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं० O-12016/57/84-ओ. एन. जी. डी-4]

अनुसूची				
हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।				
राज्य—गुजरात	जिला—वडोदरा	तालुका—करजण		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कोठाव	95	0	10	56
	96	0	09	12
	97	0	20	64
	98	0	18	88
	99	0	07	04
	100	0	17	76
	91	0	22	56
	103	0	04	64
	90/1	0	00	16
	89	0	24	64
	88/2	0	09	44
	87	0	33	76
	86	0	01	44
	116	0	00	16
	119	0	21	12
	67	0	15	84
	66/1/पी	0	07	68
	66/1/पी } 66/2/पी } 66/2/पी }	0	39	68
	123/9	0	03	04
	123/10	0	13	12
	123/11	0	10	40
	123/12	0	13	12
	123/13/ए	0	16	00
	123/13/बी	0	08	00
	125	0	08	96
	126	0	11	04
	127	0	09	60
	128	0	04	80
	129	0	14	56
	130	0	14	72
	131	0	11	36
	132	0	03	04
	138	0	19	20
	137/1/2	0	04	00
	35-36/1,2	0	36	24
	26	0	04	00
	27/1	0	10	72
	27/2	0	11	04
	27/3	0	11	20
	27/4	0	12	00
	27/5	0	11	36
	28/1	0	20	80
	28/2	0	45	76
	28/3	0	00	08
	16	0	60	80
	10	0	04	80
	11	0	21	60
	12	0	16	48

1	2	3	4	5
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/पी	0	14	72
	375	0	05	12

[सं० O-12016/58/84-प्रो. एन. जी. सी-4]

S.O. 2391.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly to Jagdishpur
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centare
1	2	3	4	5
Kothav	95	0	10	56
	96	0	09	12
	97	0	20	64
	98	0	18	88
	99	0	07	04
	100	0	17	76
	91	0	22	56
	103	0	04	64
	90/1	0	00	16
	89	0	24	64
	88/2	0	09	44
	87	0	33	76
	86	0	01	44
	116	0	00	16
	119	0	21	12
	67	0	15	84
	66/1/P	0	07	68
	66/1/P } 66/2/P } 66/2/P }	0	39	68
	123/9	0	03	04

1	2	3	4	5
	123/10	0	13	12
	123/11	0	10	40
	123/12	0	13	12
	123/13/A	0	16	00
	123/13/B	0	08	00
	125	0	08	96
	126	0	11	04
	127	0	09	60
	128	0	04	80
	129	0	14	56
	130	0	14	72
	131	0	11	36
	132	0	03	04
	138	0	19	20
	137/1/2	0	04	00
	35			
	36/1,2) }	0	36	24
	26	0	04	00
	27/1	0	10	72
	27/2	0	11	04
	27/3	0	11	20
	27/4	0	12	00
	27/5	0	11	36
	28/1	0	20	80
	28/2	0	45	76
	28/3	0	00	08
	16	0	60	80
	10	0	04	80
	11	0	21	60
	12	0	16	48
	13	0	00	32
	8	0	00	80
	9/1	0	19	68
	9/2/P	0	14	72
	375	0	05	12

[No. O-12016/58/84-ONG-D-4]

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

का०आ० 2392.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जे आर. ई. मे जे. आर. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पात्र अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962

का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जे. आर. ई. से जे. आर. एफ. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात जिला :— मेहसाना तालुका :— कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर आर	सेन्टीयर
मेरडा	1	0	02 00
	8	0	05 25
	11	0	31 56
	9	0	06 18
	228/1 + 2	0	07 65
	255/1	0	01 20
	254	0	07 20
	253/1	0	05 55
	253/2	0	07 74
	238	0	04 50
	239	0	04 50
	240	0	03 00
	247/1	0	01 00

[सं. O-12016/52/84-ऑ. एन. जी. डी.-4]

New Delhi, the 11th July, 1984

S.O. 2392.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JRE to JRF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JRE to JRF

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Merda	1	0	02	0
	8	0	05	0
	11	0	31	0
	9	0	06	18
	228/1+2	0	07	65
	255/1	0	01	20
	254	0	07	20
	253/1	0	05	55
	253/2	0	07	74
	238	0	04	50
	239	0	04	50
	240	0	03	00
	247/1	0	01	00

[No. O-12016/52/84-O NGD-4]

का० आ० 2393.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जे. एल. बी. (जे-17) से जे. आर. एफ. (जे-36) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी जमीनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आदेश एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जे. एल. बी. (जे-17) से जे. आर. एफ. (जे-36)

राज्य : गुजरात जिला :— मेहसाना तालुका कडि

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर ए आर ई सेंटीयर		
मेरडा	266/2	0	02	00
	268	0	07	95
	269	0	09	00
	271/1	0	03	00
	271/2	0	10	05
	250	0	10	74
	251	0	06	00
	249	0	09	45

[मं. O-12016/53/84-ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 2393.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JLB(J-17) to JRF (J-36) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JLB(J.17) to JRF(J.36)

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Merda	266/2	0	02	00
	268	0	07	95
	269	0	09	00
	271/1	0	03	00
	271/2	0	10	05
	250	0	10	74
	251	0	06	00
	249	0	09	45

[No. O 12016/53/84-O NGD-4]

का. आ. 2394.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम

के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी भुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से अगदीणदर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात जिला :— बड़ोदरा तालुका :— डभोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर एआरई	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
टिमबरवा	865	0	11	40
	864	0	20	00
	863	0	00	40
	868	0	16	00
	869	0	09	60
	870/1	0	02	10
	870/2	0	13	00
	871	0	07	70
	872	0	36	00
	877	0	09	10
	875	0	17	60
	896/2	0	44	00
	896/1	0	02	03
	897	0	08	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	60
	898	0	08	00
	945/1	0	12	00
	945/2	0	04	80

1	2	3	4	5
	944	0	24	60
	937	0	02	00
	938	0	61	00
	941/1	0	11	00
	942	0	01	60
	941	0	08	60
	1091	0	17	60
		0	06	08

[सं० O-12016/54/84-ओ० एन० जी०-डी०-4]

S.O. 2394.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Shinor

Village	Survey No.	Hectare	ARE	Centiare
1	2	3	4	5
Timbarva	865	0	11	40
	864	0	20	00
	863	0	00	40
	868	0	16	00
	869	0	09	60
	870/1	0	02	10
	870/2	0	13	00
	871	0	07	70
	872	0	36	00
	877	0	09	10
	875	0	17	60
	896/2	0	44	00
	896/1	0	02	03
	897	0	08	00
	Cart Track	0	01	60
	898	0	08	00
	945/1	0	12	00
	945/2	0	04	80
	944	0	24	60
	937	0	02	00
	938	0	61	00

1	2	3	4	5
	942/1	0	11	00
	942	0	01	60
	941	0	08	60
	1091	0	17	60
	Kans	0	06	08

[No. O-12016/54/84-ONG-D-4]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

का०आ० 2395.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदप्राप्त अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित या है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :— गुजरात जिला: बड़ोदरा तालुका: डभोई

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर एआरई	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
जीयातलावड़ी	कार्ट ट्रैक	0	03	96
	283	0	27	20
	284	0	01	76
	290	0	00	32
	282	0	24	48
	281	0	09	92
	280	0	09	12

1	2	3	4	5
	277	0	25	60
	272	0	11	20
	273	0	11	20
	274	0	04	00
	268	0	04	64
	257	0	00	96
	275	0	22	00
	264/1	0	04	48
	264/2	0	06	40
	262	0	09	44
	261	0	12	62
	263/1	5	07	20
	263/2	0	03	52
	95	0	14	50
	Kharabo	0	03	50

[सं. O-12016/61/84-ओ. एन० जी.-डी.-4]

New Delhi, the 12th July, 1984

S.O. 2395.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Dabhoi		
Village	Survey No.	Hectare	Aro	Centiare
1	2	3	4	5
JIVATALAVADI	Cart Track	0	03	96
	283	0	27	20
	284	0	01	76
	290	0	00	32
	282	0	24	48
	281	0	09	92
	280	0	09	12
	277	0	25	60
	272	0	11	20
	273	0	11	20
	274	0	04	00

1	3	4	5	1	2	3	4	5
268	0	04	64		56	0	33	12
257	0	00	96		57	0	00	16
275	0	22	00		67	0	29	28
264/1	0	04	48		68	0	17	60
264/2	0	06	40		69	0	21	60
262	0	09	44		70	0	17	60
261	0	12	62		73	0	07	20
263/1	0	07	20		74	0	00	16
263/2	0	03	52		72	0	20	00
95	0	14	50		71	0	04	48
Kharabo	0	03	50		कार्ट ट्रैक	0	06	40

[No. O-12016/61/84-ONG-D-4]

का. आ. 2396.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : डभोई

गाव	मर्चे नं.	हक्केदार एआरई	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
पारिवोला	54	0	08	16
	38	0	07	68
	53	0	32	00

[सं. O-12016/66/84-ऑ. एन. जी. डी.-4]

S.O. 2396.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	ARE	Centiare
1	2	3	4	5
Parikha	54	0	08	16
	38	0	07	68
	53	0	32	00
	56	0	33	12
	57	0	00	16
	67	0	29	28
	68	0	17	60
	69	0	21	60
	70	0	17	60
	73	0	07	20
	74	0	00	16
	72	0	20	00
	71	0	04	48
Cart Track		0	06	40
	306	0	02	56
	308	0	16	00
	305	0	31	20
	304	0	00	80
	188	0	05	76
	189	0	33	82
	190	0	13	60
	191	0	00	80
	205	0	00	32
	204	0	16	32
	203	0	13	60
	202	0	13	12
	201	0	06	08
	215	0	08	80
	216	0	05	44
	217	0	02	56
	218	0	33	12
	277	0	13	12
	232	0	11	84
	233	0	17	60
	274	0	09	60
	2 36	0	22	56
	235	0	11	20
	237	0	08	00
	152	0	04	00
Boundary		0	06	00

[No. O-12016/66/84-ONG D-4]

का. आ. 2397.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 की इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : डभोई

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	ए.आर.ई.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
	119 ए	0	37	12
	119 बी	0	02	32
	116	0	28	00
	87	0	02	88
	112	0	08	96
	111	0	08	64
	107	0	05	52
	109	0	00	32
	108	0	06	40
	106	0	00	88
	103	0	14	76
	37	0	09	12
	39	0	29	52
waste land		0	11	68
	42	0	03	44
	43	0	29	88
	44	0	25	88
	48	0	02	36
	57	0	43	72
	66	0	39	20
	60	0	00	26
	63	0	01	12

1	2	3	4	5
	49	0	11	68
	64	0	35	68
	62	0	12	80
waste land	0	02	32	

[स. O-12016/67/84-ओ. एन. जी. -डी.-4]

S.O. 2397.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabho i
Village Block No. Hectare ARE Centiare

1	2	3	4	5
Abcalpura	119/A	0	37	12
	119/B	0	02	32
	116	0	28	00
	87	0	02	88
	112	0	08	96
	111	0	08	64
	107	0	05	52
	109	0	00	32
	108	0	06	40
	106	0	14	88
	103	0	09	76
	37	0	29	12
	39	0	11	52
	Waste land	0	03	68
	42	0	29	44
	43	0	25	88
	44	0	02	88
	48	0	43	36
	57	0	26	72
	66	0	39	20
	60	0	00	26
	63	0	01	12
	49	0	11	68
	64	0	35	68
	62	0	12	80
	Waste land	0	02	32

[No. O-12016/67/84-ONG D-4]

का. आ. 2398.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा मे बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हों या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्यः— गुजरात जिलाः— बडोदरा तालुकाः—डमोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
बाधदपुरा	7	0	01	12
	8	0	35	96
	10	0	24	16
	18	0	13	72
	19/1	0	02	08
	19	0	11	56
	17	0	05	76
	21	0	10	20
	22	0	20	48
	29	0	18	56
	28	0	10	28
	48 पी	0	16	00
	48	0	02	08
	49	0	00	48
	47	0	10	24
	46	0	22	88

1	2	3	4	5
	50	0	27	08
	51	0	18	24
	52	0	22	24
	53	0	03	04
	54	0	04	64
	323	0	27	48

[सं. O-12016/69/84-ओ. एन. जी. डी.-4]

S.O. 2398.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Survey No.	Hectare	ARE	Centiare
Vayadpura	7	0	01	12
	8	0	35	96
	10	0	24	16
	18	0	13	72
	19/1	0	02	08
	19	0	11	56
	17	0	05	76
	21	0	10	20
	22	0	20	48
	29	0	18	56
	28	0	10	28
	48/P	0	16	00
	48	0	02	08
	49	0	00	48
	47	0	10	24
	46	0	22	88
	50	0	27	08
	51	0	18	24
	52	0	22	24
	53	0	03	04
	54	0	04	64
	323	0	27	48

[No. O-12016/69/84-ONGD-4]

का. आ. 2399.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायबद्ध अनुभूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्यः— गुजरात जिलाः— बड़ोदरा तालुकाः—डभोई

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	एआरडी	सेन्टीयर
नारीया	466	0	03	64
	474	0	30	56
	473	0	10	72
	468	0	10	40
	469	0	11	84
	472	0	28	32
	528	0	19	68
	529	0	21	60
	530	0	38	56
	538	0	23	20
	471	0	01	60
	536/2	0	43	04
	534	0	23	20
	535	0	03	84
	561/1	0	18	46
	561/2	0	20	96
	559	0	26	40
	558	0	10	72
	560	0	08	96

[सं. ओ-12016/71/84-ओ. एन. जी. डी. 4]

पी. के. राजागोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 2399.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State: Gujarat District: Vadodara Taluka: Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	ARE	Centiare
Nariya	466	0	03	64
	474	0	30	56
	473	0	10	72
	468	0	10	40
	469	0	11	84
	472	0	28	32
	528	0	19	68
	529	0	21	60
	530	0	38	56
	538	0	23	20
	471	0	01	60
	536/2	0	43	04
	534	0	23	20
	535	0	03	84
	561/1	0	18	46
	561/2	0	20	96
	559	0	26	40
	558	0	10	72
	560	0	08	96

[No. O-12016/71/84-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारत

बम्बई, 30 जून, 1984

कां.अं. 2400 —परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 27 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि नीचे स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कार्यालयों/परियोजनाओं/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाले अधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा (26) (1) (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाले अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम	कार्यालयों/परियोजनाओं/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिवालय, छत्रपति शिवाजी महा-राज मार्ग, बम्बई-100039	(1) सभी निदेशक/उप सचिव (2) उप सुरक्षा अधिकारी (3) सुरक्षा अधिकारी
2.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, बम्बई-400085	(1) प्रभागध्यक्ष (2) मुख्य सुरक्षा अधिकारी (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (4) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (5) सुरक्षा अधिकारी
3.	विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनः-समाधान संयंत्र (भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र), तारापुर, जिला थाणे-401504	(1) प्रशासनिक अधिकारी iii (2) उा मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (3) सुरक्षा अधिकारी
4.	भारी पानी परियोजनाएं बम्बई	(1) प्रबन्धक, योजना तथा समन्वय तथा (2) प्रशासनिक अधिकारी
5.	नामिकीय ईंधन गमिश्र, हैदराबाद	(1) उप मुख्य कार्यकारी (प्रशासन) (2) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (3) सुरक्षा अधिकारी
6.	विद्युत परियोजना अभियांत्रिक प्रभाग, बम्बई	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
7.	रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र, जिला चेन्नलपट्ट, कलपाक्कम, तमिल-नाडु	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और लेखा अधिकारी तथा (2) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
8.	परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद	(1) वरिष्ठ प्रशासनिक तथा लेखा अधिकारी और (2) सुरक्षा अधिकारी
9.	परमाणु खनिज प्रभाग के उत्तरी क्षेत्रीय/पूर्वी क्षेत्रीय/वर्षा क्षेत्रीय/पश्चिमी क्षेत्रीय/उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जोकि अमरावती, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, नागपुर तथा शिलांग में स्थित हैं।	(1) संबंधित क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी
10.	तारापुर परमाणु बिजलीघर, तारापुर जिला थाणे—401504	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (2) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (3) सुरक्षा अधिकारी
11.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर, फांटा, राजस्थान	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (2) मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (3) सुरक्षा अधिकारी
12.	मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम, जिला चेन्नलपट्ट, तमिलनाडु	(1) मुख्य प्रशासनिक तथा लेखा अधिकारी (2) प्रशासनिक अधिकारी तथा (3) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1	2	3
13	नरीरा परमाणु विद्युत परियोजना, नरीरा, उत्तर प्रदेश	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (2) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा (3) सुरक्षा अधिकारी
14	ककरावार परमाणु विद्युत परियोजना, ककरावार, गुजरात	(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
15	भारी पानी संयंत्र, बड़ोदा, गुजरात	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
16	भारी पानी संयंत्र, कोटा राजस्थान	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
17	भारी पानी संयंत्र, तर्वा हारिन, तमिलनाडु	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
18	भारी पानी संयंत्र, मल्लार उड़ीसा	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) निरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
19	भारी पानी परियोजनाएं, मानुगु, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
20	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डाकखाना जादुगोडा, जिला मिहभूम, बिहार	(1) प्रबंधक (कार्मिक तथा प्रशासन) तथा (2) सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
21	इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बेरगावल्ली, हैदराबाद	(1) प्रधान कार्मिक वर्ग तथा (2) मुख्य सुरक्षा अधिकारी
22	इंडियन रेक्टर अर्थ लिमिटेड बम्बई	(1) प्रशासनिक अधिकारी तथा (2) सुरक्षा अधिकारी
23	इंडियन मेअर अर्थ लिमिटेड उगोमडल, आन्ध्र, केरल	सुरक्षा अधिकारी
24	इंडियन रेक्टर अर्थ लिमिटेड, मिनरल ट्रेडिंग प्लॉट, चवारा, करनापापल्ली ताल्लुक, जिला त्रिचलान, केरल	सुरक्षा अधिकारी
25	इंडियन रेक्टर अर्थ लिमिटेड, मिनरल ट्रेडिंग प्लॉट, मानवला- कुरची, जिला कल्याकुमारी, तमिलनाडु	सुरक्षा अधिकारी

[गं० एईए/27/1/83-ई आर]

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Bombay, the 30th, June, 1984

S.O. 2400.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers conferred under Section 26(1)(b) of the Act shall in respect of jurisdiction falling under the Offices/Projects/Public Sector Undertakings specified in Column 2 of the Schedule below, be exercisable by the authorities mentioned in the corresponding entries in Column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Offices/ Projects/Public Sector Undertakings	Designation of the Authority
1	2	3
1.	Department of Atomic Energy Secretariat Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-400039.	(i) All Directors /Deputy Secretaries (ii) Deputy Chief Security Officer (iii) Security Officer
2.	Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Bombay-400085.	(i) Heads of the Divisions (ii) Chief Security Officers (iii) Sr. Administrative Officer (iv) Deputy Chief Security Officers and (v) Security Officers
3.	PREFRE (Bhabha Atomic Research Centre), Tarapur, Dist. Thane-401504.	(i) Administrative Officer-III (ii) Deputy Chief Security Officers and (iii) Security Officers
4.	Heavy Water Projects, Bombay.	(i) Manager, Planning & Coordination and (ii) Administrative Officer
5.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	(i) Deputy Chief Executive (Adm.) (ii) Deputy Chief Security Officer and (iii) Security Officers
6.	Power Projects Engineering Division, Bombay.	(i) Chief Administrative Officer and (ii) Security Officers
7.	Reactor Research Centre, Dist. Chingalput, Kalpakkam, Tamil Nadu.	(i) Chief Administrative & Accounts Officer and (ii) Assistant Commandant, CISF.
8.	Atomic Minerals Division, Hyderabad.	(i) Sr. Administrative & Accounts Officer and (ii) Security Officer
7.	Atomic Minerals Division Northern Regional/Eastern Regional/Southern Regional/Western Regional/Northern Eastern Regional Offices at New Delhi, Calcutta, Bangalore, Nagpur and Shillong respectively.	(i) Security Officers of the concerned Region.
10.	Tarapur Atomic Power Station, Tarapur, Dist. Thane-401504	(i) Chief, Administrative Officer (ii) Deputy Chief Security Officer and (iii) Security Officers
11	Rajasthan Atomic Power Station, Kota, Rajasthan.	(i) Chief Administrative Officer (ii) Chief Security Officer and (iii) Security Officer

1	2	3
12. Madras Atomic Power Station, Kalpakam, Distt. Chingalput, Tamil Nadu.	(i) Chief Administrative & Accounts Officer (ii) Administrative Officer and (iii) Assistant Commandant,	
13. Narora Atomic Power Project, Narora, U.P.	(i) Chief Administrative Officer (ii) Deputy Chief Security Officer and (iii) Security Officer	
14. Kakrapar Atomic Power Project, Kakiapar, Gujarat.	(i) Chief Administrative Officer and (ii) Assistant Commandant, CISF.	
15. Heavy Water Plant, Baroda, Gujarat.	(i) Administrative Officer and (ii) Security Officer	
16. Heavy Water Plant, Kota, Rajasthan.	(i) Administrative Officer and (ii) Security Officer	
17. Heavy Water Plant, Tuticorin, Tamil Nadu.	(i) Administrative Officer and (ii) Security Officer	
18. Heavy Water Plant, Talcher, Orissa.	(i) Administrative Officer and (ii) Inspector, CISF	
19. Heavy Water Projects Manuguru Dist. Khammam, Andhra Pradesh.	(i) Administrative Officer and (ii) Security Officer	
20. Uranium Corporation of India Ltd., P.O. Jaduguda, Dist. Singhbhum, Bihar.	(i) Manager (Personnel and Administration) and (ii) Assistant Commandant CISF.	
21. Electronics Corporation of India Ltd., Cherlapalli, Hyderabad.	(i) Head, Personnel Group and (ii) Chief Security Officer	
22. Indian Rare Earths Ltd., Bombay.	(i) Administrative Officer and (ii) Security Officers	
23. Indian Rare Earths Ltd., Udyogmandal, Alwaye, Kerala.	Security Officer	
24. Indian Rare Earths Ltd., Minerals Dressing Plant, Chawara, Karunagapally Taluk, Dist. Quilon, Kerala.	Security Officer	
25. Indian Rare Earths Ltd., Mineral Dressing Plant, Manavalakurchi, Kanyakumari Dist., Tamil Nadu.	Security Officer	

[No. AEA/27/1/83-ER]

प्रादेश

कांआ० 2401:—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 27 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
486 GI/84—4

केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि नीचे स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कार्यालयों/परियोजनाओं/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा (26) (1) (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	कार्यालयों/परियोजनाओं/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3
1.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई 400085	निदेशक
2.	भारी पानी परियोजनाएं, बंबई	मुख्य कार्यकारी
3.	नाभिक्रिय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद	मुख्य कार्यकारी
4.	विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग, बम्बई	निदेशक
5.	परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद	निदेशक
6.	ग्रीकटर अनुसंधान केन्द्र, कलपाकम तमिलनाडु	निदेशक
7.	तारापुर परमाणु बिजलीघर, तारापुर, महाराष्ट्र, राज्य	मुख्य अधीक्षक
8.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर, कोटा, राजस्थान	स्टेशन अधीक्षक
9.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, कलपाकम, तमिलनाडु	परियोजना निदेशक
10.	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना, नरोरा, उत्तर प्रदेश	परियोजना निदेशक
11.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, ककरापार, गुजरात	परियोजना, निदेशक
12.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई-20	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
13.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
14.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोडा जिला सिंहभूम, बिहार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
15.	भारी पानी संयंत्र, कोटा	कार्य प्रबन्धक
16.	भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा	कार्य प्रबन्धक
17.	भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन	कार्य प्रबन्धक
18.	भारी पानी संयंत्र, तलचर	कार्य प्रबन्धक
19.	भारी पानी, सयल, मानसरोवर	निर्माण प्रबन्धक

अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 तथा 17 (4) के अन्तर्गत प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने-अपने यूनिटों से अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 8, 14 तथा 17 के अधीन प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने में भी सक्षम होंगे।

[सं. एईए/27/1/83-ई प्रार.]

एन. जयरामन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 2401. -In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Atomic Energy Act 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers conferred under Section 26(1)(a) of the Act shall in respect of jurisdiction falling under the Offices/Projects/Public Sector Undertakings specified in column 2 of the schedule below, be exercisable by the authorities mentioned in the corresponding entries in column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Offices/ Projects/ Public Sector Undertakings	Designation of the Authority
1	2	3
1.	Bhabha Atomic Research Centre, Bombay-400085.	Director
2.	Heavy Water Projects, Bombay.	Chief Executive
3.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.	Chief Executive
4.	Power Projects Engineering Division, Bombay.	Director
5.	Atomic Minerals Division, Hyderabad.	Director
6.	Reactor Research Centre, Kalpakkam, Tamil Nadu.	Director
7.	Tarapur Atomic Power Station, Tarapur, Maharashtra State.	Chief Superintendent
8.	Rajasthan Atomic Power Station, Kota, Rajasthan	Station Superintendent
9.	Madras Atomic Power Project, Kalpakkam, Tamil Nadu.	Project Director
10.	Narora Atomic Power Project, Narora, U.P.	Project Director

1	2	3
11.	Kakrapar Atomic Power Project, Kakrapar, Gujarat.	Project Director
12.	Indian Rare Earths Ltd., Bombay-20.	Chairman-cum-Managing Director
13.	Electronics Corporation of India Ltd. Hyderabad.	Chairman-cum-Managing Director
14.	Uranium Corporation of India Ltd. Jaduguda, Dist. Singhbhum, Bihar.	Chairman-cum-Managing Director
15.	Heavy Water Plant, Kota.	Works Manager
16.	Heavy Water Plant, Baroda.	Works Manager
17.	Heavy Water Plant, Tuticorin.	Works Manager
18.	Heavy Water Plant, Talcher.	Works Manager
19.	Heavy Water Plant, Manuguru.	Construction Manager.

In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Act, the Central Government directs that the authorities mentioned in Column 3 of the above schedule shall also be the competent authorities to appoint officers from their respective units to exercise power of entry and inspection under section 8 and 17(4) of the Act. The officers so appointed will also be competent to exercise the general powers conferred under Section 8, 14 and 17 of the Atomic Energy Act 1962.

[No. AEA/27/1/83-ER]

N. JAYARAMAN, Jt. Secy.

राष्ट्र और नागरिक प्रति मंत्रालय

(नागरिक प्रति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 29 जून, 1984

क्र. भा. 2402.—भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सूत लपेटने के कागज के कोनों की मानक डिजाइन में कुछ संशोधन किया गया है। इन मानक चिह्नों की संशोधित डिजाइन, ग्राफिक विवरण तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं।

ये मानक डिजाइन भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित्त 1983-05-16 से लागू होंगी।




अनुसूची

क्रम	मानक चिह्न की डिजाइन संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का ग्राफिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4888 (Part I) — कोन आंशिक	सूत लपेटने के लिए कोन	IS. 4888 (भाग 1) — 1982 सूत लपेटने के कोनों की विशिष्ट भाग 1 कोन का भ्रष्ट कोण 3° 30' (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें IS शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गये और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की संख्या और उसके नाम तथा शब्द "कोन आंशिक" प्रकट किए गए हैं।

IS:4888(PART I) 2



COPY ONLY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. IS 4888 (भाग II) कोन घोलनी	सूत लपेटने के कोन	IS 4888 (भाग 2)—1982 सूत लपेटने के कोनो की विशिष्टि : भाग 2 कोन का अर्ध-कोण $4^{\circ} 20'$ (दूसरा पुनरीक्षण)		
IS 4888 (PART II)  CONE ONLY				
3. IS : 4888 (भाग III) कोन घोलनी		IS 4888 (भाग 3)—1982 सूत लपेटने के कोनो की विशिष्टि : भाग 3 कोन का अर्ध-कोण $5^{\circ} 57'$ (दूसरा पुनरीक्षण)		
IS 4888 (PART III)  CONE ONLY				
4. IS : 4888 (भाग 4)— कोन घोलनी	"	IS : 4888 (भाग 4)—1982 सूत लपेटने के कोनो की विशिष्टि भाग 4 कोन का अर्ध-कोण $9^{\circ} 15'$ (दूसरा पुनरीक्षण)		
IS 4888 (PART IV)  CONE ONLY				

[सं. सी० एम० डी०/13 : 9]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)





INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 29th June, 1984

S.O. 2402.—Indian Standards Institution, hereby, notifies that the design of the Standard Mark for paper cones for winding yarn has been revised. The revised designs of the Standard Marks together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the designs are given in the following Schedule.

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1983-05-16 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS 4888 (PART I)  CONE ONLY	Cones for yarn winding	IS : 4888 (Part I)-1982 Specification for cones for yarn winding. Part I Half angle of the cone $3^{\circ} 30'$ (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Co., (2); the number of the Indian standard, along with its parts, being superscribed on the top side and the words 'CONE ONLY' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.
2.	IS 4888 (PART II)  CONE ONLY	Cones for yarn winding	IS : 4888 (Part II)-1982 Specification for cones for yarn winding : Part II Half angle of the cone $4^{\circ} 20'$ (second revision)	
3.	IS 4888 (PART III)  CONE ONLY	-do-	IS : 4888 (Part III)-1982 Specification for cones for yarn winding : Part III Half angle of the cone $5^{\circ} 57'$ (second revision)	
4.	IS 4888 (PART IV)  CONE ONLY	-do-	IS : 4888 (Part IV)-1982 Specification for cones for yarn winding : Part IV Half angle of the cone $9^{\circ} 15'$ (second revision)	

[No. CMD/13 : 9]

का. प्रा. 2403.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सूत लपेटने के कोनों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए व्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और ये फीस 1982-04-16 से लागू होंगी :

अनुसूची				
क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मुहर लगाने की फीस	
			प्रति इकाई	इकाई के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सूत लपेटने के कोन		(i) IS : 4888 (भाग 1)—1982 सूत लपेटने के कोनों की विशिष्टि : भाग 1 कोन का अर्ध कोण 3° . 30' (दूसरा पुनरीक्षण)	1000 कोन	
		(ii) IS : 4888 (भाग 2)—1982 सूत लपेटने के कोनों की विशिष्टि : भाग 2 कोन का अर्ध कोण 4° . 20' (दूसरा पुनरीक्षण)	0.30	पहली 5000
		(iii) IS : 4888 (भाग 3)—1982 सूत लपेटने के कोनों की विशिष्टि : भाग 3 कोन का अर्ध कोण 5° 57' (दूसरा पुनरीक्षण)	0.15	अगली 20000
		(iv) IS : 4888 (भाग 4)—1982 सूत लपेटने के कोनों की विशिष्टि : भाग 4 कोन का अर्ध कोण 9° . 15' (दूसरा पुनरीक्षण)	0.10	शेष के लिए
			[सं. सी. एम. डी / 13 - 10]	
			ए. एस. चीमा, अपर महानिदेशक	

S.O.2403.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for cones for yarn winding, details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from 1982-04-16:

SCHEDULE

S. No.	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Marking Fee		
			Unit	Per unit	For unit
1.	Cones for yarn winding	(i) IS : 4888(Part I)—1982 Specification for cones for yarn winding : Part I Half angle of the cone 3° . 30' (second revision)	1000 Cones	0.30	First 5000
		(ii) IS : 4888(Part II)—1982 Specification for cones for yarn winding : Part II Half angle of the cone 4° . 20' (second revision)		0.5	Next 20000
		(iii) IS : 4888(Part III)—1982 Specification for cones for yarn winding : Part III Half angle of the cone 5° . 57' (second revision)		0.10	Remaining
		(iv) IS : 4888(Part IV)—1982 Specification for cones for yarn winding : Part : IV Half angle of the cone 9° 15' (second revision)			

[No. CMD/13 : 10]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General

नई दिल्ली 29 जून, 1984

का० प्रा० 2401.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए भारतीय मानकों के संशोधन उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम (1) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों के अधीन जारी किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	उस राजपत्र अधि-सूचना की संख्या और तारीख जिसमें भारतीय मानक के संसार होने की सूचना छपी थी।	संशोधन की संख्या और तारीख	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 133—1975 इनेमल, अन्तर्बर्ती की विशिष्टि (क) अन्तर्लेपन (ख) फिनिश देने का (द्वितीय पुनरीक्षण)	एस प्रो 1982 1977-06-11	सं० 1 नव० 1980	खंड 0.5 और 4.6 के स्थान पर नए खंड रखे गए हैं।	1980-11-30
2.	IS : 204 (भाग II)—1978 चटखनियों की विशिष्टि भाग II असोह धातुओं वाली (चतुर्थ पुनरीक्षण)	—	सं० 1 नव० 1980	मारणी 1 और 2 संशोधित की गई हैं।	1980-11-30
3.	IS : 418—1978 सामान्य उपयोग के लिए टंगस्टन तंतु के बिजली के लैम्पों की विशिष्टि (तृतीय पुनरीक्षण)	--	*सं० 1 अक्टू० 1980	(1) पृष्ठ 6, खंड 3.4 टिप्पणी पंक्ति 3—“तार” के स्थान पर “तार यदि कोई हो” कर लें। (2) खंड 4.3, 7.3 और मारणी 1 ए संशोधित की गई हैं। (3) खंड 4.4 सी-1 और एफ-1.2 के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं। (4) पृष्ठ 11 पर खंड 7.4.1 की संख्या बदलकर 7.5.1 की गयी है। (5) पृष्ठ 17 पर (X) चिह्नित पाद टिप्पणी के स्थान पर नयी पाद टिप्पणी रखी गयी है।	1980-10-31
4.	IS : 1068—1968 लोहा और इस्पात पर निकेल एम प्रो 368 और क्रोमियम के बिजली मुल्यमे की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस प्रो 1969-01-25	सं० 2 नव० 1980	खंड बी-3.1 और बी-4.1 संशोधित किए गए हैं।	1980-11-30
5.	IS : 1112—1963 सामान्य प्रकाश के काम धाने वाली बत्तियों के खोल शीशों की विशिष्टि (संशोधित)	एस प्रो 2595 1964-08-01	सं० 1 नव० 1980	(1) खंड 4.4 और 4.5 संशोधित किए गए हैं। (2) खंड 4.5 के बाद खंड 4.6 जोड़ा गया है। और तनुदुसार बाध के खंडों की संख्याएं ठीक की गयी हैं। (3) खंड 4.10 (पुनः संख्यात 4.11) और 4.11.1 (पुनः संख्यात 4.12.1) के बाद क्रमशः 4.11.1 और 4.12.2 नए खंड जोड़े गए हैं।	1980-11-30
6.	IS : 1222—1973 दो सिलिंडर वाली रोटरी मशीनों के लिए प्रतियां निकलाने की स्थायी की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	एस प्रो 182 1976-01-10	सं० 1 नव० 1980	1. खंड 3.9 संशोधित किया गया है। 2. खंड 5.1 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-11-30
7.	IS : 1239 (भाग 2)—1969 मृदु इस्पात नलियों, नलिकाकार वस्तुओं एवं अन्य पिटवा इस्पात की फिटिंगों की विशिष्टि भाग II मृदु इस्पात की नलिकाकार वस्तुएं तथा पिटवा इस्पात की अन्य पाइप फिटिंगें (द्वितीय पुनरीक्षण)	एस प्रो 3015 1971-08-14	सं० 2 नव० 1980	खंड 5 के बाद खंड 5.0 जोड़ा गया है।	1980-11-30

*भारतीय मानक संस्था अमानत बिन्दु योजना के प्रयोजनों के लिये यह संशोधन 1981-05-15 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	IS: 1248—1968 बिजली के प्रत्यक्ष एस ओ 3961 सं० 4 कार्यकारी सूचक यंत्रों की विशिष्टि 1968-11-09 नव० 1980 (प्रथम पुनरीक्षण)			(1) खंड 9.1.1 (सी) और 9.1.2(सी) के बाद नयी सामग्री जोड़ी गयी है। (2) खंड 9.4.2.2 के बाद खंड 9.5 जोड़ा गया है तथा तदनुसार बाद के खंडों की संख्याएँ फिर से वाली गयी है।	1980-11-30
9.	IS: 1511—1979 हस्तचालित कुट्टी मशीन के लिए फाल की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	—	स० 1 नव० 1980	खंड 5.2 के स्थान पर नया खंड रखा गया है	1980-11-30
10.	IS: 1652—1972 सीसकाम्ल प्रकार की प्लाटी घनात्मक प्लेटों वाली स्थिर सेलों और बैटरियों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 1290 1975-04-26 नव० 1980	सं० 3	खंड 7.8.5 संशोधित किया गया है।	1980-11-30
11.	IS: 1746—1970 जूते की पालिस शेई की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 3318 1972-10-21 नव० 1980	सं० 2	सारणी 1 संशोधित की गयी है।	1980-11-30
12.	IS: 1762 (भाग 1)—1974 इस्पातों की अभिधान संहिता भाग 1 स्रक्षर प्रतीकों पर आधारित (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 2547 1977 1977-08-13 नव० 1980	सं० 1	(1) पृष्ठ 8, खंड 3.1.1.1 उदाहरण, पंक्ति 14"—एफई 510 बीए" के स्थान पर "एफई 510 बी" कर लीजिए। (2) खंड 3.1.1.1 संशोधित किया गया है।	1980-11-30
13.	IS: 1848-1971 मिखाई और छपाई के कागजों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)		सं० 5 नव० 1980	पृष्ठ 4, खंड 3.4 टिप्पणी (संशोधन न० 1 भी देखिए) हटा लीजिए।	1980-11-30
14.	IS: 2016—1967 सादा बाशरों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 1367 1968-04-20 नव० 1980	सं० 3	(1) सारणी 1 और 2 के नीचे प्राकृतियों के स्थान पर नयी प्राकृतियाँ दी गई हैं। (2) खंड 4.2 के बाद खंड 4.3 जोड़ा गया है।	1980-11-30
15.	IS: 2049—1978 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए पिटवा इस्पात की पहिचान की रंग संहिता (प्रथम पुनरीक्षण)		सं० 1 नव० 1980	(1) सारणी 5 संशोधित की गयी है। (2) खंड 6.1 के बाद खंड 6.1.1 जोड़ा गया है। (3) परिशिष्ट "ए" के नीचे नयी सामग्री जोड़ी गयी है।	1980-11-30
16.	IS: 2086—1963 पुनः फ्यूज तार लकाने योग्य 650 बोलेट तक के बिजली के फ्यूजों में प्रयुक्त बाहकों और घड़ों की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	एस ओ 2370 1963-08-24 नव० 1980	सं० 7	(1) खंड 7.1.3 (बी) के बाद नयी सामग्री (जी) जोड़ी गयी है। (2) खंड 7.1.3.1 के बाद नयी सामग्री जोड़ी गयी है।	1980-11-30
17.	IS: 2622—1976 गुण (हस्तामार्जन) एकल की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 415 1980-02-23 नव० 1980	सं० 1	1 (पृष्ठ 4, खंड 2.1.1, 3 1.1, 3.1.1 1980 11 30 1 और 3.1.1.2 तथा पृष्ठ 8, खंड 7 और 7.1.1—शब्द "टेंडर" हटाया गया है। (2) खंड 7.2 के बाद खंड 8 और 8.1 जोड़े गये हैं। (3) पृष्ठ 8 पर, + चिह्न पाठटिप्पणी के "!!" चिह्नित नयी पाठ टिप्पणी जोड़ी गयी है।	1980 11 30
18.	IS: 2865—1978 मिथाईल पैराथियोस पायमनोस सांघ की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 3416 1980-12-13 नव० 1980	सं० 1	खंड 2.2.4 और ए-2 से ए-2.4 तक के स्थान पर नये खंड रखे गये हैं।	1980-11-30

1	2	3	4	5	6
19.	IS: 3081-1965 सामान्य उपयोग के सूक्ष्म-दक्षियों के परिमाण और निशान	एस ओ 2820 1965-09-11	सं० 1 नव० 1980	आकृति 1 संशोधित की गई है।	1980-11-30
20.	IS: 3107-1974 उठाऊ बहुप्रयोजनीय प्रत्यक्ष कार्यकारी बिजली के सूचकयंत्र (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 2858 1976-08-07	सं० 2 नव० 1980	खंड 4.3 1 संशोधित किया गया है।	1980-11-30
21.	IS: 3156 (भाग 2)--1978 बोल्डना ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि भाग 2 मापन बोल्डना ट्रांसफार्मर (प्रथम पुनरीक्षण)	--	सं० 1 नव० 1980	सारणी 1 संशोधित की गई है।	1980-11-30
22.	IS: 3326-1978 छोटे सूती धागे की विशिष्टि एस ओ 3171 (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 3171 1980-11-15	*सं० 2 नव० 1980	यह संशोधन छोटे कुंघे के बेलों की कुल संख्या के विकल्प के रूप में प्रति डेसीमीटर बेलों की संख्या की आवश्यकता को शामिल करने के लिए जारी किया जा रहा है।	1980-11-30
23.	IS: 3390-1977 रुधिरदाह मापी शारदीय की एस ओ 1606 की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 1606 1980-06-14	सं० 2 नव० 1980	(1) खंड 4.8.3.3 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (2) खंड 8.1 के बाद खंड 9 और 9.1 जोड़े गये हैं।	1980-11-30
24.	IS: 23829-1978 अंतिज बेलनाकार और अंतिज आयताकार वाष्प जीवाणु नाशक यंत्रों, दाब प्रकार (अस्पताली और भेषज प्रयोग के लिए) की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)		सं० 1 नव० 1980	(1) खंड 5.4 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (2) खंड ए-1 की अनौपचारिक सारणी संशोधित की गई है। (3) खंड 5.1 के बाद नयी टिप्पणी जोड़ी गयी है। (4) खंड 8 1.1 के बाद खंड 8.2 जोड़ा गया है।	1980-11-30
25.	IS: 3976-1975 बलिकों के लिए सुरक्षा रकड़ नैनवास के सुरक्षा बटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	--	सं० 6 नव० 1980	खंड 4.2.2 और 4 2.8 के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं।	1980-11-30
26.	IS: 4301-1967 फाऊंड्री के लपटे बल्बों की एस ओ 520 विशिष्टि	एस ओ 520 1968-02-10	सं० 3 अप्र. 1980	(1) खंड 6.1 के बाद खंड 7 और 7.1 जोड़े गये हैं। (2) पृष्ठ 7 के अन्त में "x" चिह्नित नयी पाद टिप्पणी जोड़ी गयी है।	1980-11-30
27.	IS: 4475-1975 मोठा इलाईयों के लिए क्रम निलम्बित हस्तचालित गरतीवार लैबलों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस ओ 1595 1979-05-19	सं० 1 नव० 1980	खंड 6.2 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-11-30
28.	IS: 4827-1968 तांबे और तांबा मिश्रित धातुओं पर निकल और प्रोमियम के बिजली मुलम्मों की विशिष्टि	एस ओ 1455 1969-04-15	सं० 2 नव० 1980	खंड बी-1.3 और बी-1.4 संशोधित किये गये हैं।	1980-11-30
29.	IS: 4941-1969 एगुमिनियम और एगुमिनियम मिश्रित धातुओं पर निकल और प्रोमियम के बिजली मुलम्मों की विशिष्टि	एस.ओ. 1906 1969-05-17	सं० 2 नव० 1980	खंड बी-3.1 और बी-4.1 संशोधित किये गये हैं।	1980-11-30
30.	IS: 5081-1969 प्रतिदीप्ति लैपो के लिए काँच की ट्यूबों की विशिष्टि	एस.ओ. 3929 1969-09-27	सं० 1 नव० 1980	(1) खंड 3-2-1 और 3-2-3 के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं। (2) खंड 3-2-3 के बाद खंड 3-2-4 और 3-2-5 जोड़े गये हैं और तबनुसार बाद के खंडों की संख्या फिर से डाली गयी है।	1980-11-30

1	2	3	4	5	6
31. IS 5117-1969 एलपीजी के साथ इन्वेंटरी के लिए वाणिज्यिक स्वयंसेवकों की विशिष्टि	एस.ओ. 1236 1970-04-04	सं० 1 नव. 1980	खंड ए-3.1 (एफ) संशोधित किया गया है।	1980-11-30	
32. IS 5321-1969 मोटा चूना (कार्बनडाइऑक्साइड शोषक के रूप में) की विशिष्टि	---	सं० 1 नव. 1980	(1) प्रथम कवर, पृष्ठ 1 और 3 पर शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक रखा गया है। (2) खंड 0.2-1.1 और परिशिष्ट सी संशोधित किये गये हैं।	1980-11-30	
33. IS.5662-1970 टीबी एरियल फीडर केबलों की विशिष्टि	एस ओ 3015 1971-08-14	*सं. 1 नव. 1980	(1) खंड 3.2 और 5.2.1 (बी) संशोधित किये गये हैं। (2) खंड 5.3.1 और पृष्ठ 4 पर + चिह्नित पाद टिप्पणी के स्थान पर नया खंड और नयी पादटिप्पणी रखी गयी है।	1980-11-30	
34. IS 5679-1970 खनिकों की टोपी बलिष्ठों की विशिष्टि	एस.ओ. 1635 1972-07-08	सं. 1 नव. 1980	परिशिष्ट 'ए' के स्थान पर नया परिशिष्ट रखा गया है।	1980-11-30	
35. IS 5731-1970 विस्फोटक और आतिशबाजी माशालों के लिए ग्रेनिटमोनी स्फार्ड की विशिष्टि	---	स 1 नव. 1980	खंड ए-9 1 से ए-9.3 तक के स्थान पर नये खंड रखे गये हैं।	1980-11-30	
36. IS:5834 (भाग 2)-1973 औद्योगिक कार्यों के लिए बिजली के समयानुक्रम रिसे की विशिष्टि भाग 2 मोटरयुक्त	एस०ओ० 2558 1975-08-09	सं. 1 नव. 1980	पृष्ठ 6 पर खंड 3.8 और 3.9 हटाए गये हैं। और बाद के खंडों की संख्याएं फिर से टीक की गयी हैं।	1980-11-30	
37. IS:6114-1971 गर्भाशय वल्मेसम के लिए फोर्सेप्स की विशिष्टि	एस.ओ. 120 1973-01-13	सं० 1 नव. 1980	खंड 5.3 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-11-30	
38. IS:6115-1971 गर्भाशय टेनाक्युलम के लिए फोर्सेप्स की विशिष्टि	एस.ओ. 886 1973-03-24	सं. 1 नव. 1980	खंड 5.3 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-11-30	
39. IS:6321-1971 हाथ की मिलाई वाली सूईयों की विशिष्टि	एस.ओ 1265 1974-05-25	सं. 1 नव. 1980	आकृति 8 की अनौपचारिक सारणी संशोधित की गयी है।	1980-11-30	
40. IS:6609 (भाग 4) 1972 वाणिज्यिक घमन विस्फोटकों और उसके सहायकांगों की परीक्षण पद्धतियां भाग 4 वागने वाले पलीते	एस.ओ० 1290 1975-04-26	सं. 1 नव. 1980	इस भाग को ध्यान में रखते हुए कि तनाव सामर्थ्य के निर्धारण की वर्तमान पद्धति नक़्को शगने वाले पलीते पर लागू होती है, इस भाग की तैयारी के लिए जिम्मेदार विषय समिति ने इसके स्थान पर जिम्मेदार वागने वाले पलीते की तनाव सामर्थ्य के निर्धारण की पद्धति रखने का निर्णय किया।	1980-11-30	
41. IS:7011-1973 थंड उद्योग में प्रयुक्त चादी चढ़े पृष्ठ वाले वर्ण की विशिष्टि	एस.ओ. 2081 1975-07-05	सं. 1 नव. 1980	खंड 3.1.1 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-11-30	
42. IS:7372-1974 मोटर गाड़ियों के लिए सीस-काम्स वाली संचायक बैटरियों की विशिष्टि	एस.ओ. 4697 1975-11-01	सं. 2 नव० 1980	सारणी 1 संशोधित की गई है।	1980-11-30	
43. IS: 7803 (भाग 1) ---1975 भेषजीय इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक के डिब्बों की विशिष्टि भाग 1 मौलिक एवं नेत्र सम्बन्धी औपधियों के अलावा।	एस.ओ 3439 1978-12-02	स. 1 नव. 1980	1. प्रथम कवर पृष्ठ 1 और 3 पर शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है। 2. खंड 0.2 और 3.1 के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं। 3. खंड 1.1 संशोधित किया गया है। 4. खंड 4.3.4 के बाद खंड 4.4 जोड़ा गया है। 5. पृष्ठ 4 पर "X" चिह्नित पाद टिप्पणी के बाद "+" चिह्नित पाद टिप्पणी जोड़ी गयी है। 6. खंड जी-3.1 के बाद परिशिष्ट 'एच' जोड़ा गया है।	1980-11-30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. IS: 7837—1975 पूर्ण वसायुक्त खाद्य सोया आटे की विशिष्टि	एस.ओ. 1596 सं. 1 1979-05-19 नव. 1980			(1) खंड 2.1.1 के बाद खंड 2.1 2 जोड़ा गया है। (2) पृष्ठ 4 पर '×' चिह्नित पादटिप्पणी के बाद "+" चिह्नित पादटिप्पणी जोड़ी गयी है। (3) पृष्ठ 4 पर सारणी 1 के नीचे नयी सामग्री जोड़ी गयी है।	1980-11-30
45. IS: 7914—1975 मानक सेलों की विशिष्टि	एस.ओ. 1596 सं. 1 1979-05-19 जन 1980			(1) पृष्ठ 5 पर खंड 2.14 हटाया गया है और बाद के खण्डों की संख्याएँ तदनुसार फिर से डाली गयी है। (2) खंड 9.4, 9.4.1 और 9.4.2 के स्थान पर नये खंड दिए गए हैं। (3) पृष्ठ 12 पर खंड 9.4.3 हटाया गया है।	1980-11-30
46. IS: 7914—1975 मानक सेलों की विशिष्टि	एस.ओ. 1596 सं. 1 1979-05-19 नव. 1980			खंड 8.2 (जी) के बाद नयी सामग्री (एक) जोड़ी गयी है।	1980-11-30
47. IS: 8144—1976 बहुध्रुवी गुष्क बैटरियों की विशिष्टि	एस.ओ. 2505 सं. 1 1979-07-21 अप्रै. 1980			(1) खंड 0.4 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (2) पृष्ठ 3 पर § चिह्नित पादटिप्पणी हटायी गयी है। (3) खंड 8.1.1 (ए) की वर्तमान सामग्री के स्थान पर नयी सामग्री रखी गयी है।	1980-04-30
48. IS: 8151—1976 लिफ्ट चालन के लिए एक गतिक तीन फेजी प्रेरण मोटरों की विशिष्टि	एस.ओ. 3823 सं. 1 1979-11-24 अग. 1980			खंड 7.2 के स्थान पर नया खंड रखा गया है।	1980-08-31
49. IS: 8160—1976 स्पष्टीय धाराभापी की विशिष्टि	एस.ओ. 3822 सं. 1 1979-11-24 नव. 1980			खंड 0.2 संशोधित किया गया है।	1980-11-30
50. IS: 8249—1976 जस्ता मल्फेट कृषि ग्रेड की विशिष्टि	एस.ओ. 49 सं. 1 1980-01-12 नव. 1980			(1) खंड ए-2 से ए-2.3 तक के स्थान पर नए खंड रखे गये हैं। (2) खंड 0.1 के बाद खंड 0.2 जोड़ा गया है और बाद के खंड 0.2 की संख्या बदल कर 0.3 की गयी है।	1980-11-30
51. IS: 8320—1976 मीनकाम्म वाली संज्ञायक बैटरियों के लिए मान्य अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां	एस.ओ. 417 सं. 1 1980-02-23 नव. 1980			(1) खंड 5.1.1 (ई) और 5.8 हटाए गये हैं। और तदनुसार बाद के खंडों की संख्याएं फिर ठीक की गयी हैं। (2) पृष्ठ 10 पर "×" चिह्नित पादटिप्पणी हटाई गयी है।	1980-11-30
52. IS: 8463 (भाग I)—1977 कृषि टैक्टर-ट्रेलर के लिए धुरी समुच्चयन की विशिष्टि भाग I 5 टन तक भार वहन की क्षमता	एस.ओ. 783 सं. 1 1980-03-29 नव. 1980			सारणी 1 संशोधित की गयी है।	1980-11-30
53. IS: 8616—1972 स्वयंयुक्त 7/24 टेपर तथा चाभी वाले स्टैंडकर्स आर्बर्स की विशिष्टि	एस.ओ. 2793 सं. 1 1980-10-18 नव. 1980			(1) खंड 1 के स्थान पर नया खंड रखा गया है। (2) पृष्ठ 2, खंड 3.1 अनौपचारिक सारणी 'डी 4-एस 30 सम्बन्धी माप' हटाये गये हैं।	1980-11-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	IS: 9158—1979 ठंडी खिंची उच्चवाहक तरल पावर मॉल्टर नलियों की विशिष्टि	--	सं. 1 नव. 1980	खंड 17.2 (ग) संशोधित किया गया है।	1980-11-30
55	IS: 9223—1979 अर्थ प्रतिरोधनामापी की विशिष्टि	--	सं. 1 नव. 1980	खंड 5.1, 10.9, 10.10.1, 10.11.2 और 10.12 संशोधित किये गये हैं।	1980-11-30

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 में तथा अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और दिवेंद्रम स्थित उसके शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

[सं. सी. एम. डी./13:5]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 29th June, 1984

S. O. 2404.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian standards Institution, hereby, notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

Sl. No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was Notified	No. and Date of the amendment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. IS : 133—1975 Specification for enamel, interior, (a) undercoating, (b) finishing (second revision)	S.O. 1892-Dated 1977-06-11	No. 1 Nov 1980	Clauses 0.5 and 4.6 have been substituted by new ones		1980-11-30
2. IS : 204 (Part II)—1978 Specification for tower bolts : Part II Non-ferrous metals (fourth revision)	—	No. 1 Nov 1980	Tables 1 and 2 have been amended		1980-11-30
3. IS : 418-1978 Specification for tungsten filament general service electric lamps (third revision)	—	*No. 1 Oct 1980	(i) Page 6, clause 3.4, Note, line 3—Substitute 'wire', if any, for 'wiro' (ii) Clauses 4.3, 7.3 and table 1A have been amended (iii) Clauses 4.4, C-1 and F-1.2 have been substituted by new ones (iv) Page 11, clause 7.4.1—Renumber this clause as '7.5.1' (v) Foot-note with '*' mark at page 17 has been substituted by a new one.		1980-10-31
4. IS : 1068-1968 Specification for electroplated Coatings of nickel and chromium on iron and steel (first revision)	S.O. 368 dated 1969-01-25	No. 2 Nov 1980	Clauses B-3.1 and B-4.1 have been amended.		1980-11-30
5. IS : 11-2-1963 Specification for glass shells for general lighting service lamps (revised)	S.O. 2595 dated 1964-08-01	No. 1 Nov 1980	(i) Clauses 4.4 and 4.5 have been amended. (ii) Clause 4.6 has been added after clause 4.5 and the subsequent clauses renumbered accordingly (iii) New clauses 4.11 and 4.12.2 have been added after clauses 4.10 (renumbered as 4.11) and 4.11.1 (renumbered as 4.12.1) respectively		1980-11-30

For purposes of ISI Certification Marks Scheme, this amendment shall come into force with effect from 1981-05-15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. IS : 1222—1973 specification for ink, duplicating, for twin cylinder rotary machines (second revision)	S.O. 182 dated 1976-01-10	No. 1 Nov 1980	(i) Clause 3.9 has been amended (ii) Clause 5.1 has been substituted by a new one	1980-11-30	
7. IS : 1239 (Part II);1969 Specification for mild steel tubes, tubulars and other wrought steel fittings : Part II mild steel tubulars and other wrought steel pipe fittings (second revision)	S.O. 3015 dated 1971-08-14	No. 2 Nov 1980	Clause 5.0 has been added after clause 5	1980-11-30	
8. IS : 1248-1968 Specification for direct acting electrical indicating instruments (first revision)	S.O. 3961 dated 1968-11-09	No. 4 Nov 1980	(i) New matter has been added after clause 9.1.1(c) and 9.1.2(c) (ii) Clause 9.5 has been added after clause 9.4.2.2 and the subsequent clauses renumbered accordingly	1980-11-30	
9. IS : 1511-1979 Specification for blades for manually-operated chaff cutter (second revision).	—	No. 1 Nov 1980	Clause 5.2 has been substituted by a new one	1980-11-30	
10. IS : 1652-1972 Specification for stationary cells and batteries, lead-acid type with plant positive plates (first revision)	S.O. 1290 dated 1975-04-26	No. 3 Nov 1980	Clause 7.8.5 has been amended	1980-11-30	
11. IS : 1746-1970 Specification for shoe polish, paste (first revision)	S.O. 3318 dated 1972-10-21	No. 2 Nov. 1980	Table 1 has been amended	1980-11-30	
12. IS : 1762 (Part I) -1974 Code for designation of steels: Part I Based on letter symbols (first revision)	S.O. 2547 dated 1977-08-13	No. 1 Nov 1980	(i) Page 8, clause 3.1.1.1, examples, line 14- Substitute 'Fe 510 B' for 'Fe 510 Ba'. (ii) Clause 3.1.1.1 has been amended	1980-11-30	
13. IS : 1848-1971 Specification for writing and printing papers (first revision)	—	*No 5 Nov 1980	Page 4, clause 3.4, Note (see also Amendment No. 1)Delete	1980-11-30	
14. IS : 2016-1967 Specification for plain washers (first revision)	S.O. 1367 dated 1968-04-20	No. 3 Nov 1980	(i) Figures under tables 1 and 2 have been substituted by new ones (ii) Clause 4.3 has been added after clause 4.2	1980-11-30	
15. IS : 2049-1978 Colour code for the identification of wrought steels for general engineering purposes (first revision)	—	No. 1 Nov 1980	(i) Table 5 has been amended (ii) Clause 6.1.1 has been added after clause 6.1 (iii) New matter has been added under appendix 'A'	1980-11-30	
16. IS : 2086-1963 Specification for carriers and bases used in reirable type electric fuses upto 650 volts (revised)	S.O. 2370 dated 1963-08-24	No. 7 Nov 1980	(i) New matter (g) has been added after clause 7.1.3 (b) (ii) New matter has been added after clause 7.1.3.1	1980-11-30	
17. IS : 2622-1976 Specification for brush, banister (hand sweeping), single (first revision)	S.O. 415 dated 1980-02-23	No. 1 Nov 1980	(i) Page 4, clauses 2.1.1, 3.1.1, 3.1.1.1, and 3.1.1.2; and page 8, clauses 7 and 7.1.1—Delete the word 'tender' (ii) Clauses 8 and 8.1 have been added after clause 7.2 (iii) A new foot-note with '†' mark has been added at page 8 after the footnote with '†' mark	1980-11-30	
18. IS : 2865-1978 Specification for methyl parathion emulsifiable concentrates (first revision)	S.O. 3416 dated 1980-12-13	No. 1 Nov 1980	Clauses 2.2.4 and A-2 to A-2.4 have been substituted by new ones	1980-11-30	
19. IS : 3081-1965 Dimensions and marking of general purposes microscopes	S.O. 2820 dated 1965-09-11	No. 1 Nov 1980	Fig. 1 has been amended	1980-11-30	
20. IS : 3107-1974 Specification for portable multipurpose direct acting electrical indicating instruments (first revision)	S.O. 2858 dated 1976-08-07	No. 2 Nov 1980	Clause 4.3.1 has been amended	1980-11-30	

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1981-04-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	IS : 3156 (Part II)—1978 Specification for voltage transformers: Part II Measuring voltage transformers (first revision)	—	No. 1 Nov 1980	Table 1 has been amended	1980-11-30
22	IS : 3326-1978 Specification for cotton stockinette (first revision)	S.O. 3171 dated 1980-11-15	No. 2 Nov 1980	This amendment is being issued to incorporate the requirement of number of wales per decimetre as an alternate to the total number of wales of stockinette	1980-11-30
23	IS : 3390-1977 Specification for sphygmomanometers, mercurial (first revision)	S.O. 1606 dated 1980-06-14	*No. 2 Nov 1980	(i) Clause 4.8.3.3 has been substituted by a new one (ii) Clause 9 and 9.1 have been added after clause 8.1	1980-11-30
24	IS : 3829-1978 Specification for horizontal cylindrical and horizontal rectangular steam sterilizers, pressure type (for hospital and pharmaceutical use) (first revision)		No. 1 Nov 1980	(i) Clause 5.4 has been substituted by a new one (ii) Informal table of clause A-1 has been amended (iii) A new note has been added after clause 5.1 (iv) Clause 8.2 has been added after clause 8.1.1	1980-11-30
25	IS : 3976-1975 Specification for safety rubber-canvas boots for miners (first revision)		No. 6 Nov 1980	Clauses 4.2.2 and 4.2.8 have been substituted by new ones	1980-11-30
26	IS : 4301-1967 Specification for brushes, foundry, flat	S.O. 520 dated 1968-02-10	No. 3 Aug 1980	(i) Clauses 7 and 7.1 have been added after clause 6.1 (ii) A new foot-note with “*” mark has been added at the end of page 7	1980-08-31
27	IS : 4475-1975 Specification for crane-suspended hand-operated geared ladles for iron foundries (first revision)	S.O. 1595 dated 1979-05-19	No. 1 Nov 1980	Clause 6.2 has been substituted by a new one	1980-11-30
28	IS : 4827-1968 Specification for electroplated coatings of nickel and chromium on copper and copper alloys	S.O. 1455 dated 1969-04-19	No. 2 Nov 1980	Clauses B-1.3 and B-1.4 have been amended	1980-11-30
29	IS : 4942-1969 Specification for electroplated coatings of nickel and chromium on aluminium and aluminium alloys	S.O. 1906 dated 1969-05-17	No. 2 Nov 1980	Clauses B-3.1 and B-4.1 have been amended	1980-11-30
30	IS : 5081-1969 Specification for glass tubes for fluorescent lamps	S.O. 3929 dated 1969-09-27	No. 1 Nov 1980	(i) Clauses 3.2.1 and 3.2.3 have been substituted by new ones (ii) Clauses 3.2.4 and 3.2.5 have been added after clause 3.2.3 and the subsequent clauses renumbered accordingly	1980-11-30
31	IS : 5117-1969 Specification for commercial boiling burners for use with LPG	S.O. 1236 dated 1970-04-04	No. 1 Nov 1980	Clause A-3.1(f) has been amended	1980-11-30
32	IS : 5321-1969 Specification for soda lime (as carbon dioxide absorbent)	—	No. 1 Nov. 1980	(i) Title at first cover, pages 1 and 3 has been substituted by a new one (ii) Clauses 0.2, 1.1 and appendix C have been amended	1980-11-30
33	IS : 5662-1970 Specification for TV aerial feeder cables	S.O. 3015 dated 1971-08-14	†No. 1 Nov 1980	(i) Clauses 3.2 and 5.2.1(b) have been amended (ii) Clause 5.3.1 and foot-note with “†” mark at page 4 have been substituted by new ones	1980-11-30
34	IS : 5679-1970 Specification for miners' cap lamps	S.O. 1635 dated 1972-07-08	No. 1 Nov 1980	Appendix A has been substituted by a new one	1980-11-30

*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1981-03-01

†For purposes of ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1981-05-15

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. IS : 5731-1970 Specification for antimony sulphide for explosive and pyrotechnic compositions	S.O. 1635 dated 1972-07-08	No 1 Nov 1980	Clause A-9 1 to A-9 3 have been substituted by new ones	1980-11-30	
36. IS : 5834 (Part II)-1973 Specification for electrical time relays for industrial purposes Part II Motorized	S.O. 2558 dated 1975-08-09	No 1 Nov 1980	Page 6, clauses 3 8 and 3 9—Delete and renumber the subsequent clauses accordingly	1980-11-30	
37. IS : 6114-1971 Specification for forceps uterine vulsellum	S.O. 120 dated 1973-01-13	No 1 Nov 1980	Clause 5 3 has been substituted by a new one	1980-11-30	
38. IS : 6115-1971 Specification for forceps, uterine tenaculum	S.O. 886 dated 1973-03-24	No. 1 Nov 1980	Clause 5 3 has been substituted by a new one	1980-11-30	
39. IS : 6321-1971 Specification for needles, hand sewing	S.O. 1265 dated 1974-05-25	No 1 Nov 1980	Informal table of Fig 8 has been amended	1980-11-30	
40. IS : 6609 (Part IV) 1972 Methods of test for commercial blasting explosives and accessories Part IV Detonating fuses	S.O. 1290 dated 1975-04-26	No 1 Nov 1980	In view of the fact that the existing method of determination of tensile strength was applicable to dummy detonating fuse, the Sectional Committee responsible for the preparation of this standard decided to substitute it with the method for determination of tensile strength of live detonating fuse	1980-11-30	
41. IS : 7011-1973 Specification for back-silvered mirrors used in instrument industry	S.O. 2081 dated 1975-07-05	No 1 Nov 1980	Clause 3 1 1 has been substituted by a new one	1980-11-30	
42. IS : 7372-1974 Specification for lead-acid storage batteries for motor vehicles	S.O. 4697 dated 1975-11-01	No 2 Nov 1980	Table 1 has been amended	1980-11-30	
43. IS : 7803 (Part I) 1975 Specification for plastic containers for pharmaceutical use Part I Other than parenteral and ophthalmic preparations	S.O. 3439 dated 1978-12-02	No. 1 Nov 1980	(i) Title at first cover page, pages 1 and 3 has been substituted by a new one (ii) Clauses 0 2 and 3 1 have been substituted by new ones (iii) Clause 1 1 has been amended (iv) Clause 4 4 has been added after clause 4 3 4 (v) Foot-note with '†' mark has been added at page 4 after foot-note with '*' mark (vi) Appendix H has been added after clause G-3 1	1980-11-30	
44. IS : 7837-1975 Specification for edible full-fat soya flour	S.O. 1596 dated 1979-05-19	No. 1 Nov 1980	(i) Clause 2 1 2 has been added after clause 2 1 1 (ii) Foot-note with '†' mark has been added at page 4 after foot note with '*' mark (iii) New matter has been added in table 1 at page 4	1980-11-30	
45. IS : 7914-1975 Specification for standard cells	S.O. 1596 dated 1979-05-19	No 1 Jun 1980	(i) Page 5, clause 2 14—Delete and renumber subsequent clauses accordingly (ii) Clauses 9 4, 9 4 1 and 9 4 2 have been substituted by new ones (iii) Page 12, clause 9 4 3—Delete	1980-06-30	
46. IS : 7914-1975 Specification for standard cells	S.O. 1596 dated 1979-05-19	No 2 Nov 1980	New matter (h) has been added after clause 8 2 (g)	1980-11-30	
47. IS : 8144-1976 Specification for multipurpose dry batteries	S.O. 2505 dated 1979-07-21	No 1 Apr 1980	(i) Clause 0 4 has been substituted by a new one (ii) Page 3, foot note with '†' mark—Delete (iii) Existing matter of clause 8 1 1 (a) has been substituted	1980-04-30	
48. IS : 8151-1976 Specification for single speed three phase induction motors for driving lifts	S.O. 3823 dated 1979-11-24	No. 1 Aug 1980	Clause 7 2 has been substituted by a new one	1980-08-31	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49. IS : 8100-1976 Specification for tangent galvanometers	S.O. 3822 dated 1979-11-24	No. 1 Nov 1980	Clause 0.2 has been amended	1980-11-30	
50. IS : 8249-1976 Specification for zinc sulphate, agricultural grade	S.O. 99 dated 1980-01-12	No. 1 Nov 1980	(i) Clauses A-2 to A-2.3 have been substituted by new ones (ii) Clause 0.2 has been added after clause 0.1 and the subsequent clause 0.2 has been renumbered as 0.3	1980-11-30	
51. IS : 8320-1976 General requirements and methods of tests for lead-acid storage batteries	S.O. 417 dated 1980-02-23	No. 1 Nov 1980	(i) Clauses 5.1.1(e) and 5.8 have been deleted and the subsequent clauses have been renumbered accordingly (ii) Page 10, foot note with * mark—Delete	1980-11-30	
52. IS : 8463 (Part I) 1977 Specification for axle assembly for agricultural tractor-trailer : Part I load carrying capacity up to 5 tonnes	S.O. 783 dated 1980-03-29	No. 1 Nov 1980	Table I has been amended	1980-11-30	
53. IS : 8616-1977 Specification for stub milling arbours with self-release 7/24 taper and with key	S.O. 2793 dated 1980-10-18	No. 1 Nov 1980	(i) Clause 1 has been substituted by a new one (ii) Page 2, clause 3.1, informal table, dimensions relating to 'd ₄ =M30'—Delete	1980-11-30	
54. IS : 9158-1979 Specification for cold-drawn high pressure fluid power cylinder tubes	—	No. 1 Nov 1980	Clause 17.2 (a) has been amended	1980-11-30	
55. IS : 9223-1979 Specification for earth resistance meter	—	No. 1 Nov 1980	Clauses 5.1, 10.9, 10.10.1, 10.11.2 and 10.12 have been amended	1980-11-30	

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 5]

कां० प्र० 2405.—भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गई अनुसूची में स्तम्भ 2 और 3 में दी गई विभिन्न यन्त्रों सम्बन्धी मुहर लगाने की फीस स्तम्भ 4, 5 और 6 में उल्लेख के अनुसार पुनरीक्षित की गई है। मुहर लगाने की पुनरीक्षित फीस की दरें प्रत्येक के भागों की गई तारीखों से लागू होगी :

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद	भारतीय मानक की संख्या	हकाई	मुहर लगाने की दर		भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) का संदर्भ			लागू होने की तारीख
				प्रति हकाई	हकाइयों के लिए	अधिकृतित एस ओ संख्या	प्रांशिक संशोधित एस ओ की संख्या	जारी होने की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. घूमर लोहे की इन्की बस्तुएं	IS : 210-1970	एक मीटर टन	3.00	सभी	—	4391	1976-10-27	1976-11-20	1982-05-01
2. घुना चिकोरी पाउडर	IS : 612-1971	एक मीटर टन	3.00	सभी	1502	1965-04-29	—	1965-05-08	1982-08-01
3. कोयला खानों में प्रयुक्त रबड़ रोहित लकड़ीले ट्रेलिंग केबल	IS : 691-1966	100 मीटर	7.50	सभी	—	2012	1971-04-27	1971-05-22	1982-04-01
4. पावर थ्रम सत	IS : 1051-1973	100 लिटर	10.00	सभी	1950	1964-05-22	4502	1964-06-06	1981-10-01
5. बेकिंग पाउडर	IS : 1159-1981	एक कि० प्र०	0.03	सभी	—	1976-11-05	—	1976-11-27	1982-11-01
6. बहिरंग डाइप लोन फेजो वितरण ट्रांसफार्मर (बिनासील कृत टाइप)	IS : 1180 (भाग 1 के बी ए 1)- 1981	0.12	सभी	—	1391	1976-03-25	—	1976-04-17	1983-02-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	मक्का, स्टार्च, सूती वस्त्र उद्योग के लिए	IS 1184-1977	एक मीटर टन	1 00	सभी	1950 1964-05-22	—	1964-06-06	1982-05-01
8	मक्खन स्नेहकमापी और श्राद (मक्खन स्नेहक मापी)	IS 1223 (भाग 1970)	एक मक्खन स्नेहकमापी	0 075 0 05	पहली श्रेणी	10000 3458 1968-09-10	—	1968-09-28	1982-08-01
9	मक्खन स्नेहकमापी और स्पीयर (नालेवार स्टापर)	"	एक लॉक स्टापर	0 01	सभी	1278 1964-03-31	—	1964-04-11	"
10	पिपेट और स्वचाल मापक (दूध की दमा के लिए)	IS 1223 (भाग 2 1972)	एक प्रदद	0 075	सभी	3458 1958-09-10	—	1968-09-28	"
11	घाघ केन्द्रित और जल कुडियां	IS 1223 (भाग 3)-1977	एक प्रदद	0 50 0 30 0 02	पहली श्रेणी	10000 200000 600000	—	—	1982-03-16
12	सूती डक, धसर	IS 1422-1977	1 मी ²	0 01 0 05	पहली श्रेणी	4377 1969-10-21	—	1969-11-01	1982-05-01
13	मैकरोनी स्पष्टेटी और नैबई	IS 1485-1976	एक कि० ग्रा०	0 03	सभी	3028 1963-10-18	—	1983-10-26	1982-09-01
14	सूती करघो से प्रयुक्त सूती हील्ड	IS 1739-1978	100 से	1 00	सभी	— 2012 1971-04-27	—	1971-05-22	1982-05-01
15	पटसन करघो से प्रयुक्त सूती कश्चे	IS 1938-1974	एक कश्चा	0 10	सभी	— 3067 1975-08-08	—	1975-09-13	1982-05-01
16	हस्तचालित दबा कर चलने पृष्ठवाही स्प्रेशर (प्रदायधारक टाइप)	IS 1970 (भाग 1) 1974	एक स्प्रेशर	2 50	सभी	— 1391 1976-03-25	—	1976-04-17	1982-11-01
17	हस्तचालित संपीकित पृष्ठवाही स्प्रेशर (दायधारक टाइप)	IS 1970 (भाग 2) 1979	"	3.00	सभी	—	—	—	1982-11-16
18	हस्तचालित पूर्णक धान निराने का यन्त्र	IS 1976-1976	एक धान निराने का यन्त्र	2 00	सभी	— 1391 1976-03-25	—	1976-04-17	1982-11-01
19	बैनन	IS 2400-1976	एक मीटरी टन	1 50 1 00	पहली श्रेणी	18 2500 1972-12-22	—	1973-01-06	1982-08-01
20	माल्टकासन	IS 240-1972	एक मीटरी टन	6.00 4 50	पहली श्रेणी	1276 1000 1964-03-30	—	1964-04-11	1982-08-01
21	बस्तियों की दोषी की बस्तियों की बैटरियां	IS 2572-1978	एक प्रदद	0 05	सभी	1114 1972-02-23	—	1972-05-13	1983-02-01
22	बम्बई हलवा	IS 2650-1975	एक कि० ग्रा०	0 10	सभी	1275 1972-03-30	—	1972-05-27	1982-08-01
23	बुलनशील काफी पाउडर	IS 2791-1972	"	0 10 0 05	पहली श्रेणी	3397 100000 1965-10-15	—	1965-10-30	"
24	दायधारक प्रकार के पृष्ठवाही संपीकित स्प्रेशर के चार्ज पम्प	IS 2870-1977	एक पम्प	3 00	सभी	— 1391 1976-03-25	—	1976-04-17	1982-11-01
25	बुलनशील काफी चिकोरी पाउडर	IS 3309-1975	एक कि० ग्रा०	0.05 0.03	पहली श्रेणी	1778 100000 1970-05-01	—	1970-05-23	1982-11-01
26	एलुमिनियम प्लगमुमा सकुघो से प्रयुक्त ताने की मलियां	IS 3625-1971	एक मीटरी टन	15.00	सभी	2763 1972-07-03	—	1972-10-07	1982-05-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27.	बिन्दुओं में घुलन करने के हस्तचालित यंत्र	IS: 3634-1977	एक एम्पी केंटर	1.25	सभी	---	1391 1976-03-25	1976-04-17	1982-11-01
28.	हस्त चालित लगातार पृष्ठवाही स्प्रैयर (पिस्टन वाले)	IS: 3906 (भाग 1) 1974	एक स्प्रैयर	3.00	सभी	---	4502 1976-11-05	1976-11-27	"
29.	अंडा पाउडर	IS: 4723-1978	एक कि० ग्राम	0.20	सभी	---	4391 1976-10-27	1976-11-20	"
30.	ड्राफ्ट प्रणालियों के लिए मॉडिफाईड रजिड के ऐप्रन (प्रतिबलित)	IS: 4892-1968	1000 यदद	1.50	सभी	---	1182 1974-04-26	1974-05-11	1982-05-01
31.	कालीनों के पीछे लगाने की पटसन कपड़ा	IS: 4900-1969	एक मीटर टन	3.00	सभी	---	1762 1971-04-07	1971-05-01	1982-05-01
32.	वेसी शराब	IS: 5287-1978	100 लिटर	0.25	सभी	1972-02-23	1114 1972-02-23	1972-05-13	1982-11-01
33.	मुनियों के चुर्मों के पूरक रूप में खनिज मिश्रण	IS: 5672-1970	एक मीटर टन	5.00	पहली 500 शेष	---	---	---	1982-08-01
34.	रोएवार ऊनी कालीन	IS: 5884-1970	1 मी	0.15	सभी	---	405 1972-01-19	1972-02-05	1982-05-01
35.	उर्वरक पैकिंग के लिए परतदार पटसन बोरे	IS: 7406 (भाग 1) 1974 IS: 7406 (भाग-2) 1980	100 बोरे	0.50	सभी	1975-12-15	180 ---	1976-01-10	1981-11-16
36.	पटसन तिरपाल का कपड़ा	IS: 7407 (भाग 1 से 3) 1980	एक मीटर टन	5.00	सभी	"	---	;	"
37.	मशीनारि में प्रयुक्त ऊनी कपड़ा (सफाई करने का कपड़ा)	IS: 7610 (भाग 2)-1975	1 मी ²	0.05	सभी	1975-12-15	181 ---	"	1982-05-01
38.	मशीनारि में प्रयुक्त ऊनी कपड़ा (मोड़ देने की कालीन)	IS: 7610 (भाग 3) 1975	"	0.05	सभी	"	"	"	"
39.	मशीनारि में प्रयुक्त ऊनी कपड़ा (पट्टू देने का कपड़ा)	IS: 7610 (भाग 4) 1976	"	0.10	सभी	---	1 790 1980-05-23	1980-07-05	"

[सं० सी एम डी 13.10]

S. O. 1115.—The Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col. 4, 5 and 6 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product	IS : No	Unit	Marking Fee Rate		Reference to Govt. of India Gazette Notification, Part II Section 3, Sub-Section (ii)			Date of Effect
						Superseded S.O. No.	Partially Modified	Date of Issue	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grey iron castings	IS : 210-1970	One Tonne	3.00	All	---	4391	1976-10-27	1976-11-20 1982-05-01
2.	Roasted chicory powder	IS : 612-1971	-do-	3.00	All	1502 1965-04-29	---	---	1965-05-08 1982-08-01
3.	Rubber-insulated flexible trailing cables for use in coal mines	IS : 691-1966	100 Metre	7.00	All	---	2012 1971-04-27	1971-05-22	1982-04-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Pyrethrum extracts	IS : 1051-1973	100 litres	10.00	All	1950	—	1964-06-06	1981-10-01	
5. Baking powder	IS : 1159-1981	One kg.	0.03	All	—	4502	1976-11-27	1982-11-01	
6. Outdoor type three-phase distribution transformers (non sealed type)	IS : 1180 (Pt. I)-1981	1 KVA	0.12	All	—	1391	1976-04-17	1983-02-01	
7. Maize, starch, cotton textile industry	IS : 1184-1977	One Tonne	1.00	All	1950	—	1964-06-06	1982-05-01	
8. Butyrometers and stoppers (Butyrometers)	IS : 1223 (Pt. I) 1970	One Butyrometer	0.075	First 10000	3458	—	1968-08-28	1982-08-01	
9. Butyrometers and stoppers (Lock stoppers)	-do-	One Lock stopper	0.01	All	1278	—	1964-05-11	-do-	
10. Pipettes and automatic measures (for milk fat)	IS : 1223 (Pt. II)-1972	One piece	0.075	All	3458	—	1968-09-28	-do-	
11. Centrifuges and water-baths	IS : 1223 (Pt. III)-1977	-do-	0.50	First 1000	—	—	—	1982-03-16	
12. Cotton duck, grey	IS : 1422-1977	1m²	0.30	Remaining	—	—	—	—	
			0.02	First 200000	4377	—	1969-11-01	1982-05-01	
			0.01	Next 600000	1969-10-21	—	—	—	
			0.005	Remaining	—	—	—	—	
13. Macaroni, spaghetti and vermicelli	IS : 1485-1976	One kg.	0.03	All	3.028	—	1963-10-26	1982-09-01	
14. Cotton healds for use in cotton looms	IS : 1739-1978	100 sets	1.00	All	—	2012	1971-05-22	1982-05-01	
15. Cotton combs for use in jute looms	IS : 1938-1974	On Comb	0.10	All	—	3067	1975-09-13	1982-05-01	
16. Hand-operated compression knapsack sprayer (non-pressure retaining type)	IS : 1970 (Pt. I)-1974	One Sprayer	2.50	All	—	1391	1976-04-17	1982-11-01	
17. Hand operated compression knapsack sprayer (Pressure retaining type)	IS : 1970 (Pt. II)-1979	-do-	3.00	All	—	—	—	1982-11-16	
18. Rotary paddy weeders manually operated	IS : 1976-1976	One Weeder	2.00	All	—	1391	1976-04-17	1982-11-01	
19. BESAN	IS : 2400-1976	One Tonne	1.50	First 2500	18	—	1973-01-06	1982-08-01	
20. Malt extract	IS : 2404-1972	One Tonne	1.00	Remaining	1972-12-22	—	—	—	
21. Miners' cap lamp battery (lead acid type)	IS : 2512-1978	One Piece	6.00	First 1000	1276	—	1964-04-11	-do-	
22. BOMBAY HALWA	IS : 2650-1975	One Kg.	4.50	Remaining	1964-03-30	—	—	—	
23. Soluble coffee powder	IS : 2791-1972	-do-	0.05	First 100000	1114	—	1972-05-13	1983-02-01	
24. Charge pump for pressure retaining type compression knapsack sprayer	IS : 2870-1977	On Pump	0.10	Remaining	1972-02-23	—	1972-05-27	1982-08-01	
25. Soluble coffee chicory powder	IS : 3309-1975	One Kg.	0.10	First 100000	1265	—	1972-05-27	1982-08-01	
26. Warp tubes for use on aluminium plug type spindles	IS : 3265-1971	One Tonne	0.05	Remaining	1972-03-30	—	1965-10-30	-do-	
27. Hand operated applicator for burrows	IS : 3634-1977	One applicator	3.00	All	3397	—	1976-10-30	-do-	
28. Hand operated continuous knapsack sprayer (piston type)	IS : 3906 (Pt. I)-1974	One Sprayer	3.00	All	1965-01-15	—	1976-04-17	1982-11-01	
29. Egg powder	IS : 4723-1978	One Kg.	0.05	First 100000	1391	—	1976-04-17	1982-11-01	
			0.03	Remaining	1778	—	1970-05-23	1982-11-01	
			15.00	All	1970-05-01	—	1972-10-07	1982-05-01	
			1.25	All	2763	—	1972-10-07	1982-05-01	
			3.00	All	—	1391	1976-04-17	1982-11-01	
			3.00	All	—	4502	1976-11-27	-do-	
			0.20	All	—	4391	1976-11-20	-do-	
						1976-10-27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Synthetic rubber aprons (reinforced) for drafting system	IS : 4892-1968	1000 pieces	1.50	All	—	1182	1974-04-26	1974-05-11	1982-05-01
31. Jute carpet backing fabric	IS : 4900-1969	One tonne	3.00	All	—	17.62	1971-04-07	1971-05-01	1982-05-01
32. Country spirit	IS : 5287-1978	100 litres	0.25	All	1114	1972-02-23	—	1972-05-13	1982-11-01
33. Mineral mixtures for supplementing poultry Feeds.	IS : 5672-1970	One tonne	5.00	First 500	—	—	—	—	1982-08-01
			3.00	remaining					
34. Tufted wool carpets	IS : 5884-1970	1m ²	0.15	All	—	405	1972-01-19	1972-02-05	1982-05-01
35. Laminated jute bags for packing fertilizers	IS : 7406 (Pt. I)-1974 IS : 7406 (Pt. II)-1980	100 bags	0.50	All	180	1975-12-15	—	1976-01-10	1981-11-16
36. Jute tarpaulin fabric	IS : 7407 (Pt. I to III)-1980	One tonne	5.00	All	-do-	—	-do-	-do-	-do-
37. Machinery fabrics wool (clearer cloth)	IS : 7610 (Pt. II)-1975	1m ²	0.05	A	181	1975-12-15	—	-do-	1982-05-01
39. Machinery fabrics wool (sizing flannel)	IS : 7610 (Pt. III)-1975	-do-	0.05	All	-do-	—	—	-do-	-do-
39. Machinery fabrics wool (plaiding cloth)	IS : 7610 (Pt. IV)-1976	-do-	0.10	All	—	1790	1980-5-23	1980-07-05	-do-

[No. CMD/13 : 10]

का०प्र० 2406.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन बिज्ञान) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे 1983-04-01 से रद्द कर दिए गए हैं और वापस के लिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या व शीर्षक	भारत के राजपत्र के एस प्रो संख्या तथा तारीख जिसके अधीन भारतीय मानकों के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1600-1960 सामान्य कार्यों के लिए समगति प्रतवाही इंजनों की टाइप संहिता	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1960-01-14 में एस प्रो 100 दिनांक 1961-01-02 के अधीन प्रकाशित	IS : 1000 (भाग 1 से 12)-1980, IS : 10001-1981, IS : 10002-1981, IS : 10003-1981 और IS : 10004-1981 के प्रकाशन के फलस्वरूप और यह भी नोट कर लिया जाए कि IS : 1000 (भाग 11) से (भाग 12) और IS : 10001 और IS : 10002 द्वारा संयुक्त रूप से IS : 1600 और 1601 का स्थान ले लिया है जबकि IS : 10000 (भाग 1 से 12) IS : 10003 और IS : 10004 ने संयुक्त रूप से IS : 1602 और 1603 का स्थान ले लिया है।
2.	IS : 1601-1960 सामान्य कार्यों के लिए समगति प्रतवाही इंजनों की कार्यकारिता की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1961-03-18 में एस प्रो 570 दिनांक 1961-03-06 में प्रकाशित	
3.	IS : 1602-1960 स्क्वेल बाहनों के लिए परिवर्ती गति प्रतवाही इंजनों के टाइप परीक्षण की संहिता	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1968-11-26 में एस प्रो 2818 दिनांक 1960-11-16 के अधीन प्रकाशित	
4.	IS : 1603-1960 स्क्वेल बाहनों के लिए परिवर्ती गति प्रतवाही इंजनों की कार्यकारिता की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 1961-05-13 में एस प्रो 1059 दिनांक 1961-05-02 के अधीन प्रकाशित	

[सं० सी एस डी/13 : 7]

S.O.2406.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn with effect from 1983-04-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1600-1960 Code for type of constant speed internal Combustion engines for general purposes.	S.O. 100 dated 1961-10-02 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 1961-01-14.	Consequent upon the publication of IS 10000 (Parts I to XII)—1980, IS : 10001 1981, IS : 10002-1981, IS : 10003-1981 and IS : 10004-1981 and it may also be noted that IS : 10000 (Part I)—to (Pt XII) and IS : 10001 and IS : 10002 jointly replace IS : 1600 and IS : 1601 while IS : 10000 (Part I to XII; IS : 10003 and IS : 1004 jointly replace IS : 1602 and IS : 1603)
2.	IS : 1601-1960 Specification for performance of constant speed internal combustion engines for general purposes :	S.O. 570 dated 1961-03-06 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1961-03-18.	
3.	IS : 1602-1960 Code for type testing of variable speed internal combustion engines for automotive purposes.	S.O. 2818 dated 1960-11-16 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1960-11-26.	
4.	IS : 1603-1960 Specification for performance of variable speed internal combustion engines for automotive purposes	S.O. 1059 dated 1961-05-02 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated 1961-05-13.	

[No. CMD/13 : 7]

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1984

का०आ० 2407 --समय समय पर संगोष्ठित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-0679871 जिसके ध्योरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं 1984-05-01 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या और तारीख	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गये लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सी एम/एल-0679871	सैरम असीम प्रॉडक्ट्स, शेड संख्या 8, प्लॉट संख्या 215 जी आई डी सी, पंडासा, मुरत (गुजरात)	फास्ट रेड ई, खाद्य ग्रेड	IS : 2926—1974 फास्ट रेड 'ई' खाद्य ग्रेड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) [सी एम डी/55 : 0679871] ए० एम० बीमा, अपर महानिदेशक, मार्क्स

New Delhi, the 3rd July, 1984

S.O.2407.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) regulation, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby notifies that licence No. CM/L-0679871 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1984-05-01.

SCHEDULE

Sl.No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-0679871	M/s Asim Products Shed No. 8, Plot No. 215, GIDC, Pandesara, Surat (Gujarat)	Fast Red E, Food Grade	IS : 2924—1974 Specification for Fast Red E, Food Grade. (First Revision)

[CMD/55 : 0679871]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General, Marks

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1984

का. प्रा. 2408—यस: संवैधानिक अधिनियम, 1948, 1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (क) के अनुसरण में कर्नाटक दन्त चिकित्सा परिषद ने 25 अप्रैल, 1984 से डा. यू.एम. मोहनदास नायक, बी.डी.एस. डेंटल सर्जन भट्टावर नन्दीगुद्धा रोड, मंगलूर को डा. पी. एस. देसाई के स्थान पर भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः, अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 12 अप्रैल, 1949 की अधिसूचना संख्या एक 10-10/48-एम 1 में जो 24 जनवरी, 1984 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य) विभाग की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 430 द्वारा पुनः प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के उपबन्ध के साथ पठित खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5
"7.	डा० यू० एस० मोहन- दास डेंटल सर्जन, भट्टावर नन्दीगुद्धा रोड, मंगलूर - 575001	निर्वाचित	कर्नाटक दन्त चिकित्सा परिषद्]	25-4-1984"

[सं बी. 12013/3/84-पी एम एस]
कुमारी सी० सिधुरी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)

New Delhi, the 9th July, 1984.

S.O. 2408—Whereas in pursuance of clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. U.S. Mohandas Nayak, BDS, Dental Surgeon, Attavar Nandigudda Road, Mangalore, has been elected to be a member of the Dental Council of India by the Karnataka Dental Council with effect from the 25th April, 1984 vice Dr. P.S. Desai;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health, No. F. 10-10/48-MI, dated the 12th April, 1949, as republished by the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 430, dated the 24th January, 1984, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (a) read with proviso to section 3", for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substitute namely:—

"7. Dr. U.S. Mohandas Nayak, Dental Surgeon, Attavar Nandigudda Road, Mangalore- 575001.	Elected Karnataka Dental Council	25-4-1984"
---	---	------------

[No. V. 12013/3/84-PMs
KUM. C. CINTURY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

का. प्रा. 2409.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्वारा यह निदेश देती है कि लंदन विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) द्वारा प्रदान की गई "एम. बी. बी. एस." चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

[संख्या बी० 11016/3/83-एम ई (पी.)]

एस. पी. भसीन, प्रवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 1984

S.O. 2409.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the medical qualification "M.B.B.S." granted by the University of London (United Kingdom), shall be a recognised medical qualification for the purpose of that Act.

[No. V. 11016/3/83-ME (P)]

S. P. BHASIN, Under Secy.

(खेल विभाग)

का० प्रा० 2410:—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जून, 1983 में एतद्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है:—

सदस्यों की सूची में क्र० सं० 2 पर सचिव, भारत सरकार, खेल विभाग के सामने "श्री बी० सी० माथुर" के स्थान पर "श्री बी० एम० स्वरूप" का नाम प्रतिस्थापित किया गया है।

[संख्या एक० 13-1/81-डी-1 (एस० पी०)]

ए० एम० सहगल, निदेशक (खेल)

DEPARTMENT OF SPORTS

New Delhi, the 5th July, 1984

S.O. 2410.—This Department's notification of even No. dated 13th June, 1983 is hereby partially modified as follow:—

In the list of the Members at Sl. No. 2 against Secretary to the Government of India, Department of Sports, the name "Shri B. N. Swarup" is substituted in place of "Shri B. C. Mathur".

[No. F. 13-1/81-D. I(SP)]

A. M. SEHGAL, Director (Sports)

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

का. प्रा. 2411.—सरकारी स्थान (प्राधिकृत अधिसूचनाओं की वेबसाई) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के हस्तात और ज्ञान मंत्रालय (हस्तात विभाग) की अधिसूचना संख्या का.भा. 4337 तारीख 11 नवम्बर 1983 का अतिक्रमण करने हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समतुल्य अधिकारी है उसका अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यक् अधिकारी नियुक्त करनी है जो उसका सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के बारे में अपने अधिकारों की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्मियों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रयोग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रबन्धक (प्रशासन) अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. आयरन और कम्पनी लि. II ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलूर 560034 (कर्नाटक राज्य)	कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिगृहीत स्थान

[संख्या 2 (7)/83-कुद्रेमुख]
बहीदुल हसन, निदेशक

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 11th July, 1984.

S.O. 2411.—In exercise of the power conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of authorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel), No. S.O. 4337, dated the 11th November, 1983, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of a Gazetted officer of Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the Public Premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Manager (Administration) or Senior Administrative Officer, Kudremukh Iron Ore Company Limited, II Block, Koramangala, Bangalore-560034 (Karnataka State)	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Kudremukh Iron Ore Company Limited.

[File No. 2(7)/83-KDM]
W HASAN, Director

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

का.भा. 2412—स्थायी आदेश संख्या 527, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पाम्मेरी/ईडाचैरी/काम्बाला टैलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-8-1984 में प्रसारित प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/84-पी.एच.बी.]

वाई.आर. भसीन, महायक महानिदेशक (पी एच बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 11th July, 1984

S.O. 2412.—In pursuance of para (k) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-8-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pomeri/Edacherry/Chombala Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-9/84-PHB]

Y. R. BHASIN, Asstt. Director General (PHB)

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

का.भा. 2413.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आकम कन्स्ट्रक्शन को. प्रा. लिमिटेड, 21, आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001, नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म.एस-35017-51/84/पी.एफ.०-II]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 12th July, 1984

S.O. 2413.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Acme Construction Company Private Limited, 21, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/51/84-PF II]

का० आ० 2414.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेडियोहमस ऐजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड, 6/3, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता-72 और रजि० आफिस 302-ए, पुनम चैम्बरस, डा० एनी बेसन्त रोड, वर्ली, बम्बई-18, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एम-35017(58)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 2414.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Radiohms Agencies Private Limited, 6/3, Madan Street, Calcutta-72 including its Regd. Office at 302 A, Poonam Chambers, Dr. Annie Basant Road, Worli, Bombay-18, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(58)/84-PF. II]

का० आ० 2415.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूपनारायण प्रॉपर्टीज एण्ड सर्विसीज प्रा० लिमिटेड, पी-42, सी. आई. टी. रोड, स्कीम नं० 6-एम, कलकत्ता 54 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एम-35017(59)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 2415.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Roonarayan Properties and Services Private Limited, P-42, C.I.T. Road, Scheme No. VI M, Calcutta-700054, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(59)/84-PF. II]

का० आ० 2416.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेबर्टस मैकलिन सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, 27 बी, कैमक स्ट्रीट कलकत्ता-16 और इसकी शाखाएं ई/1

मण्डेवालान एकस्टेंशन लिंक रोड, नई दिल्ली-55, और (2) एलाक हाउस सर प० मेहता रोड, बम्बई-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एम-35017(60)/84-पी० एफ० 2]

S.O. 2416.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Robert Mclean Services Private Limited, 27B, Camac Street, Calcutta-16, including its offices namely (i) Northern Regional Office at F/I Jhandewalan Extension, Link Road, New Delhi-55 (ii) Western Regional Office at Ilac House, Sir, P. Mehta Road, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(60)/84-PF. III]

का० आ० 2417.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बासील फर्मा, 1, प्रभात नगर, जोगेश्वरी (वेस्ट) बम्बई-400102, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एम-35018(12)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 2417.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Basil Pharma, 1, Prabhat Nagar, Jogeshwari (W), Bombay-400102, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(12)/84-PF. III]

का० आ० 2-18.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रमेश भवन, 80-नार्थ कार स्ट्रीट, तिरुचेल गोडे, जिला सालम, तमिल नाडू नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(140)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 2418.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Ramesh Bhawan, 80, North Car Street, Tiruchengode, Salem District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (140)/84-PF.III]

का० आ० 2419.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रभाकर प्रोडक्ट्स, सी-2, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गुड्डुडी, मद्रास-600032, तमिल नाडू नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(150)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 2419.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Prabhakar Products, C-2, Industrial Estate, Guindy, Madras-600032, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019 (150) 84-PF.III]

का० आ० 2420.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि इलेक्ट्रीसिटी स्टाफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सी-2075, 10वां ईस्ट मेन रोड,

गांधी नगर, बेल्लोर-632006, एन० ए० डिस्ट्रिक्ट, तमिल नाडू नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(185)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 2420.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs The Electricity Staff Co-operative Society, Limited C-2073, 10th East Main Road, Gandhi Nagar, Vellore-632006, N. A. District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(185)/84-PF.III]

का० आ० 2421.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गौतमी इन्जीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नाचराम इण्डस्ट्रियल एरिया, नाचराम, हैदराबाद-501507, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(251)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 2421.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Gautami Engineering and Construction Company Private Limited, Nacharam Industrial Area, Nacharam, Hyderabad-501 507, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (251)/84-PF.III]

का० आ० 2422.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेशासायी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एम्प्लॉईज को-ओपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, वाडालूर, साउथ-आरकोट, तमिलनाडू नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(252)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 2422.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Seshasayee Industries Limited Employees Co-operative Thrifts and Credit Society, Vadalur, South Arcot, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (252)/84-PF.II]

का० आ० 2423.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माया आटो एण्ड फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-29, जी० टी० कर्नाल रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-33, अपने प्रधान कार्यालय 28, मोतिया खान, नई दिल्ली-55, स्थित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(253)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 2423.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Maya Auto and Forgings Private Limited, B-29, G. T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-33 including its Head Office at 28, Motia Khan, Jhandewalan Road, New Delhi-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(253)/84-PF.II]

का० आ० 2424.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुल्लिवर्स ट्रेवल्स, 44-रिगल बिल्डिंग, कन्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (254)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 2424.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Gulliver's Travels, 44, Regal Building, Connaught Place, New Delhi-110001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(254)/84-PF.II]

का० आ० 2425.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डीकोलाइट (इण्डिया), डब्ल्यू० जेड०-75/33, शकूरपुर, दिल्ली-34, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(256)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 2425.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Decolite (India), WZ-75/33, Shakurpur, Delhi-34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (256)/84-PF. II]

का० आ० 2426.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजयन सिक्योरिटी सर्विसेज, 19, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, (सीढ़ियों पर), अम्बूर, नार्थ आर्कोट जिला, तमिलनाडु, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम-35019(257)/84/पी०एफ०-II]

S.O. 2426.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Vijayan Security Services, 19, Perumal Koil Street, (Upstairs), Ambur, North Arcot, District Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (257)]84-PF.II]

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

का. आ. 2427.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सीलीगुडी होलसेल कन्ज्युमर्स कोपरेटीव सोसायटी लिमिटेड, पो. आफिस सीलीगुडी, दार्जिलिंग, (वेस्ट बंगाल), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(52)/84/पी. एफ.-II]

New Delhi, the 13th July, 1984

S.O. 2427.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Siliguri Wholesale Consumers Co-operative Society Limited, Post Office Siliguri, District Darjeeling (West Bengal), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(52)]84-PF. II]

का. आ. 2428.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आगरा फाईन लैडर टेनरी, 23-ए, चन्द्र नाथ राय रोड, कलकत्ता-39 और कार्यालय 29, मौलाना शौकत अली स्ट्रीट, कलकत्ता-73, में स्थित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35017(53)/84/पी. एफ.-II]

S.O. 2428.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Agra Fine Leather Tannery, 23A, Chandra Nath Roy Road, Calcutta-39 and its office at 29, Maulana Shaukat Ali Street, Calcutta-73 (West Bengal), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017 (53)]84-PF. II]

का. आ. 2429.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स युनाईटेड वेंनीर मैन्युफैक्चरिंग कं०, 2, गुरुदास दत्ता गार्डन लेन, कलकत्ता-67 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(54)/84/पी. एफ.-II]

S.O. 2429.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs United Veneer Manufacturing, Company, 2 Gurudas Dutta Garden Lane, Calcutta-67, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017 (54)]84-PF. II]

का. आ. 2430.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोरेगिया टर्मिनल सर्विसेज, 24-स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017(55)/84/पी. एफ. -2]

S.O. 2430.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Gorsia Terminal Services, 24-Strand Road, Calcutta-700-001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017 (55)/84-PF. II]

का. आ. 2431.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बिटुमन प्रोडक्ट्स (इन्डिया), 90-ए बिरन रोय रोड, (ईस्ट) कलकत्ता-41, और प्रधान कार्यालय 16-लेक टेम्पल रोड, कलकत्ता-29 में स्थित, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017(56)/84/पी. एफ. -2]

S.O. 2431.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Bitumen Products (India), 90A, Biren Roy Road, (East), Calcutta-41 including its Head Office at 16-Lake Temple Road, CALCUTTA-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(56)/84-PF. II]

का. आ. 2432.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी लोयनल एडवर्ड्स एण्ड आई. एस. एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, 21, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35017(57)/84-पी. एफ. -2]

S.O. 2432.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs The Lionel Edwards' and I.S.S. Employees Co-operative Credit Society Limited, 21, Old Court House, Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017 (57)/84-PF. II]

का. आ. 2433.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शालीन ट्रेडिंग को. (प्राइवेट) लि., 25/26, मेकर चैम्बरस, III, नारिमान प्वायंट बम्बई-21, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35018(11)/84/पी. एफ. -2]

S.O. 2433.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Shalina Trading Company (Private) Limited, 25/26, Maker Chambers, III Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(11)/84-PF. II]

का. आ. 2434.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तमिलनाडू स्टील एण्ड मेटल फैब्रिकेटर्स, 15-होस्पिटल रोड, मद्रास-600015, तमिलनाडू तथा स. 29, श्री स्वैगदम स्ट्रीट, मद्रास-600033 स्थित अपने कार्यालय सहित, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(151)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2434.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Tamil Nadu Steel and Metal Fabricators, 15, Hospital Road, Madras-600 015, Tamil Nadu including its office at No. 29, Thiruvengadam Street, Madras-33, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (151)]84-PF. II]

का. आ. 2435.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स व्यवसाय सेवा सहकारी संघ नियामिथा, होस्पेट सं. 2, बेल्लारी जिला, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(170)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2435.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Vyavasaya Seva Sahakara Sangha Niyamitha, Hospet No. II, Bellary District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (170)]84-PF.II]

का. आ. 2436.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महालक्ष्मी फाउन्ड्री, प्लॉट सं. 107, उद्यमबाग, बेलगौम-590008, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(171)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2436.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Mahalakshmi Foundry, Plot No. 107, Udyambag, Belgaum-590 008, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(172)]84-PF. II]

का. आ. 2437.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कर्नाटक बाल बीयरिंग्स कार्पोरेशन लिमिटेड, 21-बी, बेला वाडी इण्डस्ट्रियल एरिया, हुसूर रोड, मैसूर-570005, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(173)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2437.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Karnataka Ball Bearings Corporation Limited, 21-B, Belawadi Industrial Area, Hunsur Road, Mysore-570 005, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(173)]84-PF. II]

का. आ. 2438.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जगदल साइन्टीफिक रिसर्च फाउन्डेशन, स. 35, समपानगी, टैंक रोड, बंगलौर-560027, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(174)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2438.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Jagdal Scientific Research Foundation, No. 35, Sampangi, Tank Road, Bangalore-560 027, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(174)/84-PF. II]

का. आ. 2439.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टाइपोसेट, प्रथम मजिल, स. 21, 12-12ए, महात्मा गांधी रोड, बंगलौर-560001, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(175)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2439.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Typoset, 1st Floor, No. 21, 12-12A, Mahatma Gandhi Road, Bangalore-560001, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(175)/84-PF. II]

का. आ. 2440.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अड्डागन एस्टेट, द्वारा-मैसर्स थिप्पेनाहल्ली एस्टेट, चिकमंगलूर डाकघर तथा जिला-577102, कर्नाटक,

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(176)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Addagan Estate, C/o. M/s. Thippenahalli Estate, Chikmagalur Post Office and District-577101, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(176)/84-PF. II]

का. आ. 2441.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरविन्द आइल मिल्स, मुत्ताथु काडावू, शेरथलई, जिला अल्लप्पी, केरल, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(184)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2441.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Aravind Oil Mills, Muttathu, Kadavu, Sherthallai, Alleppey District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(184)/84-PF. II]

का. आ. 2442.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडियन वायर कम्पनी, 24, मुकेर नल्लामुथु स्ट्रीट मद्रास-600001, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण

उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(186)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Indian Wire Company, 24, Muker Nallamuthu Street, Madras-600001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(186)/84-PF. II]

का. आ. 2443.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजया ट्रेडर्स, 6/100, न्यू टाउन, कोचीन 2, मट्टनचेरी गांव, कोचीन तालुक, अरनाकुलम जिला, केरल नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(194)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Vijaya Trades, VI/100, Jew Town, Cochin-2, Mattanchery Village, Cochin Taluk, Ernakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(194)/84-PF. II]

का. आ. 2444.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्लाट लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड, काडायीरूपू गांव तथा डाकघर, कोल्लनचेरी-682311, कुन्नाथूनाडू तालुक, अरनाकुलम जिला, केरल नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(195)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Plant Lipids Private Limited, Kadayiruppu, Village & Post Office, Kolenchery-682311, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(195)/84-PF. II]

का. आ. 2445.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टेक्निक, 173, जी आई डी. सी. इण्डस्ट्रियल इस्टेट, मकडपुरा, बरौदा-10, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019 (241)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2445.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Technique, 173, G.I.D.C. Industrial Estate, Makarpura, Baroda-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(241)/84-PF. II]

का. आ. 2446.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री राधा कृष्णा इण्डस्ट्रीज, 12-1-513, लालपेट, सिकन्दराबाद-40, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(250)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 2446 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Radhakrishna Industries 12-1-513, Lalaper, Secunderabad-40, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(250)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1984

का. आ. 2447.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डियन सिल्क म्यूजियम, 47-ए, गारियाहट रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35017/46/84/पी. एफ.-2]

New Delhi, the 16th July, 1984

S.O. 2447 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Silk Museum, 47-A, Gariahat Road, Calcutta-19, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/46/84-PF. II]

का० आ० 2448.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्योर पैक प्रोडक्ट्स, 3, जौहरा बाजार लेन, कस्बा, कलकत्ता-42 और कार्यालय 13-रानी रासमोनी रोड, कलकत्ता-13, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35017/47/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2448 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs Pure Pack Products, 3, Jahura Bazar Lane, Kasba, Calcutta-42 including its office at 13, Rani Rashmoni Road, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/47/84-PF. II]

का. आ. 2449.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेशनल कंटेनर, 12, गिरिश चन्द्र घोष रोड, (पातीपुकर), कलकत्ता-48 और इसका 127-ए०, ए. पी. सी. रोड, कलकत्ता-700006, स्थित कार्यालय नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस०-35017/48/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2449 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs National Container, 12, Girish Chandra Ghosh Road, (Patipukur) Calcutta-48 and its Office at 127-A, A.P.C. Road, Calcutta-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/48/84-PF. II]

का. आ. 2450.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोयम्बटूर प्लाईवुड एण्ड टूल्स मार्ग, 223-224, डा० नानजप्पा रोड, कोयम्बटूर-641018, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(53)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2450 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Coimbatore Plywood and Tools Mart, 223, 224, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore-641018, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(153)/84-PF. II]

का. आ. 2451.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द नर्सरी स्कूल, मैलपट्टम्बक्कम, पानलुती तालुका, साउथ आरकोट जिला, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (154)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2451 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ananda Nursery School, Melpattambakkam, Paniuti Taluk, South Arcot District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(154)/84-PF. II]

का. आ. 2452.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० के० त्रिवेदी, एट एण्ड पोस्ट थसरा, जिला कायरा, गुजरात नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (171)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2452 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. K. Trivedi, At and Post Thasra, District Kaira, Gujarat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(171)/84-PF. II]

का. आ. 2453.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होटल हरिप्रसाद, कूडापुर, एस. के० डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (177)/84 पी. एफ.-2]

S.O. 2453 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Hariprasad, Coondapur, S. K. District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(177)/84-PF. II]

का. आ. 2454.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बान्तीया इण्डस्ट्रीज राइस मिल, कम्पनी रोड, गंगावती, रायचूर जिला, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (178)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2454 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bantia Industries Rice Mill, Kampli Road, Gangavati, Raichur District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(178)/84-PF. II]

का. आ. 2455.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री दुर्गा भवन कृष्णाराजापेट, जिला-मान्ड्या, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (179)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2455 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Durga Bhavan, Krishnarajapet, Mandya District, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(179)/84-PF. II]

का. आ. 2456.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्दी इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, बी.-44/1, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स, कुशाईगुडा, हैदराबाद-500762, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (180)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2456 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ad Engineering Industries, B-44/1, Electronics Complex, Kushaiguda, Hyderabad-500762, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(180)/84-PF. II]

का. आ. 2457.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर. एच. मेशी एण्ड कम्पनी प्राई. एन. सी. (इण्डियन लायमन आफिस) 26, बसंत लोक नई दिल्ली-110057, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (181)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2457 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs R. H. Massey & Co., Inc. (Indian Liaison Office), 26, Basant Lok, New Delhi-110057, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(181)/84-PF. II]

का. आ. 2458.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इजि राइडर (एक्सपोर्ट्स) प्रा. लि., ए.-42, नागायणा इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली और इसकी शाखाएं (i) में 10 मेन मार्किट बसंत विहार, नई दिल्ली, और (ii) 158-गफार मार्किट, नई दिल्ली में स्थित। नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (182)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2458 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Easy Rider (Exports) Private Limited, A-42, Naraina Industrial Area, New Delhi including its branches at (i) C-10, Main Market, Vasant Vihar, New Delhi, (ii) 158, Ghaffar Market, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(182)/84-PF. II]

का. आ. 2459.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डायमण्ड एसोसिएट्स, 60-साउथ राजा स्ट्रीट, तूतीकोरिन-628001, तमिल नाडू नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म. एम.-35019 (183)/84/पी. एक-2]

S.O. 2459 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Diamond Associates, 60-South Raja Street, Tuticorin-628001, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(183)/84-PF. II]

का. आ. 2460.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कट्टा मशीनिंग्स, प्रोविडन्स रोड, कोचीन-18, अरनाकुलम गाँव, कानायान्नूर तालुक, अरनाकुलम जिला, केरल। नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म. एम.-35019 (187)/84/पी. एक-2]

S.O. 2460 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Katta Machinings, Providence Road, Cochin-18, Ernakulam Village, Kanayannur Taluk, Ernakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(187)/84-PF. II]

का. आ. 2461.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लार्ड एण्ड लार्डिंग, 50/21, गली नं०-1 इन्डस्ट्रियल एरिया न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली। नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म. एम.-35019 (188)/84/पी. एक-2]

S.O. 2461 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Light and Lighting, 50/21, Gali No. 1, Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(188)/84-PF. II]

का. आ. 2462.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्डस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स, हरिनगर कालोनी नं० 2, कम नं० 145, उधना सुरत (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[म. एम.-35019 (189)/84/पी. एक-2]

S.O. 2462 :—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Industrial Security Force, Harinagar, Colony No. 2, Room No. 145, Udhna Surat (Gujarat), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(189)/84-PF. II]

का. आ. 2463.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टार सिक्युरिटी फायर एण्ड कन्सल्टेंटसी सर्विसिज (प्रा०) लि०, "गुलनार", शामला हीन्ज, भोपाल (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम.-35019 (190)/84/पी. एफ-2]

S.O. 2463.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Star Security Fire and Consultancy Services (Private) Limited, 'Gulnar', Shamlu Hills, Bhopal (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(190)/84-PF. II]

का.आ. 2464.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनाय वायर्स एण्ड मेटल्स, 11वां किलोमीटर होसूर रोड, बंगलूर-560068, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम.-35019 (242)/84/पी. एफ.-2]

S.O. 2464.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manay Wires and Metals, 11th K. M. Hosur Road, Bangalore-560068, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(242)/84-PF. II]

का. आ 2465.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कलिंगा बाडी बिल्डर्स, ए.-31, इण्डस्ट्रियल एरिया, रसूलगढ़, भुवनेश्वर-10, उड़ीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम.-35019 (243)/84/पी. एफ 2]

S.O. 2465.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kalinga Body Builders, A-31, Industrial Area, Rasulgah, Bhubaneswar-10, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(243)/84-PF. II]

का. आ. 2466.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामगढ़ीया कोऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, 15, ब्रूटा कोटेज (कृष्णा मार्केट के पीछे) पहाड़गंज लेन, नई दिल्ली, 110055, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम.-35019 (244)/84/पी. एफ-2]

S.O. 2466.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ramgarhia Cooperative Bank Limited, 15, Broota Cottage (Behind Krishna Market) Pahar Ganj Lane, New Delhi-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(244)/84-PF. II]

का० आ० 2467.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स काल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 67/1 14 वां क्रॉस, 11 वां फ्लैट मानेस्वरम बंगलूर-560003 कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एम०-35019 (245)/84/पी० एफ०-2]

S.O. 2467.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kal Electronics and Consultants Private Limited, 67/1, 14th Cross, XI Main, Malleswaram, Bangalore-560003 Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(245)/84-PF. II]

का० आ० 2468.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि भारत को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सं० 27 9वां मेन, तीसरा खण्ड, जयनगर बंगलूर-11 कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(246)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 2468.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Bhatath Co-operative Bank Limited, No. 27, 9th Main, 3rd Block, Jayanagar, Bangalore-II, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(246)/84-PF. II]

का०आ० 2469.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मीनू एन्टरप्राइजिज 10/81, रंगा कोंनार स्ट्रीट कटूर, कोयंबटूर-641009 तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(247)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 2469.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Meenu Enterprises, 10/81 Ranga Konar Street, Kattur, Coimbatore-641009, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(247)/84-PF. II]

का०आ० 2470.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री लक्ष्मी टिम्बर्स, टिम्बर मर्चेन्ट्स-एण्ड कोप कन्ट्रेक्टर्स, पवूरचत्रम-627808, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(248)/84-पी० एफ० 2]

S.O. 3470.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Lakshmi Timbers, Timber Merchants and coupe contractors, Pavoorchatram-627808, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(248)/84-PF. II]

का०आ० 2471.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बसन्धा भवन, 41, गांधी रोड अरनी, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(249)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 2471.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vasantha Bhavan, 41, Gandhi Road, Arni, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(249)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 13 जून, 1984

आदेश

का.आ. 2472.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कं. लिमिटेड, डाक-घर-वेंकटेश खानो के प्रबंधनत्व से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम.एन. राव होंगे, जिन का मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर वेंकटेश खानो के प्रबंधनत्व द्वारा इन्कलाइन संख्या-5 में ट्रेजर, सर्वश्री बसालाल और नामीला मल्लैया को अतिरिक्त दो वेतन-वृद्धि का लाभ देने से इन्कार करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुपाद के हकदार हैं?”

[सं. एल.-22012/147/83-डी-3(बी)]

New Delhi, the 13th June, 1984

ORDER

S.O. 2472.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Venkatesh Khani and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, P.O. Venkatesh Khani, are justified in denying the benefit of two additional increments to Sarvaswari Bayyalal and Namilla Mallaiiah, Trammis at No. 5 Incline? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?”

[No. L-22012(147)/83-D.III(B)]

नई दिल्ली, 16 जून, 1984

आदेश

का.आ. 2473.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में गणेश क्वैरी वर्क्स, नानी रावल के प्रबंधनत्व से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी.एस. बरोट होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या मैसर्स गणेश क्वैरी, वर्क्स, डाकघर इन्द्रवरण, जिला भरुच, क्वैरी आर्नेस के प्रबंधनत्व की कर्मकार, श्री सुभाषभाई जेठाभाई ताडवी की 1-10-82 में सेवा समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुपाद का हकदार है?”

[सं. एल.-29012 1/84-डी-3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1984

S.O. 2473.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ganesh Quarry Works, Nani Raval and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Messrs Ganesh Quarry Works, P.O. Indravarna, Distt. Bharuch, Quarry Owners, in terminating the services of Shri Subhashbhai Jethabhai Tadi, workman, with effect from 1-10-82 is legal and justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

[No. L-29012/1/84-D.III(B)]

आदेश

का.आ. 2474.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विश्वेश्वर्या आयरन एण्ड स्टील लि., भद्रावती और उनके ठेकेदार सर्वश्री

टी० पुट्टैया और चेन्नाकेशवा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी.एन. लालगे होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलूर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या विश्वेश्वर्या आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती और उनके ठेकेदार, सर्वश्री टी० पुट्टैया और चेन्नाकेशवा द्वारा बिल्मीकेल्लाबेट्टा क्वाट्रज माइन्स के 185 कर्मकारों की, जिनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं, 1-1-83 से छंटनी करना वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? ”

अनुबन्ध

क्रमांक	बी.एफ. संख्या	कर्मकार का नाम
1	2	3
1.	401	बोम्माराई
2.	504	थामैया
3.	408	गिरिजास्मा
4.	409	चिन्नासामी
5.	410	दाथनास्मा
6.	417	मुथस्मा
7.	701	दाशयसामी
8.	514	चन्नाप्पा
9.	422	के.एम. रामासामी
10.	423	जयास्मा
11.	215	रामासामी
12.	318	मरी मुथु
13.	526	एस०आर० कृष्णा
14.	732	सिद्दाप्पा
15.	733	सिद्दास्मा
16.	330	मुनियास्मा
17.	702	मरी मुथु
18.	109	हनुमानायक
19.	738	एस. मुनियासामी
20.	209	कासी
21.	110	शिवास्मा
22.	131	चिन्नाप्पा
23.	103	परवाथस्मा

1	2	3
24.	104	हनुमानयस्मा
25.	205	टी.सी. शंकर
26.	206	बेलायदन
27.	111	येरीप्पा
28.	114	हलानायक
29.	115	आर० कामजीबाई
30.	718	कोलनदाई
31.	725	चिन्नामादा
32.	722	केनदायी
33.	151	बोरैया
34.	806	अमामे
35.	818	रामासामी
36.	819	सुन्दरस्मा
37.	802	चिन्ना रामा
38.	803	गनियास्मा
39.	815	मालास्मा
40.	329	बिरासामी
41.	910	ईस्वरप्पा
42.	546	शथनास्मा
43.	515	रुद्राप्पा
44.	741	कुप्पास्मा
45.	917	जयास्मा
46.	1175	जयास्मा (टी.सी.)
47.	847	मोक्कास्मा
48.	747	रेनास्मा
49.	850	मोहम्मद इब्राहिम
50.	352	मुनिमामी
51.	355	तगास्मा
52.	354	एस० बालु
53.	259	सी. लक्ष्मन
54.	970	पेरुमन
55.	967	पोन्नुसामी
56.	968	मक्कन
57.	853	सुन्दरस्मा
58.	162	सिद्दाप्पा
59.	163	सिद्दास्मा
60.	166	न जाप्पा
61.	451	बन्गाशस्मा
62.	858	ओ० मुनियासामी
63.	859	पलानियास्मा
64.	863	जानकीबाई
65.	452	चिन्नास्मा
66.	453	गोविन्दराज
67.	458	अक्कास्मा
68.	456	एस० हनुमन्था
69.	157	एस. रामा
70.	868	सी० अरुमुगम

1	2	3	1	2	3
71.	869	चन्द्राम्मा	118.	1110	निगाम्मा
72.	176	केमाप्पा	119.	1111	पप्पान्ता
73.	267	दोदाराश्मा	120.	1113	सन्नेगोवदा
74.	270	ए.म. विगराम	121.	1114	पुट्टाम्मा
75.	366	अन्ता मलाई	122.	1115	नंजैया
76.	16	पेह्मना	123.	1116	बट्टाम्मा
77.	31	राम नायक	124.	1118	सिद्दासेट्टी
78.	32	गन्गाम्मा	125.	1119	चौदाम्मा
79.	33	लक्ष्मी	126.	1120	केमपैया
80.	6	सी. सागादेवन	127.	1121	दोदाथायी
81.	8	मोहन	128.	1123	शिर्बलिंगा
82.	10	पेह्मल	129.	1134	पट्टाम्मा
83.	846	पी. पार्वती	130.	1135	ऐलुमलाई
84.	14	चिन्ताथायी	131.	1143	रंगासामी
85.	15	टी. कानन	132.	1146	ए.म. वेंकटन
86.	23	ए.म. मुनिसामी	133.	1160	सन्ताप्पा
87.	26	कुमार	134.	27	मरसेट्टी
88.	35	सावित्री	135.	1181	विशालाक्षी
89.	43	वरुप्पन	136.	1182	येरप्पा
90.	988	दस्थगिरिसाब	137.	1183	करियाम्मा
91.	1005	एरेगोवदा	138.	1184	चन्द्राप्पा
92.	852	चिन्ताप्पा	139.	1192	बल्ली
93.	1035	चिन्तासामी	140.	1193	जी. वासुदेवन
94.	1036	लक्ष्मी	141.	1187	विजलक्ष्मी
95.	1038	जी. कावरीयाम्मा	142.	1189	चिक्कु
96.	1039	ए.म. कावरीयाम्मा	143.	1190	निगाम्मा
97.	1040	चिन्तापोन्नु	144.	1195	भागयाम्मा
98.	1013	थिप्पेसामी	145.	268	मुलेरामनी
99.	1024	वेंकटप्पा	146.	1202	डी. सिद्दिया
100.	1026	गंगाप्पा	147.	1203	गोवराप्पा
101.	1034	सिद्दाम्मा	148.	1204	रंगासामी
102.	1037	एस. चौदेया	149.	749	मुनियाम्मा
103.	1051	गोवाराप्पा	150.	866	चिदाम्बरा
104.	22	गोपाल	151.	1105	मदाम्मा
105.	872	मुनियाम्मा	152.	1207	सिद्दासेट्टी
106.	1066	मरीयाप्पा	153.	1209	पट्टाचन्द्राम्मा
107.	1073	पुट्टाम्मा	154.		मुद्दैया
108.	1074	श्रन्ताम्मा	155.	1213	नंजैया
109.	1077	पी. जयान्ता	156.	1219	टी. के. प्रसाद
110.	1069	लक्ष्मण	157.	1235	योम्मारयागोवदा
111.	1056	निगाम्मा	158.	1237	मरीगोवदा
112.	1076	सिद्दाम्मा	159.	1038	नंजप्पा
113.	1078	लक्ष्मण	160.	1210	रछम्मा
114.	1097	मुनियाम्मा	161.	1223	ए.च. एस. महेश्वरैया
115.	1093	बोरेगोवदा	162.	1224	मन्जा
116.	1094	महालिंगेगोवदा	163.	1227	करीयप्पा
117.	1108	नंजाम्मा	164.	1329	कदैया

1	2	3	Sl. No.	B.F. No.	Name of the Workman
165.	1230	पी रंगा	3.	408	Girijamma
166.	416	पी माया	4.	409	Chinnasamy
167.	1234	जयलक्ष्मी	5.	410	Tattnamma
168.	1240	एन. बोरोगोवदा	6.	417	Muthamma
169.	1241	कुल्लेगोवदा	7.	701	Doraisamy
170.	1243	बोरोगोवदा	8.	514	Channappa
171.	1244	कोडीगोवदा	9.	422	K.M. Ramasamy
172.	1245	निगा	10.	423	Jayamma
173.	1248	सावरेगोवदा	11.	215	Ramasamy
174.	1249	टी० थिमैया	12.	318	Mari Muthu
175.	1253	बोम्माप्पा	13.	526	M.R. Krishna
176.	1255	केमपैया	14.	732	Siddappa
177.	1267	थिमैया	15.	733	Siddamma
178.	1268	डी० कृष्णा	16.	330	Muniyamma
179.	1273	रुद्राम्मा	17.	702	Mari Muthu
180.	1274	चेल्लाकन्ता	18.	109	Hanumanaik
181.	1277	सी० नंजुनदैया	19.	738	M. Munisamy
182.	1279	चिक्काजावारैया	20.	209	Kasy
183.	1280	मोट्टैया	21.	110	Shivamma
184.	1281	निगेगोवदा	22.	431	Chinnappa
185.	1282	हुसैनसाब	23.	103	Parvathamma
			24.	104	Hanumanthamma
			25.	205	T.C. Shankar
			26.	206	Velaidan
			27.	111	Yerrappa
			28.	114	Halanaik
			29.	115	R. Kamalibai
			30.	718	Kolandai
			31.	725	Chinnamada
			32.	722	Kandayee
			33.	151	Borajah
			34.	806	Amase
			35.	818	Rammasamy
			36.	819	Sundramma
			37.	802	Chinna Rama
			38.	803	Raniyamma
			39.	815	Solamma
			40.	329	Veeasamy
			41.	910	Eswarappa
			42.	546	Rathnamma
			43.	515	Rudrappa
			44.	741	Kuppamma
			45.	917	Jayamma
			46.	1175	Jayamma (T.C.)
			47.	847	Mokkamma
			48.	747	Renamma
			49.	850	Mohd. Ibrahim
			50.	352	Munisamy
			51.	355	Nagamma
			52.	354	S. Balu
			53.	259	C. Laxmana
			54.	970	Perumal
			55.	967	Ponnusamy
			56.	968	Sakkan
			57.	853	Siddamma
			58.	162	Siddappa
			59.	163	Siddamma
			60.	166	Nanjappa
			61.	451	Bangaramma
			62.	858	O. Munisamy
			63.	859	Palaniyamma
			64.	863	Janakibai
			65.	452	Chinnamma
			66.	453	Govindaraj

[सं एल-26011/7/83-डी-3(बी)]

ORDER

S.O. 2474.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visvesvaraya Iron and Steel Limited, Bhadravathi and Sarvashri T. Puttaiah and Chennakeshava, their contractors, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B.N. Lalage shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether retrenchment of 185 workmen, mentioned in the Annexure, of Bilikellabetta quartzmines by the management of Visvesvaraya Iron and Steel Limited, Bhadravathi and their contractors, Sarvashri T. Puttaiah and Chennakeshava, with effect from 1-4-83, is legal and justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?

ANNEXURE

Sl. No.	B.F. No.	Name of the Workman
1.	401	Bommarayee
2.	504	Thammiah

Sl. No.	B.F. No.	Name of the Workman	Sl. No.	B.F. No.	Name of the workman
67.	458	Akkamma	132.	1146	S. Venkatan
68.	456	S. Hanumantha	133.	1160	Sannappa
69.	457	S. Rama	134.	27	Marsetty
70.	868	C. Arumugam	135.	1181	Visalakshi
71.	869	Chandramma	136.	1182	Yerrappa
72.	176	Kempamma	137.	1183	Kariyamma
73.	267	Doddarama	138.	1184	Chandappa
74.	270	M. Singaram	139.	1192	Valli
75.	366	Anna Malai	140.	1193	G. Vasudevan
76.	16	Perdama	141.	1187	Visalakshmi
77.	31	Ramanak	142.	1189	Chikku
78.	32	Gangamma	143.	1190	Ningamma
79.	33	Laxmi	144.	1195	Bhagyamma
80.	6	C. Sagadevan	145.	268	Suleramany
81.	8	Mohan	146.	1202	D. Siddaiah
82.	10	Perumal	147.	1203	Gowramma
83.	846	P. Parvathi	148.	1204	Rangasamy
84.	14	Chinnathayee	149.	749	Muniyamma
85.	15	T. Kannan	150.	866	Chidambara
86.	23	S. Munisamy	151.	1105	Madamma
87.	26	Kumar	152.	1207	Siddasetty
88.	35	Savithri	153.	1209	Puttachandramma
89.	43	Karuppan	154.		Muddiah
90.	988	Dasthagirisab	155.	1213	Nanjaiah
91.	1005	Eregowda	156.	1219	T.K. Prasad
92.	652	Chinnappa	157.	1235	Bommarayagowda
93.	1035	Chinnasamy	158.	1237	Marigowda
94.	1036	Laxmi	159.	1038	Nanjappa
95.	1038	G. Kaveriyamma	160.	1210	Rachamma
96.	1039	S. Kaveriyamma	161.	1223	H.S. Maheshwaraiah
97.	1040	Chinnaponnu	162.	1224	Manja
98.	1013	Thippesamy	163.	1227	Kariyappa
99.	1024	Venkatappa	164.	1229	Kadaiah
100.	1026	Gangappa	165.	1230	P. Ranga
101.	1034	Siddamma	166.	416	P. Maya
102.	1037	S Chowdaiah	167.	1234	Jayalakshmi
103.	1051	Gowaramma	168.	1240	N. Boregowda
104.	22	Gopal	169.	1241	Kullegowda
105.	872	Muniyamma	170.	1243	Boregowda
106.	1066	Mariyappa	171.	1244	Kodigowda
107.	1073	Puttamma	172.	1245	Ninga
108.	1074	Annamma	173.	1248	Savaregowda
109.	1077	P. Jayanna	174.	1249	T. Thimmaiah
110.	1069	Laxmana	175.	1253	Bommappa
111.	1056	Ningamma	176.	1255	Kempaiah
112.	1076	Siddamma	177.	1267	Thimmaiah
113.	1078	Laxmana	178.	268	D. Krishna
114.	1097	Maniyamma	179.	1273	Rudramma
115.	1093	Boregowda	180.	1274	Chellakanna
116.	1094	Mahalingegowda	181.	1277	C. Nanjundaiah
117.	1108	Nanjamma	182.	1279	Chikkajavarajah
118.	1110	Ningamma	183.	1280	Mottaiah
119.	1111	Pappanna	184.	1281	Ningegowda
120.	1113	Sannegowda	185.	1281	Hussainsab
121.	1114	Puttamma			
122.	1115	Nanjaiah			
123.	1116	Battamma			
124.	1118	Siddasetty			
125.	1119	Chowdamma			
126.	1120	Kempaiah			
127.	1121	Doddathayee			
128.	1123	Shivalinga			
129.	1134	Pattamma			
130.	1135	Elumalai			
131.	1143	Rangasamy			

[No. L-26011(7)/83 D.IIIB]

दिनांक 13 जून 1984

आदेश

का.आ. 2475.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषय के बारे में सिगरेनी कोलियरीज क. लि., कोठामुडियम के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम. एन. राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर बेकटेशखानी के प्रबंधन द्वारा ग्रेड “डी” में जूनियर ड्रिलर, श्री सैयदा अहमद को, ग्रेड “ए” देने में इंकार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० एल-22012/164/83-डी-3(बी)]

New Delhi, the 18th June, 1984

ORDER

S.O. 2475.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Koghagudum and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Post Office Venkatesh Khani, are justified in denying Grade ‘A’ to Shri Syed Ahmed, Junior Driller presently in Grade ‘D’ ? If not to what relief is the workman concerned entitled?”

[No. 1-22012(164)/83-D.III(B)]

आदेश

का० आ० 2476—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मंगमपीट बायराइट्स माइन्स आफ मैसर्स आंध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन, डाकघर मंगमपीट के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती

है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम. एन. राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मंगमपीट बायराइट्स माइन्स आफ आंध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन के प्रबंधन की उज्जरती दर पर कार्य कर रहे कर्मकार, श्री बी कृष्णा रेड्डी की 4-5-83 से सेवा समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० एल-43012/18/83-डी-3(बी)]

ORDER

S.O. 2476.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mangampet Mines of Messrs Andhra Pradesh Mining Corporation, Post Office Mangampet and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the management of Mangampet Biarytes Mines of Andhra Pradesh Mining Corporation are justified in dismissing Shri B. Krishna Reddy, a piece-rated worker, from service with effect from 4-5-83? If not to what relief is the workman concerned entitled?”

[No. 1-43012(18)/83-D.III(B)]

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1984

आदेश

का० आ० 2477—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स उदयपुर मिनरल डिवलपमेंट सिण्टीकेट प्राइवेट लि०, पोस्ट बाक्स संख्या-5, भीलवाडा-311001 के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद

को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स उदयपुर मिनेरल डिवलपमेंट सिण्डीकेट प्राइवेट लि० भिलवाडा के प्रबंधन की सहायक स्टोर कीपर, श्री के० एस० रणवात, को अपनी भगवासा सोपस्टोन माइन में 16-1-84 को ड्यूटी ग्रहण न करने देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० एन-29012/20/84-डी 3(बी)]

नन्द लाल, अवसर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 1984

ORDER

S.O. 2477.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Udaipur Mineral Development Syndicate Private Ltd., Post Box No. 5, Bhilwara-311001 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs Udaipur Mineral Development Syndicate Private Ltd., Bhilwara were justified in not allowing Shri K. S. Ranwat, Assistant Store Keeper, to join duty on 16-1-84 at their Bhagwasa Soapstone mine ? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-29012(20)/84-D.III(B)]
NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 1984

आदेश

का.भा. 2478—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, रामागुण्डम डिवीजन-I के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० एन० राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, रामागुण्डम डिवीजन-I के प्रबंधन की गोदावरी खानी-I इस्काइन में

जनरल मजदूर श्री उसीकमान्ला लाचुलु की 9-8-1982 से सेवा समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० एन-22012/35/83-डी-3 (बी) डी-2 (बी)]

New Delhi, the 16th June, 1984

ORDER

S.O. 2478.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division I and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action taken by the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., Ramagundam Division I in terminating the services of Shri Usikamalla Lachulu, General Mazdoor Godavari Khani I incline w.e.f. 9th August, 1982 is justified ? If not, to what relief, the workman is entitled ?

[No. L-22012/35/83-D.III(B)/D. II(B)]

का.भा. 2479—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, बेल्लमपल्ली के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० एन० राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड बेल्लमपल्ली के प्रबंधन की ग्रेड-I लिफ्ट, श्री एम० नारायण को सोमागुडम संख्या-I ए इस्काइन में पिट कार्यालय सहायक के रूप में नियमित न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो श्री एस० नारायण किस अनुतोष के हकदार है ?”

[सं० एन-22011/68/82-डी-3 (बी) डी-2 (बी)]

S.O. 2479.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli is justified in not regularising Sri S. Narayana Grade-I Clerk as Pit Office Assistant in Semagudem No. 1A Incline? If not, to what relief is Sri S. Narayana entitled?"

[No. L-22011/66/82-D.III(B)/D. II(B)]

का०अ० 2480.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम. एन. राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद की श्री एम. ए. अजीम को अवसर श्रेणी लिपिक के रूप में 26-2-76 से पदावनत करने और हैदराबाद में तैनात करने की कार्यवाही न्यायोचित है जबकि उससे कनिष्ठ उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में हैदराबाद में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एन-15012/3/83-डी-2(बी)]

S.O. 2480.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Employees State Insurance Corporation Hyderabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. N. Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Hyderabad in reverting Shri M. A. Azem as L.D.C. from 26-2-76 and posting him at Hyderabad when his juniors were officiating at UDCs at Hyderabad is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. L-15012(3)/83-D.II(B)]

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1984

प्रदेश

का. आ. 2481.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में 57 फ़िल्ड रेजिमेंट मार्फ़त 56 ए. पी. ओ. के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेंद्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कमांडिंग आफ़िसर 57 फ़िल्ड रेजिमेंट मार्फ़त 56 ए० पी० ओ० द्वारा भिविलियन बर्दई, श्री हनुमान पान पुत्र श्री नाथू राम की पहली अप्रैल, 1983 से सेवा समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं. एन-13012/१/83-डी-2 (बी)]

टी. बी. सीतारामन, अवसर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 1984

ORDER

S.O. 2481.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of 57 Field Regiment C/o 56 A.P.O. and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the termination of services of Shri Hanuman Lal, S/o Shri Nathu Ram, Civilian Carpenter by the Commanding Officer, 57 Field Regiment C/o 56 APO with effect from the 1st April, 1983 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

[No. L-13012(8)/83-D.II (B)]
T. B. SITARAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 20th July, 1984

S.O. 2482.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Telecom Factory, Deonar, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 4th July, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-11 of 1978

AND

PARTIES:

Employers in relation to Telecom Factory, Deonar, Bombay.

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the employer—Mr. B. M. Masurkar, Advocate.

For the Posts and Telegraphs Mazdoor Union, Bombay—Mr. S. G. Wakankar, Secretary.

For Telephone Workers' Union, Bombay—Mr. R. M. Oke, Hon. General Secretary.

For All India P&T Workers' Union, Bombay—Mr. S. R. Wagh, Gen. Secretary.

INDUSTRY: Telecommunication. **STATE:** Maharashtra
Bombay, the 9th May, 1984

AWARD

This reference No. L-42011(4)/766-D.II(B) dated 28th February, 1978, worded in the following manner is referred to this Tribunal under Section 10, sub-section 1(d) of the Industrial Disputes Act, 1947:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Telecom Factory, Bombay in increasing the bus fares with effect from 1-8-1976 for the subsidised transport facility enjoyed by the workmen since 1968, is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. The workmen in the Telecom Factory in their statement of claim have set out the circumstances in which transport facility was provided in the year 1968 for the first time the Factory was shifted from Gell Street, Agripada, to Deonar which was at that time not a developed area. They pointed out that the subsidised departmental transport was agreed to be provided by the Ministry then. Accordingly, none buses were purchased and the departmental buses had started from March 1969 to maintain service between Dadar Railway station to Deonar and similarly from Kurla railway station to Deonar. The transport charges which were fixed that time initially from Dadar to Deonar were Rs. 10 for pay range up to Rs. 300, Rs. 18 for pay range from Rs. 301 to Rs. 599 and Rs. 25 for pay range from Rs. 600 and above. From Kurla to Deonar the same was Rs. 8, Rs. 15 and Rs. 20 respectively. According to the workmen, this was fixed taking into account the non-recurring capital expenditure, annual recurring expenditure and the subsidy which according to them then worked out to 56 per cent.

3. With effect from 1st August, 1979, which is the material date for the purposes of this reference the fare charge was split in two divisions upto Rs. 400 and above. From Dadar to Deonar it was Rs. 9 for pay range upto Rs. 400 and Rs. 12 for pay range of Rs. 401 and above. From Kurla to Deonar the same was Rs. 7 and Rs. 11 respectively. This fare continued until it was sought to be refixed with effect from 1st August, 1976, giving rise to this reference. The proposed revision was that upto pay of Rs. 650 the bus fare between Dadar to Deonar would be Rs. 25 and above Rs. 650 it should be Rs. 28. Similarly, from Kurla it should be Rs. 20 and Rs. 22 and from Sion where apparently new service was started it was Rs. 15 and Rs. 18. The workmen

also pointed out that after this dispute was raised and the matter was taken up before the Regional Labour Commissioner the fares were reduced unilaterally with effect from 1st March, 1977 downwards, from Dadar the fare was reduced to Rs. 16 and Rs. 20 and from Deonar to Sion as also Kurla at Rs. 12 and Rs. 16 respectively for the pay differential.

4. According to the workmen, subsidised bus fare should be fixed only on the basis of fuel consumption. The fleet of the factory has become very old and it has actually outlived its life. Repairs, therefore, and maintenance has become more costly. That should not add to the cost of maintenance of transport service and the workmen should not be called upon to pay for it. The subsidy percentage should be maintained and the workmen should be called upon to pay only the shortfall. Their further contention is that the staff strength in the factory has continued to the same while production has increased resulting in higher and higher profits to the factory. Therefore, it is their case that bus rates should be fixed only on the basis of fuel consumption taking into account the subsidy payable the rates prevailing in March 1970 be continued to prevail.

5. The justification which the employer-factory has given is that the cost of running the service has increased on account of increases in cost of fuel, spare parts and other ancillaries and maintenance. According to it, the President after considering all the matters decided to raise the fare and they have merely implemented the President's decision. They have, however, provided a comparable table showing what was the cost of bus fares by B.E.S.T. between the two stations between which the present transport service is maintained showing that it is higher. In other words, the employer seems to content that had the workmen been required to travel the distance by public transport they would have been required to pay much more than what they are paying. It may be mentioned, however, that even according to that justification the bus fares which are recovered from passengers travelling from Kurla and passengers travelling from Sion and Kurla who are in the receipt of salary above Rs. 650/- would have been required to pay less by the public transport than what was proposed to be recovered from them with effect from 1-8-1976 by the factory.

6. The reference calls for adjudication as to whether the proposed rise in the fares with effect from 1-8-1976 is justified or the subsidised transport facility. It may be emphasised and mentioned that the reference itself speaks of transport facility as one "subsidised". It is, therefore clear that what was being made available to the workmen was something which the Government subsidised like in the case of a canteen.

7. It is unfortunate, however, that only at the end what was the subsidy agreed upon to be borne by the department or the Government either at the initial stages in 1969 or 1979, or on what amount of subsidy or percentage of subsidy on which proposed revised fares with effect from 1-8-1976 were worked out was not clarified. It was only at the end when I called upon the employer to state what was the percentage of subsidy that any light was thrown on the subject.

8. It is quite clear that what was in 1969 cannot be what should be in 1976. The upward revision of the bus fares, therefore, would be justified. The problem, however, is not over with this generalisation. It has to be found out though the reference does not in so many words says, so the extent of the justification for the rise. It was not disputed that from what were the prevailing rates or what were the cost of operating the bus service which were prevailing in 1969, those in 1976 had undergone an upward change.

9. A number of statements have been filed both on the side of the workmen as well as on the side of the employer. Not all of them are relevant but a few. They give us an idea as to what is the expenditure incurred whether it is increasing, stagnant or falling and in what proportion and on what account. I shall presently refer to these statements.

10. I may, however, put aside the question of subsidy in the first instance to clear the ground for considering the other aspects of the matter viz., justification for revision and the extent of the justification. I may in this context refer to a

letter from the President, Telephone Workers' Union, to the General Manager, P&I Workshops, Calcutta, dated 7th December, 1968, and minutes of the meeting of the Expenditure Finance Committee held on 10-5-1968. The letter of the 7th December, 1968, suggests that the subsidy should be 60 per cent and 67 per cent instead of 50 per cent which was worked out then. According to it, Rs. 7 per person per month worked out the subsidy at 60 per cent. The proposal then was to limit the subsidy to 50 per cent and according to the union it should have been raised to 67 per cent so that the flat rate of Rs. 5 could be charged per person per month. This was admitted to be done on the basis of the capital cost which was then worked out at Rs. 1,34,570, the depreciation was calculated upon that at various rates to Rs. 55,355. The other heads of expenditure accounted to another Rs. 13,000 and operating expenses such as cost of oil and spare parts and engineering and repairs expenses, etc. to another Rs. 86,000.

11. The minutes of the meeting of the 10th May, 1968, do not disclose fixation of any specific percentage of the subsidy. It fixed three slab rates varying with the pay group; below Rs. 300, between Rs. 300 to Rs. 600 and Rs. 600 and above at different levels. The trend of the discussion seems to indicate the maintenance of a differential of subsidy depending upon the pay group. On the other hand, the instance of the Atomic Energy establishment charging a flat rate at a much lower level per month was cited before the committee. One more document which is a memorandum dated 22nd April, 1968, when the bus service was in the proposal stage, works out the cost on the basis of various figures which had been given as annexure 'I'. That would not really be of any assistance to us in the present context as the reference calls for the Tribunal to decide whether the rise in the fares was justified, and as I have pointed the ancillary part thereof, if it was justified to what extent it was justified. As I have stated earlier the justification for the rise is to be found in the circumstances and general price rise and admitted increase in the case of every input such as diesel, lubrication oil, spare parts, tyres and tubes, pay and allowances of operating staff, cost of repairs, and maintenance and depreciation on the assets already installed. It would have been better if the department had fixed upon, as a matter of policy the percentage of subsidy to be given. Instead it has chosen to leave the formula of subsidy in a fluid form and has not chosen to give a particular figure. In order that this question, in a situation where prices are continuously rising of every material and service, not become a source of continuing friction and dispute between the employer and members of the staff over the bus transport it would be advisable and proper to fix the percentage of subsidy which the department was prepared to bear. It would also be advisable to have national policy or uniform policy on this issue, in as much as there are and there are likely to be factories producing this material not only in Bombay, but all over the country. Indeed an attempt was sought to be made during the late stages of the argument that the subsidy which is being paid for similar transport service to other workmen in the factories located at other stations eg. Bhillai is 67 per cent. In order, therefore, there should be some uniformity in subsidised bus service, there should be a uniformity in the level of subsidy which the department wishes to undertake. At the time when this question was first considered in the minutes of the meeting of 1st May, 1968, what was envisaged was a gradual discontinuation of the transport service. This now seems to be a far-cry and the subsidised bus transport has apparently come to stay.

12. Turning now to the various statements it seems to me that they clearly justify the increase in the bus fares. Two sets of statements have been filed, one relating to the period between 1970 and 1976 and the other relating to the period between 1976 and 1982. Broadly speaking statements relating to the period 1976 to 1982 are not relevant except to show that there is no regression of the expenses on account of the transport service, but that they have kept on rising even after 1976 when the revision was made. I will, therefore, confine myself in the present discussion to the first set, since limits of the reference call upon the Tribunal to decide justification of the fare increase with effect from 1st August, 1976, which has been reduced from March 1977 again. The statements filed by the employer are not entirely satisfactory. It may be mentioned that when this reference came up for hearing excepting the justification which

was given in the written statement that the President had passed an order no other data or material, not even to what extent, how and since when there is an upward revision of prices of such materials like diesel, oil, engineering spare parts, tyres and tubes salary of operating staff, etc. was provided. By an order dated 21st February, 1984, I directed the employer-factory to file statements "showing the increased cost of fuel, increased cost of spare parts, tyres, tubes, increased wage bill, etc." It was thereafter and in accordance with these directions only that on the 19th March, 1984, the employer filed certain documents to which I shall presently refer. What was done before that was to file statements relating to expenditure between the period 1976 and 1982.

13. These statements now show whatever position they are related under three heads classified as statements 'A', 'B' and 'D'. Statement 'A' relates to expenditure on account of spare parts, repairs and service, statement 'B' pay and allowances of transport staff, and statement 'D' cost of fuel consumption. The abstract also goes to show that cost of diesel per litre was raised to Rs. 1.06 in 1974 and 1975. With effect from 14th July 1975 it was raised to Rs. 1.26. The employer-factory has, however, not mentioned the quantity of diesel in litres consumed by it year by year. It has merely given the cost which was incurred per year. That would have facilitated finding out whether there is increase in the consumption of diesel oil. Statements 'A', 'B' & 'D', however, clearly go to show that the expenditure year by year on spare parts, pay and allowances and use of diesel oil has been going up and up. With regard to expenses on spare parts it appears that in the years 1972-73 and 1973-74 a considerable amount was spent Rs. 63,227 and Rs. 43,330 on these items. Since then for the year 1974-75 and 1975-76 these figures have fallen to come to the level of 1971-72 expenditure of Rs. 21,804. The figures of expenditure on this account for the year 1975-76 is lesser than that for the year 1974-75. It appears apparently major repair costs were incurred in the year 1972-73, 1973-74 and partly also in the year 1974-75. This does not include the cost of depreciation per year on the fixed permanent assets or movable assets such as the fleet of buses. The rate at which the depreciation is to be calculated is also not clear. Apparently the rate at which this was counted when the various proposals were put forward, so far as buses were concerned was at 10 per cent, so far as the other equipment and fittings were concerned at about 4-1/2 and with regard to lands and buildings at 1 per cent. I do not think that this rate of depreciation is according to the recognised standard accountancy procedures. In any event, where transport is being subsidised by the employer it is also necessary for it in order to impart a rational, logical basis of devising the fare system to fix the rate of depreciation in regard of each item of asset installed.

14. The fourth statement which is statement 'C' shows the amount of recoveries by way of fares from the passengers between the period 1971 and 1976. This has remained virtually stationary with minor fluctuations. The difference between realisations and actual expenditure taking into account only three heads of expenses viz., cost of spare parts, repairs, servicing, pay and allowances of transport operating staff and cost of fuel has been rising from year to year. In the year of considerable expenditure on account of repairs viz., 1972-73 and 1973-74 the shortfall is to the tune of Rs. 74,000 and Rs. 94,000. Year by year it produced a different percentage of loss which may be described as subsidy by the Government. In the absence of a fixed percentage of subsidy, in the absence of complete figures with regard to the calculation of other overhead expenses, and depreciation as well as the possible increased expenditure likely to be required on account replacement of worn out assets such as the fleet of buses it is extremely difficult to fix a rate structure of fares, and to provide a comparable scale for future guidance. The worked out depreciation over the year may not provide the full cost of replacement. It is well known that it far exceeds. This assistance was not forthcoming particularly from the employer who had both the material information and data as well as the capacity to do so. I do not expect, and the workmen could not have been expected on their own to provide any such formula or such material on the basis of which exact fares or their variable proportion or percentage with the rising cost could have been fixed. Consequently, I have to address the question in a broad manner only.

15. One constantly rising factor in the expenses which is incurred is the cost of pay and allowances for the transport staff. From 1971-72 to 1975-76 it has nearly doubled climbing from Rs. 52,500 to Rs. 92,600. For the year subsequent to 1976 the rising trend continues and in the year 1981-82 the total expenditure incurred on this account stood at Rs. 1,20,830.39. This pattern as to be seen and is present in all other heads of expenditure. This is borne out clearly by the other statements for the period 1976 to 1982. The average cost for these six-year period of operation of only three material heads of expenditures has come to Rs. 3,49,000 while the fare realised is about Rs. 1,73,318.66 leaving a gap of Rs. 1,76,668.43.

16. These figures to which I have drawn attention, besides the general rise in the prices of which judicial note can be taken is a universal formula particularly known to be present in our country. As there is an increase, the increased cost of everything justifies the revision of fares. I have pointed out that in 1975-76 before the increase of fares with effect from 1-8-1976 the difference was Rs. 78,000. These fares were subsequently reduced from the year 1977-78. The years 1977-78 and 1978-79 would, therefore, be the relevant years and the figures, therefore, for increase as well as the earnings, useful in order to determine the extent of justification of the fare rise. For the years 1977-78 the fare realisation was Rs. 1,59,000 (committing the remaining digits after three) for the year 1978-79 it is Rs. 1,60,000. While expenses for these two years on account of pay and allowance for transport staff, maintenance and repairs and cost of diesel alone comes to Rs. 2,81,689 for the year 1977-78 and Rs. 2,79,482 for the year 1978-79. I have already referred to the realisation from the workmen for those years which worked out to a little more than 50 per cent of the expenditure. However, the expenditure does not take into account other factors to which I have already drawn attention.

17. The contention of the workmen was that if the department was to pay or suffer 67 per cent of the expenses incurred on account of providing transport then there is scope for further reduction of the fares. On that basis it was their contention that what was done on 1-8-1976 was not justified. Though it was not disputed that the increase in the fares would be justified on account of the rise in the cost of various such items the extent to which it was attempted to be raised was strongly disputed.

18. I have already pointed out the difficulties, and circumstances, want of assistance and material, and on account of absence of any specific decision of the department regarding subsidy to fix a particular ratio or amount as the extent to which the fare increase would be justified. For this result the employer largely is to be blamed. In spite of orders adequate material was not produced. To some extent the employer was handicapped in the absence of a decision at higher level of the amount of percentage of subsidy. The circumstance and the fact that the employer himself due to agitation and representation by the workmen reduced the fare charged from those fixed with effect from 1-8-1976 though reduced later from March 1971, go to show that the extent of the rise was unjustified. I have already indicated my inability to fix, in the circumstances, what increase should be. Confirming however, my attention to the two years 1977-78 and 1978-79 which are the immediate following years after the reduction of the fares for that proposed on 1-8-1976, as I indicated above a little less than 50 per cent of the cost is being, in any event, borne by the department. To this have to be added certain other heads of expenditure and cost. In the circumstances, the fare fixed at the revised level from March 1977 it seems to me to be fair. The reference, therefore, has to be answered in the first part in the negative with regard to the extent it has to be held in the absence of adequate material that the fares charged with effect from 1st March, 1977, seem to be justifiable.

19. There is one more aspect of the matter which requires attention. This is a case of subsidised transport. There does not appear to be any rational in introducing the two stage fares depending upon the pay slab of the workmen concerned. The cost incurred in uniform whether the persons availing of the facility of transport is drawing a salary of above Rs. 600 or below Rs. 550. It is the cost of the service rendered, irrespective of who is taking the benefit of those service that subsidy has to be determined. If it is the inten-

tion to deny this facility of subsidy to better paid members of staff, then the result can be achieved by limiting the number of such persons instead of by introducing a difference in the fare structure. But, that is an entirely different matter.

20. Award accordingly. No order as to costs.

R. D. TULPUL, Presiding Officer

[No. L-40011(4)/76-D.II(B)]

T. B. SITARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

आदेश

का० आ० 2483—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आई. पांडु रंगाराव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन द्वारा रोजगार कार्यालयों द्वारा नामित उम्मीदवारों के साथ भूतपूर्व चौकीदार, श्री के० मकबूल अहमद की नियुक्ति के बारे में विचार न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० एल-42012/2/83-डी-4(बी)डी-5]

एस. एस. मेहता, डेस्क अधिकारी ।

New Delhi, the 28th June, 1984

ORDER

S.O. 2483.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Food Corporation of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri I. Pandu Rangarao shall be the Presiding officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the management of the Food Corporation of India is justified in not considering Shri K. Maqbool Ahmed, ex-watchman for appointment along with the Employment Exchange sponsored candidates ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

[F. No. L-42012(2)/83-D.IV (B)/DV]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 12th July, 1984

S.O. 2484.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Coal India Ltd., North Eastern Coalfields, Margherita, P.O. Margherita Distt. Dibrugarh Assam and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th July, 1984.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CALCUTTA**

Reference No. 30 of 1981

PARTIES :

Employers, in relation to the management of Coal India Limited, North Eastern Coalfields, Margherita, P.O. Margherita, Distt. Dibrugarh, Assam.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Employer—None.

On behalf of Workmen—None.

STATE : Assam

INDUSTRY : Coal

AWARD

By Order No. L-24012(4)/81-D.IV (B) dated 24th July, 1981, the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Coal India Limited, North Eastern Coalfields Margherita, P.O. Margherita, District Dibrugarh, Assam in dismissing Smt. M. Papma, Sweepers, Hospital without following Company Certified Standing Orders dated 18-7-1955 is justified ? If not to what relief the workmen is entitled to ?”

2. The instant reference was pending before this Tribunal for adjudication. But in the meantime, as per decision of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, the instant case was sent for conciliation by the Regional Labour Commissioner (C), Gauhati.

3. The Regional Labour Commissioner (C), Gauhati has informed this Tribunal by this letter No. 8(5)/84-G/RLC dated 20-6-84 at the instant reference has been settled between the parties on the following terms :

- Keeping in view of the contents of the letter dated 23-2-83 written by Smt. M. Papma to the management, the Union has agreed not to contest the instant industrial dispute before the Tribunal.
- It is agreed by the management that as per the request made by Smt. M. Papma in her letter dated 23-2-83, management shall offer a letter of appointment to her son named Sri Anand Rao on the post of sweeper with a view to provide permanent source of income to his ailing father and ageing mother.
- It is agreed between the parties that copy of the settlement will be placed by them jointly before the Central Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Calcutta with a request to the Tribunal to pass award in terms of the settlement. Any other demand before the Tribunal not mentioned above will also be deemed to have been withdrawn by the workmen/Union.
- Agreed that both the parties shall send copy of the award given by the Tribunal in terms of the settlement to the Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi and Regional Labour Commissioner (C), Gauhati.

As per para 3 of the terms of settlement both parties were to place the copy of the settlement before this Tribunal.

However, I do not think it necessary to wait for their copies since a copy of the settlement has already been received from the Conciliation Officer himself.

4. On a perusal of the settlement I find the terms are just, fair, proper and in the interests of both parties. I accept the same.

Accordingly I pass my award in terms of settlement. The letter dated 20-6-84 of Regional Labour Commissioner (Central) Gauhati with its enclosures including the terms of settlement shall form part of this award and the same is marked as Annexure—“A”.

This is my award.

Dated, Calcutta,
the 25th June, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-24012(4)/81-D.IV (B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer
Registered

(Copy)

ANNEXURE ‘A’

MINISTRY OF LABOUR

Office of the Regional Labour Commissioner (C), Ashram
Road, Guwahati-7

Dated, the 20th June, 1984

No. 8(5)/84-G/RLC

To

The Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court, 20, British Indian Street, 1st Floor,
Calcutta-700069.

Subject.—Industrial Dispute between the management of Coal India Ltd., N. E. Coal Fields, Margherita and their workmen represented by the General Secretary, Assam Coal Mines Mazdoor Union (AITUC), Margherita over the issue of dismissal of Smt. M. Papma. Sweepers pending before the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Calcutta.

Reference No. 30 of 1981

Sir,

This has a reference of D.O. letter No. Co 4/1(5)/ITC/83-1438 dated 6-10-83 from Justice M. P. Singh, Presiding Officer addressed to the underground regarding pending cases pertaining to this be at more than two years old as on 3-9-83 inter-alia containing the Industrial Dispute of Smt. M. Papma, Sweepers, Coal India Ltd., N. E. Coal Fields, Margherita.

In terms of directives contained in Para 2 of D.O. No. 15(11)/83-SC dated 12-9-83 (copy enclosed—Annexure-I) from Shri K. Sharan, the then CLC(C), New Delhi addressed to the undersigned, effective measures were taken by me to resolve the instant Industrial Dispute amicably between the parties. As a result of effective steps taken by me this Industrial Dispute was settled amicably and tripartite settlement was signed on 13/14-6-74 a copy of which is enclosed herewith (Annexure-II) for your kind information and further necessary action.

Yours faithfully,
Sd/-

J. P. CHANDRA, Regional Labour
Commissioner (C), Guwahati.

Encl : Six pages.

Copy to :

- The CLC(C), New Delhi (By name Shri K. Sharan, Jt. CLC(C), New Delhi in reference of his D.O. letter quoted above.
- The File No. 63(25)/83-SE-G/RLC.

Regional Labour Commissioner (C),
Gauhati

**ANNEXURE ‘A’
FORM ‘H’**

(Copy)

(See Rule 58)

Industrial Dispute Central Rules, 1957, Memorandum of settlement under section 12(3) of the Industrial Dispute Act,

1947 as amended entered between the management of Coal India Limited, North Eastern Coalfields, Margherita, P.O. Margherita, Dist. Dibrugarh (Assam) and Assam Coal Mines Mazdoor Union (AITUC) P.O. Margherita, Dist. Dibrugarh (Assam) in respect of the Industrial Dispute relating to the dismissal of Smt. M. Papma, Sweepers, Central Hospital referred for adjudication and still pending before the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Calcutta (Ref. No. 30 of 1981). In the course of the Conciliation proceedings held by the Regional Labour Commissioner (Central) Gauhati at Margherita.

Name of the Parties

Representing Employer :

Shri S. N. Bhatt,
Deputy General Manager,
Coal India Limited,
North Eastern Coalfields,
Margherita, Assam.

Representing Workmen :

Shri B. P. Hazarika,
General Secretary,
Assam Coal Mines Mazdoor
Union (AITUC), Margherita,
Assam.

Short Recital of the case

The General Secretary, ACMMU, Margherita raised an industrial dispute before the A.L.C. (C), Gauhati vide his letter No. GR/4/251.80/ACMMU dated 13-11-80 addressed to R.L.C. (C), Calcutta endorsing a copy thereof to the A.L.C. (C) Gauhati-7 over the alleged illegal dismissal of Smt. M. Papma, Sweepers, who was working in the Central Hospital, Margherita and demanding her reinstatement. The matter was seized in conciliation by the A.L.C. (C), Gauhati and since there was no settlement in the dispute, the A.L.C. (C), Gauhati send report of failure of conciliation to the Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The Desk Officer Government of India, Ministry of Labour, New Delhi vide its order No. L-24012(4)/81-D.IV (B) dated 24-4-81 referred the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta. This dispute is still pending before the Hon'ble Tribunal.

Since the aforesaid dispute is pending before the Tribunal for a period exceeding two years prior to September, 1983 the R.L.C. (C) Gauhati initiated conciliation proceedings in the said dispute and the proceedings were fixed on 13-6-84 in the Guest House of Coal India Ltd., Margherita and both the parties were informed to attend the proceedings accordingly on the said date. This action was taken by the R.L.C. (C) Gauhati in terms of directive contained in the DO letter No. 15(11)/83-BE dated 12-9-83 from the Chief Labour Commissioner (C), New Delhi.

On the aforesaid date the dispute was discussed between the parties at length. During the course of discussion the Union stated that Smt. M. Papma was dismissed by the management in an unjustified manner ignoring the provision of law and, therefore, they demanded her reinstatement with retrospective effect with all benefits. The management on the other hand contended that Smt. M. Papma was dismissed on certain charges of serious misconduct, and a Departmental Enquiry was held providing full opportunity to the said workmen to defend her case. The charges were established against her and accordingly she was dismissed from the services with effect from 1-10-80. The action taken by the management was justified and the demand of the Union for her reinstatement cannot be met with. It was further contended by the management that Smt. M. Papma vide her letter dated 28-2-83 copy produced during the course of proceedings and the General Secretary, ACMMU was given a copy of the same Annexure-I addressed to the Dy. General Manager, North Eastern Coalfields, Coal India Ltd., Margherita intimated to the management that due to serious sickness of her husband she has decided to go to her native home at Andhra Pradesh and it will not be possible for her to pursue the industrial dispute proceedings to her dismissal before the Industrial Tribunal Calcutta and accordingly she decided not to content the dispute, together with a request to pay her final dues to enable her to leave Margherita permanently. Accordingly, all her dues were paid to her and

she had already left this place long back. In the same letter it was also requested by her to provide employment on sympathetic and humanitarian ground to her son Sri Anand Rao in the Sanitation Department of the Company. As such the instant dispute does not exist.

The R.L.C. (C) Gauhati already discussed with representatives of both the parties on 20-2-84 and made certain suggestions to both the parties for settling amicably the instant industrial dispute. The conciliation proceedings in respect of the instant industrial dispute were held on 13-6-84 in the Guest House of Coal India Ltd., Margherita in which representatives of both the parties participated. As a result of his persuasion the instant industrial dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :

Terms of settlement

1. Keeping in view the contents of the letter dated 28-2-83 written by Smt. M. Papma to the management, the Union has, agreed not to contest the instant industrial dispute before the Tribunal.
2. It is agreed by the management that as per the request made by Smt. M. Papma in her letter dated 28-2-83 management shall offer a letter of appointment to her son named Sri Anand Rao on the post of sweeper with a view to provide permanent source of income to his ailing father and ageing mother.
3. It is agreed between the parties that copy of the settlement will be placed by them jointly before the Central Industrial Tribunal cum Labour Court, Calcutta with a request to the Tribunal to pass award in terms of the settlement. Any other demand before the Tribunal not mentioned above will also be deemed to have been withdrawn by the workmen/Union.
4. Agreed that both the parties shall send copy of the award given by the Tribunal in terms of the settlement to the Office of Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi and Regional Labour Commissioner (C), Gauhati.

Signature of the Parties

Representing employer :

Sd/-
S. N. Bhatt
Dy. General Manager
North Eastern Coalfields
Coal India Ltd., Margherita.

Representing workmen :

Sd/-
B. P. Hazarika
General Secretary
Assam Coal Mines Mazdoor
Union (AITUC) Margherita.

WITNESS :

1. Sd/-
S. S. Mundra
Asstt. Labour Commissioner (C)
Gauhati.
2. Sd/-
G. B. Pandit
Labour Enforcement Officer (C)
Dibrugarh.

Signed before me
Sd/- J. P. Chandra, Regional Labour
Commissioner (C) and Conciliation Officer

Dated, Margherita,
the 13th June 84.

(COPY)

To

The Dy. General Manager,
North Eastern Coalfields,
Coal India Limited,
P.O. Margherita : Assam.

Sir,

I have been honour to inform you that my husband has become seriously ill and I have decided to go to my native home at Andhra Pradesh.

As such it will not be possible for me to continue with the case lying in Arbitration and I am desirous to withdraw the same

In view of the circumstances I would request your honour to kindly do the needful in this respect and arrange payment of my dues to enable me to leave this place permanently

I would also request your honour to consider my situation with a sympathetic view and provide my son Sri Anand Rao in the sanitation department of the Company

I hope I shall not be deprived of your favourable order in this respect for which act of your kindness I shall remain evergrateful.

Yours faithfully,
RIT of M Papma
(M Papma)
Central Hospital, North
Eastern Coalfields
Coal India Ltd.
Margheita 28-2-83

(COPY)

Copy of D.O. letter No 15(11)/83-SC dated 12-9-83 from Shri K. Sharan, CLC(C), New Delhi addressed to Shri J. P. Chandra, R.L.C (C), **Gauhati**.

In the meeting of the Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Courts, held at New Delhi on September 3, 1983, it has been decided that the efforts will be made by the Regional Labour Commissioners to use their good offices in bringing about compromise between the concerned employers and workmen/Trade Unions in respect of reference which have been pending with the Industrial Tribunals for periods exceeding 2 years prior to September 3, 1983

2 The Secretary desires that RLCs should have informal discussions with the concerned Presiding Officers of the Central Government Industrial Tribunals to find out relevant details in respect of those reference which are pending with them for a period exceeding 2 years prior to September 3, 1983 and after obtaining the relevant details they should make sincere efforts by calling upon the representatives of the concerned managements and workmen/Trade Unions and persuading them to question and to file joint application before the concerned Industrials praying therein to consider the terms of settlement as fair and to give award in terms of the settlement

3 Accordingly, you are requested to contact the Presiding Officer(s) of Central Government Industrial Tribunals, the headquarters of which is/are located in your region and collect complete details in respect of references (including those which pertain to other regions also) pending adjudication for a period exceeding 2 years prior to September 3, 1984 and submit these details to me in the enclosed proforma. Simultaneously you should forward the relevant details in respect of relevant reference pertaining to other regions to the RLCs concerned in the same proforma endorsing a copy thereof to me. I am separately writing D.O. letters to the Presiding Officers of the Central Government Industrial Tribunals to extant you all cooperation in this regard

4 After obtaining the relevant information or as the case may be after receiving the relevant particulars from the RLCs you should take necessary action in cases pertaining to your region in the manner indicated in para 2 and also keep informed of the progress made by you in this regard every month so as to enable me to report the same to the Secretary

5 I am confident you will pull your weight and make sincere efforts to achieve the desired result, which will go a long way in increasing the honour and credibility of the Central Industrial Relations Machinery, besides achieving the objective for which this Machinery exists. You should communicate the final outcome of your efforts to the Presiding Officers to the Tribunals concerned demiofficially under intimation to me

6 Before I close I seek your full co-operation in this matter and convey my best wishes to you for your success in this august endeavour

7 Please acknowledge receipt of the D.O. letter

43/GI/84—10

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

आदेश

का आ 2485 — भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली के प्रबन्धन में सम्बद्ध नियाजको और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन, काडला करती है के बीच एक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियाजको और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को जो उसे 27 जून, 1984 को मिला था, एनदृष्टांग प्रकाशित करती है।

(करार)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)
भारतीय खाद्य निगम

और

ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन के बीच
पक्षकारों के नाम

नियाजको का प्रतिनिधित्व करने वाले

1 एस एस भाटिया
वाणिज्यिक प्रबन्धक
भारतीय खाद्य निगम
नई दिल्ली।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

1 श्री मनाहर
कोतवाल
अध्यक्ष,
ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक
वर्कर्स यूनियन,
काण्डला।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच जी. भावे उप मुख्य श्रमायुक्त भारत सरकार श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का करार किया गया है।

पता —

श्री एच जी भावे
उप मुख्य श्रमायुक्त,
श्रम शक्ति भवन
रफी अहमद किवर्डी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

(1) विनिर्दिष्ट विवाद प्रश्न विषय —

“परिवहन और पोत परिवहन मंत्रालय तथा पत्तन और गोदी श्रमिकों की वार अधिनियम भारतीय फेडरेशन के बीच तारीख 4-1-1981 को हुए समझौते की शर्त सख्या 21.1 को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य का भी ध्यान में रखते हुए कि काण्डला पत्तन में अनाज हैण्डल करने वाले श्रमिकों में निम्न पत्तन और श्रमिकों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में “परिणाम—याजना” द्वारा वर्तमान अदायगीया विद्यमान याजना के अस्तित्व में रहते हुए भी काण्डला डाक लेबर वार्क के तारीख 28-1-1983 के ज्ञापन सख्या 361 द्वारा जैसा कि परिवहन तथा पोतपरिवहन मंत्रालय के तारीख 26-2-83 के पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था 1-4-1981 से संशोधित की गई थी, क्या तारीख 4-11-1980 के करार, जो समाप्त हो जाने पर उक्त समझौते को 1-8-1983 के समूह के

भारतीय खाद्य निगम के दावे के बावजूद भी, काण्डला पत्तन में भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की यह मांग न्यायोचित है कि उनके वरों में 1-4-81 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाय ? यदि हाँ, तो वे किस अनुसूच के लिए किस तारीख से हकदार हैं ?

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण — भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली और काण्डला पत्तन में नियोजित उनके कर्मकार ।

पता :—

भारतीय खाद्य निगम
16-20 बारा खम्भा
लेन नई दिल्ली ।

(3) कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले — ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन, काण्डला ।

पता :—

मार्फत ट्रांसपोर्ट एण्ड
डाक वर्कर्स यूनियन,
काण्डला सवाबला-
बिल्डिंग, नया काण्डला,
जिला भुज (गुजरात)

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 1800

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 1425

हम यह करार भी करने हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा मध्यस्थ अपना पचाट समुचित सरकार द्वारा इस करार को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद एक मास की कालावधि के भीतर देगा ।

तारीख 18 जून, 1984

पक्षकारों के हस्ताक्षर ।

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

ह. - (एम. एस. भाटिया) ह. - (मनोहर कोतवाल) अध्यक्ष,
आणिजिक प्रबन्धक ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स
भारतीय खाद्य निगम यूनियन काण्डला ।
नई दिल्ली ।

माफ़ी

(1) ह. - (2) ह. - (डॉ. एम. प्रभु)
मध्यस्थ की सम्मति

में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन उक्त विवाद में मध्यस्थ बनने के लिए अपनी सहमति देता है ।

ह. -

(एन. जी. भावे)

उप मध्य आयुक्त (केन्द्रीय)

नई दिल्ली

तारीख 12-4-1984

[संख्या-एन-42025/1/84-सी-5]

एम. एस. मेहता, हेड ऑफ़ ऑफ़िस

New Delhi, the 13th July, 1984

S.O. 2485.—Whereas the industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, New Delhi and their workmen represented by Transport & Dock Workers' Union, Kandla;

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 27th June 1984.

AGREEMENT

Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947
BETWEEN

The Food Corporation of India

AND

Transport & Dock Workers' Union, Kandla.

Representing employers —Shri S.S. Bhatia,
Commercial Manager,
Food Corporation of India,
NEW DELHI

Representing workmen —Shri Manohar Kotwal,
President,
Transport & Dock Workers'
Union,
KANDLA

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the Arbitration of Shri H.G. Bhawe, Deputy Chief Labour Commissioner, Government of India in the Ministry of Labour & Employment

Address

—Shri H.G. Bhawe,
Dy. Chief Labour Commissioner,
Shramik Bhavan
Rafi Ahmed Kidwai Marg,
NEW DELHI-110001

(i) Specific matters in dispute—

"Having regard to the term No. 21.1 of the Settlement dated 4-1-1981 reached between the Ministry of Shipping & Transport and the four all India Federations of Port and Dock Workers and further having regard to the fact that the existing payments by result Scheme in respect of other categories of Port and Dock Workers other than food handling workers at the Port of Kandla were revised with effect from 1-4-81 vide Kandla Dock Labour Board resolution No. 361 of 28-1-1983 as approved by Ministry of Shipping and Transport under its letter dated 26-2-83 despite subsisting scheme, whether claims of the FCI workers in Port Kandla to the effect that their rates be revised by 20% with effect from 1-4-81 in spite of the contention of the FCI to make it effective from 1-8-83 on the expiry of the agreement dated 4-11-1980 is justified ? If so, to what relief and from what date are they entitled?"

(ii) Parties to the dispute—

(a) FOOD CORPORATION OF INDIA, NEW DELHI and their workmen employed in the Port of Kandla.

Address : FOOD CORPORATION OF INDIA,
16-20, Barakhamba Lane,
NEW DELHI.

(iii) Representing the workmen—

TRANSPORT & DOCK WORKERS' UNION, KANDLA
Address—C/o TRANSPORT & DOCK WORKERS'
UNION, KANDLA,
Mawawala Bui'ding NEW KANL (Distt
Bhui (Gujarat)

(iv) Total number of workmen employed in the 1800
Undertaking affected

(v) Estimated number of workmen affected by 1425
the dispute

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us. The Arbitrator shall make his Award within a period of one month from the date of publication of this Agreement in the Official Gazette by the appropriate Government

Dt the 18th June, 1984

Signatures of the parties —

For Employers

For workmen

Sd/-

Sd/-

(S S. BHATIA)

(MANOHAR KOTWAL)

Commercial Manager Food
Corporation of India,
NEW DELHI

President,
TRANSPORT AND DOCK
WORKERS' UNION,
KANDLA

Witnesses (1) Sd/-

(2) Sd/- (W S. PRABHU)

Consent of the Arbitrator

I hereby give my consent to act as an arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute

New Delhi, 12-4-84

Sd/-

(H G. BHAVE)

Dy Chief Labour Commissioner
(Central)

[L-42025/1/84-DV]

S S MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 20th July, 1984

SO 2486—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Limited Victoria Chanch, Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th July, 1984

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No 28 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs
Bharat Coking Coal Limited, Victoria Chanch,
Burdwan.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr Justice M. P Singh—Presiding Officer

APPEARANCES :

On behalf of Employer—Mr Bhaskar Gupta, Counsel with
Mr M N Kar, Advocate

486 G of 1/84—10

On behalf of Workmen—Mr Gautam Som, Advocate
STATE West Bengal INDUSTRY Coal.

AWARD

By Order No L-19012(96)/82-DIV(B) dated 11th April, 1983, the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication

"Whether the action of the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, is justified in transferring Shri S P Mondal, Asstt f and Surveyor from the office of the G M to Banantmata Colliery with effect from 22/2-8-81 ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2 A preliminary objection was raised by the management of the BCCL to the effect that the Central Government of India in the Ministry of Labour having once declined to make any reference on 16 August 1982 had no jurisdiction to make the present reference subsequently on 11 April, 1983 without hearing or without giving an opportunity to the management and hence the order of reference is a nullity for violation of the principles of natural justice Mr Gautam Som the learned advocate for the union has not disputed the fact that in the instant case the management of Bharat Coking Coal Ltd was not heard nor was given opportunity of being heard The earlier order of the Central Govt dated 16th August, 1982 refusing to refer runs as unde

"In continuation of this Ministry's letter of even number dated 28-6-82, on the above subject I am directed to say that the Central Government have decided not to refer the above dispute to the Industrial Tribunal for adjudication for the reasons that transfer due to exigency of work is prerogative of the management and that the Union could not substantiate their case of vindictiveness or vendetta"

On a perusal of the above it is clear that the order refusing to refer has indicated the reasons for declining the reference

3 After hearing both sides, I think, Mr Bhaskar Gupta for the management is right in contending that natural justice was violated because after refusing to refer in the first instance no notice was given to the management while making the reference for a second time There are several authorities which support this contention See the cases of Indian Telephone Industries Ltd v State of Karnataka 1978 Lab IC 1779 1978(1) LLJ 544 (Karnataka) American Express International Banking Corporation v Union of India, (1978 79) 83CWN 439 1979(2) LLJ 22(Cal) Muthukrishnan v The Administrative Manager, New Morizan Sugar Mills Pvt Pondicherry, 1980 Lab IC 475 FB(Madras) 1980 LLJ Vol I 215 Dunlop India Ltd, v State of West Bengal 1980 Vol II CLJ 197(Cal) 1981 Lab IC(NOC) 91(Cal) M/s Escorts Ltd, Faridabad v Industrial Tribunal Haryana, 1983 Lab IC 223(Pun & H) In all these cases it has been held that the power once exercised in the negative cannot subsequently be exercised without giving opportunity of hearing to the management before exercising the power and if no such opportunity is given, natural justice is violated and the order is a nullity I may point that it is not a case where the Central Government has changed its mind and reconsidered the matter on account of new facts coming into light or because it had misunderstood the existing facts or because it had overlooked any material fact or for any other relevant consideration It was a simple case of transfer of an employee from one place to another and there could be no question of misunderstanding any fact In fact the government gave reasons in its order of refusal True it is that the power to refer cannot be said to have been exhausted when it has declined to refer at an earlier stage and it can reconsider the matter and change its mind and can make reference for a second time or third time See the case of Avon Services (Production Agencies) Pvt Ltd v Industrial Tribunal Haryana, Faridabad, 1979(1) LLJ 1(SC) But the question is as to how this power should be exercised in a case when the power has earlier been exercised in the negative I think, principles of natural justice have to be observed However wide and extensive the discretionary administrative power of the government under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 may be, it is always possible to require them to be exercised in a manner that is procedurally fair Procedural fairness in administrative decisions is not a matter of secondary importance Government must

act fairly. As Lord Sellaune said in *Spackman v. Plumsfeed District Board of Works* (1885) 10 App. Cas. 229 at 240 :

"There would be no decision within the meaning of the statute if there were anything of that sort done contrary to the essence of justice."

Quoting these words the Privy Council in *Fairmount Investments Ltd. v. Secretary of State for the Environment*, (1976) 1 WLR 1255 at 1263 said that a decision which offends against the principles of natural justice is outside the jurisdiction of the decision making authority. Thus violation of natural justice makes the decision void. In the present case natural justice has been violated because no notice was given to the management before exercising the power to refer in the second time. The order of reference is, therefore, held to be a nullity. If so there is nothing to decide. The reference is thus disposed of.

This is my award.

Dated, Calcutta.

The 28th June, 1984

M. P. SINGH, Presiding Officer.
[No. L-19012(96)/82-D.IV(B)]

S.O. 2487.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of WCL, Kanhan Area and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th July, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(44)/1982

PARTIES :

Employers, in relation to the management of Western Coalfields Limited, Kanhan Area, Post Office Durgaria, District Chhindwara (M.P.) and their workmen mentioned in the Schedule to the order of reference represented through the M. P. Rashtriya Koyala Mazdoor Sangh (INTUC), Sashtri Kasturba Incline Branch Post Office Gudi, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For workmen—Shri S. K. Rao, Advocate.

For management—S/Shri P. S. Nair and Rajendra Menon, Advocates.

INDUSTRY : Coal DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated June, 28, 1984

In exercise of powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 Central Government referred for adjudication the following question :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Limited, Kanhan Area in relation to their Ambara Colliery in stopping 52 senior workmen in the year 1980 and allowing other junior workmen to continue is justified? If not, to what relief these 52 workmen as per list are entitled to?"

LIST OF WORKMEN

1. Shri Sheonarayan S/o Ramsahya.
2. „ Atarlal S/o Rampratap.
3. „ Narbada S/o Ramji.
4. „ Amroo s/o Iharo.
5. „ Rajkumar s/o Balakram.
6. „ Lakhn Lal S/o Thakur Prasad.

7. Shri Jugoo S/o Tulsiram
8. „ Khemchand S/o Saimlal
9. „ Jaganath S/o Tikaram,
10. „ Ganpat S/o Pusia.
11. „ Tikaram S/o Damddu.
12. „ Sagar S/o Chaitram.
13. „ Choteylal S/o Tulsi.
14. „ Mahesh S/o Sukha.
15. „ Bipatlal S/o Pirmoo
16. „ Phoolbhansa S/o Tulsi.
17. „ Sheolal S/o Jian.
18. „ Mumtajali S/o Ahasan Ali.
19. „ Guruprasad S/o Durghat.
20. „ Chunilal S/o Likhi Ram.
21. „ Harbans S/o Saran.
22. „ Purushotam S/o Mahatam.
23. „ Balkishan S/o Durjan.
24. „ Ramgopal S/o Haikya.
25. „ Bhimrao S/o Balakram.
26. „ Ramjan S/o Muna.
27. „ Ravi Shankar S/o Dawarka
28. „ Latif S/o Yannus Khan.
29. „ Manhaylal S/o Malukohand.
30. „ Nawal Kishore S/o Bhayalal.
31. „ Chandan S/o Deviddin.
32. „ Pancham S/o Rama.
33. „ Sheonath S/o Sheocharan.
34. „ Nijamuddin S/o Jhairuddin.
35. „ Sukhdayal S/o Ganaram
36. „ Vijabhadr S/o Ramnath.
37. „ Shyamlal S/o Premlal.
38. „ Satnaryan S/o Ramsewak.
39. „ Dukhi S/o Natnu.
40. „ Sukhdayal S/o Gopichand.
41. „ Dhanoo S/o Rama.
42. „ Babu S/o Baloo.
43. „ Goverdhan S/o Ramji.
44. „ Ramesh S/o Tulsiram.
45. „ Mohan S/o Rambaran.
46. „ Juber Ahamad S/o Bakriddi
47. „ Sudhichand S/o Hektar.
48. „ Ganesh S/o Hari.
49. „ Nanakram S/o Gorey.
50. „ Jairam S/o Heman.
51. „ Dhanlal S/o Kishanlal.
52. „ Sahadat S/o Sikandar Khan.

2. The case had been contested and was at the evidence stage. When on 28-6-1984 an application was filed duly signed by the representatives of both the sides that the case stands settled and that all the workmen have been taken on duty. Shri P. N. Srivastava, Senior Personnel Manager, Ambara Colliery, was examined and he stated that the parties have arrived at the settlement as per Ex M/1 The settlement is as under :—

- 1 That the workman Shri Sheonarain and 51 others mentioned in the order of reference shall be given employment on temporary basis w.e.f. 30-10-1983 as piece-rated workers in the temporary vacancies

wherever available in Kanhan Area which is likely to be extended from time to time.

2. They will not be paid any back wages or any other relief. The union gives up all other claim with reference to the dispute between the parties and shall not take up any demand in respect of matter under reference.

3. This is full and final settlement of the dispute under reference. The parties shall submit this agreement before the CGIT before 30-9-83 and pray for an award.

Parties agree that the award may be given. I, therefore, order that Shri Sheonarayan and 51 others mentioned in the schedule of reference shall be employed with effect from 30-10-1983 as piece-rated workers in the temporary vacancies wherever available in Kanhan Area. Their employment shall be on temporary basis but shall be extended from time to time. None of these persons so employed will be paid any back wages or any other relief. The Union foregoes all claim with reference to this dispute and shall not make any demand in respect of this matter any further. There shall be no order as to costs.

28-6-1984.

K. K. DUBE, Presiding Officer.
[No. L-22012(8)|82-D.IV(B)|D-V]

SO 2488.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Rare Earths Limited, Chavara and their workmen, which was received by the Central Government on the 11-7-84.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-11 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to Shri M. S. Panickers, Contractor to M/s. Indian Rare Earths Ltd., Chavara.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For Shri M. S. Panicker—No appearance.

For Indian Rare Earths Ltd.—Mr. K. V. R. Shenoy, Advocate.

For Travancore Mineral Works Union, Chavara—Mrs. Pushpa Metha, Advocate.

For Kerala Mineral Workers Congress, Chavara—No appearance.

For Kerala Minerals Employees Association, Chavara—No appearance.

STATE : Kerala

INDUSTRY : Mining

Bombay, dated the 3rd day of May, 1984

AWARD

By this reference under Section 10, sub-section (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the dispute between the mining workmen and their employer is referred to this Tribunal. The schedule of reference No. L-43011/3/76-D.II.B, dated 22nd June, 1977, is worded as follows :—

SCHEDULE .

“Whether the demand of the workmen engaged on mining work by Messrs Panicker, Mineral sand Supply Contractor to Messrs Indian Rare Earths

Limited, Chavara for payment of compensation from 17-7-1976 to 8-9-1976 both days inclusive, is justified ? If so, to what relief the workmen are entitled ?”

2. Notices were issued upon receipt of the reference to Mr. M. S. Panicker named as the employer in the reference and to the Secretary, Travancore Mineral Workers Union (hereinafter referred to as “the Union”). Two other unions figured in the reference order namely Kerala Mineral Workers Congress and Kerala Minerals Employees Association also at Chavara, district Quilon.

3. Pursuant to the notices as preliminary statement of claim was filed by the workmen represented by the union. It appears that at the initial stage no notice was sent to the other two unions viz., Kerala Mineral Workers Congress and Kerala Minerals Employees Association. The statement of claim describes the work which is done by these workmen. The work consists of scrapping and heaping sand washed on the shores by the sea which contains minerals processed by the Indian Rare Earths, which is a Public Sector company and belongs to the Government a company known as the Indian Rare Earths Ltd. The Indian Rare Earths Ltd., took over three companies viz., The Travancore Minerals Ltd., The Associated Minerals Ltd., and M/s. Hopkins & Williams Ltd., all three of which before their take over were closed.

4. The work of the workmen consists as stated above of scrapping and heaping of the sand which contain the rare mineral such as ilmenite, rutile, zircon, monazite, etc., and then to transport it either by trucks or by head-load to boats waiting at the loading place. The barges or boats then transport the loaded sands to the unloading point which is near the plant of the Indian Rare Earths. The unloading workman then convey the sand to the pit-head where the elevators of the plant lift the material and take it inside the plant for processing.

5. This work of mining of really scrapping, heaping, loading and unloading as well as transport of the sand to the loading point and to the pit-head used to be given under a contract by tenders. Tenders used to be invited and the Indian Rare Earths used to enter into contracts with these tenderers. Panicker was the successful tenderers for the previous year. For the period of 1st April 1976 to 31st March 1977 Mr. Panicker was the only tenderer. According to the union, Mr. Panicker was persuaded to undertake the work from June 1976 at a reduced rate than he had tendered. In July 1976 the contractor thought of having the workmen contrary to the former basis on the basis of weight at the weighing-bridge at the pit-head and not as before at the loading point. There were about 690 workmen in all employed in this work and though there were different tenderers or contractors the workmen had remained, according to the union, the same.

6. The projected mode of payment by Mr. Panicker would have resulted in loss to the workman by about 15 per cent. The workman resisted and a notice of change was issued by Mr. Panicker on 17th July, 1976, under Section 9-A. Ultimately, there was intervention and work was resumed on 8th September, 1976. The present reference, therefore, requires adjudication of this period of stoppage of work from 17th July 1976 to 8th September 1976 and fixation of liability for that period and compensation in that behalf.

7. A reply to this was filed by Mr. Panicker who complained that the order of reference was not served upon him, but filed his reply on the supposition that he was a party. He narrated the events leading to acceptance of work for the period 1976-77 at the rate which was formerly operative for the previous year. It may be mentioned that Mr. Panicker was also the contractor in 1975-76, that he was persuaded by the Managing Director, N. D. Hansotia to continue the work for a period of two months which he did upto 31-5-76. Thereafter, there were further negotiations, according to him, between Hansotia, himself and the union leaders and in the presence of the then Revenue Minister, Mr. Baby John, certain agreement was reached called by him “a gentlemanly understanding.” That it was not reduced to writing but according to him in view of the agreement Mr. Panicker

agreed to work at the reduced rate. The union agreed that the "workers need be paid only on the basis of the weight of the sand recorded by the weighing machine," and that the total lay off compensation would be limited to 45 days in a year and the contractor would not be subjected to arbitrary demands for payment on the basis of weight at the loading point.

8. According to Mr. Panicker, however, the workmen refused to follow this agreement when he started paying them in accordance with the pit-head weight and resorted to violence and lawlessness and that they insisted on payment on the basis of the weight of sand arbitrarily fixed by them at the loading point and forced Mr. Panicker to make payments by use of threats and force. Accordingly, he was forced to make payments from 9-6-1976 to 17-7-1976 of Rs. 7,152,89 in excess. That he repeatedly gave notice to the union reminding them of the agreement and asking them to accept payment accordingly and not to indulge in coercive practices which they refused, from 9-6-1976 to 17-7-1976, according to him, there were only 34 working days and on 17 days work could not be carried on because of the monsoon and bad weather.

9. On 17-7-1976 he says that the labour situation became explosive and uncontrollable and it was no longer possible for him to work any further. On 17-7-1976 he says "the workers manhandled my cashier and other staff." He, therefore, under these circumstances says "which were beyond my control, there was no other alternative except to force to stop work with effect from 19-7-1976." He then says accordingly he was forced to stop work "with effect from 19-7-76."

10. Mr. Panicker then refers to intervention proceedings by the Asstt. Labour Commissioner(C), Ernakulam, and discussion between the management, representative of the union and himself, but says that work was resumed as Onam which is a festival in Kerala was approaching fast and he was made to pay Rs. 150 to each worker before resuming the work. The Labour Commissioner had suggested by way of compromise that the period of stoppage of work should be treated as lay off which was limited to 45 days. As 17 days had already been lost, the lay off compensation to 28 days would have come to Rs. 140. According to him he has paid Rs. 10 in excess to the workmen. He therefore, submitted that there was no work between 19-7-1976 to 9-9-1976 and there was, therefore, no wages earned and no liability to pay.

11. It may be mentioned that the union in its statement of claim had also made a claim for payment of gratuity and provident fund, besides compensation for 57 days of stoppage of work as also arrears of wages from 6-6-1976 to 17-7-1976. In view, however, of the fact that the reference is limited only to compensation for work stoppage between 17-7-1976 to 8-9-1976 I have not to refer to these aspects of the matter.

12. The reference then dragged on until on the 22nd December, 1982, an application came to be made by the union to join Indian Rare Earths as a party "being the principal employer", and bound to pay the wages and all other legitimate dues to the workman". On the same day a writing was submitted by Mr. Panicker that the Indian Rare Earths be made as a party. Therefore, an order was passed by my predecessor on the 22nd August, 1983, impleading the Indian Rare Earths as a party. An additional written statement was then filed by Mr. Panicker alone saying that the Indian Rare Earths now does not give the mining work on contract and that most of the workmen have been absorbed by the company while the rest were retrenched. He stated that when he was a tenderer he was merely "working as an agent or supervisor of the company".

13. A written statement dated 18th August, 1983, and an objection application dated 19th September, 1983, came to be filed for setting aside the ex-parte order dated 22nd August, 1983, by the Indian Rare Earths. By this written statement, briefly stated, the company objected to the jurisdiction of the Tribunal and submitted that it was not a party and no dispute is to be adjudicated between it and the contractor. In terms of the contract the contractor is solely and exclusively responsible for the payment to the workmen. It also pointed out that the transaction between the workmen and the contractor was as between two independent principals, and as between itself and the contractor was also contract between two principals. That there can be no question of

Mr. Panicker being an agent or supervisor. That Mr. Panicker is not bankrupt, which is the reason alleged by the union in seeking to join the company at a party and that is also not a valid ground. The company has not taken over the business of Mr. Panicker, when it abolished the contract system and took over the mining work itself. That action would not make it a successor to the contract or the contractor, it was pointed out.

14. On behalf of the company its application for setting aside the ex-parte order was pressed. However, it agreed later to have the entire adjudication heard and the matter, therefore proceeded to trial.

15. On behalf of the parties a number of documents were filed to which it does not appear to be necessary to refer except a few. A number of documents were also filed on behalf of the company, but I do not propose to go to them in view of the award which I am making. I would only refer to the documents which, in my opinion, coped with the oral evidence, and want of any evidence from Mr. Panicker establish in my opinion that there was a lock out with effect from 17-7-1976 brought about by Mr. Panicker. Before proceeding to the inquiry an order was passed setting out the points of dispute to focus the attention of the parties in the matter of leading evidence. They are as follows :—

- "(1) Whether the stoppage of work between 17th July 1976 and 8th September 1976 was in the nature of lock-out or it was a lay-off ?
- (2) What amount in case it was a lay-off or lock-out by way of compensation will be justified to be paid to the employees ?
- (3) If point No. 2 is answered in the affirmative who is responsible for the payment of that compensation, whether the contractor or Indian Rare Earths Ltd.,?
- (4) Whether Shri Panicker was an independent Contractor or a mere agent of Indian Rare Earths Ltd.?"

Oral evidence was led on behalf of the union and the company. No evidence was led by Panicker.

16. I will firstly refer to the documents which throw light on the events leading to this stoppage of work from 17-7-1976. The first letter is dated 3-7-1976 addressed to the union which speaks of indiscipline amongst the workman and the manhandling of the cashier on that day. Mr. Panicker apprehended a law and order situation unless the union leaders intervened on the 17th July, 1976. He addressed another letter which does not speak of any violence or untoward incident, but merely refers to "contrary to prior understandings, many demands have been raised." He then informs the General Secretary of the union "that without definite understandings on the issues, there is no possibility of resumption of work. If work is to be resumed from Monday, urgent decisions has to be taken on this matter I have stopped working from Monday." It appears that 18-7-1976 was a Sunday and 19-7-1976 was a Monday. This letter of the 17-7-1976, therefore, clearly goes to show that Panicker decided to stop work from Monday, the 19th July. That was not because of any untoward situation, threat or violence or intimidation at least on 17th July though it appears that there was some trouble on or about the 3rd July, 1976. As to whether that trouble aggravated so as to meet the situation the employer was compelled to declare lock-out there is no further light. The employer Mr. Panicker has chosen not to go into the witness box and satisfied himself with the cross-examination of witnesses who gave evidence on behalf of the union. On behalf of the Indian Rare Earths evidence was led of the Divisional Manager, R. M. Pillai. But, his evidence is merely directed towards explaining the nature and relationship between the company and the contractor and the relationship between the workmen and the contractor. He merely stated that "there was no work between 17-7-1976 to 8-9-1976. That was on account of dispute between the contractor and the workmen." In his cross-examination he admitted that he was not present "on the 17th July, 1976, at the site," and did know "What happened." He stated that following what took place "on 17-7-1976 the contractor stopped giving work to the workmen till 8-9-1976."

17. The Union examined one P. K. Diwakaran, who was the Secretary of the union during the relevant period and one P. K. Kesavan, who was a tally clerk. Diwakaran was

cross examined by the counsel for Mr Panicker. According to Diwakaran the contractor stopped work on 17.7.1976. He then referred to the letter referred to above by me and in the cross examination he denied that the cashier was attacked by the workmen on 17.7.1976. It was suggested to him that 17th July was a pay day. He also denied any incident of gherao of the workmen to the contractor's employees at any time. His cross examination does go to show, however, that there was some dispute between the workman and Mr Panicker in regard to the mode of calculation of payment to the workmen.

18. The tally clerk examined on behalf of the union was admittedly present during the relevant period. His evidence as to what happened in June and July 1975 runs uncontradicted. He stated that there was dispute about the wage of the workmen from June 1976 and that the workmen were not prepared to accept the wage offered. According to him the contractor stopped work from 17th July 1977 and though the workers were ready to work on that day and the offer the contractor did not offer any work. Even he as a monthly rated employee did not get any wages. He was also subjected to cross examination by the counsel on behalf of Mr Panicker. He admitted that the dispute was over payment on the basis of the weightment noted in the company's premises. But he denied the suggestion that the workmen had "started gherao and other violent processes against the contractor's employees and cashiers". He denied also that the work was stopped because of the violent agitation and activities. His evidence was led on 22-3-1983. On that day Mr Panicker was present in the Court. After the union's evidence was over the counsel for Mr Panicker stated that he does not want to lead any oral evidence. The case was therefore adjourned for the company's evidence which was completed on the next day.

19. The position which emerges therefore is that on the part of the union evidence has been led to show that the work was stopped by the contractor unilaterally with effect from 19-7-1976. The documentary evidence coming from Panicker himself goes to show that he directed stoppage of work with effect from 19-7-1976. There is no reference to any untoward incident or violent activities or coercive tactics on behalf of the workmen on the 17th July though that was suggested to Diwakaran. A dispute appears to have existed between the workmen and Mr Panicker for payment of wages and the letter of the 3.7.1977 refers to some law and order situation and trouble. There is no evidence however to show that in fact there were any violent activities between 3.7.1976 to 17.7.1976 necessitating the stoppage of work. The absence of Mr Panicker from the witness box is significant. He has also not led any evidence such as by way of examining the cashier or other employees to indicate what was the situation which led to work stoppage by him on the 19th. 17th July 1976 was a Saturday and 18th July 1976 was a Sunday. Stoppage of work therefore was unjustified. It was an unjustified lock out on his part and he is therefore liable to pay compensation to the workmen for stoppage of work and illegal lock out between 19.7.1976 to 8.9.1976. The work was resumed on 8th July 1976. He will therefore be responsible for payment to the workmen for that period.

20. It is quite clear that the primary responsibility for payment to the workmen is that of Mr Panicker. The question whether his financial position is sound or otherwise is totally irrelevant at this juncture. It seems to me that the question whether Mr Panicker is a mere agent and whether the real liability was that of the Indian Rare Earths is a question which would require investigation and context acquiring a different dimension. It would require examination of further material and evidence. It would introduce subjects and matters which do not properly pertain to the terms of this reference. No question is required to be adjudicated in terms of the order of reference as to what is the real relationship between Mr Panicker and the Indian Rare Earths and whether the company would be ultimately liable to pay to workmen. I have already pointed out that Mr Panicker is liable to pay compensation to the workmen. If they are unable to recover that compensation they may raise a dispute later. With regard to the liability of the company I do not think that I should go into that question in this reference for the obvious difficulties indicated.

21. As regards the rate of compensation I direct that compensation should be paid to the workmen on the basis 486 GI/84—12

of their average earnings in the same period in the previous year i.e. 1975 and failing that material on the basis of the payments made to them for the months of April and May 1976.

22. Award accordingly. No order as to costs.

R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. 1-43011(3)/76 D IV(B) D V]
S. S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली 29 जन 1984

आदेश

का आ 2489—केंद्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट पैनाम्बूर के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच विद्यमान है—

और केंद्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है,

अतः केंद्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी. एन. लालगे होगे जिनका मुख्यालय बंगलूर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

'क्या न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष की न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में काम कर रहे आयल मैन सेरांग ग्रेड-1 लाच चाटवर ग्रेड 1, जमादार सफाईवाला खलासियों और हैल्परों के वेतनमानों को तुलनात्मक पोर्ट ट्रस्ट में वर्तमान वेतन मानों के बराबर करने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायचित है और यदि नहीं तो उक्त कर्मचारियों किस तारीख में किस अनुपात के हकदार हैं ?

[मं. एल-45012/1/84-डी-4 (ए)]

New Delhi the 29th Jun, 1984

ORDER

SO 2489—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of New Mangalore Port Trust, Panambur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Dispute Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Lalage shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Chairman of New Mangalore Port Trust in refusing to revise the pay scales of the Oilmen, Serang, Gr. I Launch Driver, Gr. I, Sweepers, Cleaners, Khalasies and Helpers working in New Mangalore Port Trust on par with those existing in Tuticorin Port Trust is justified and if not to what relief the said workmen are entitled to and from what date?"

[No. L 45012/1/84/D-IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1984

का.प्र. 2490—केन्द्रीय सरकार की राय है कि हमारे उपावह अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट मंगलोर के प्रबंधन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी. एन. लालगे होंगे जिनका मुख्यालय बंगलोर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करनी है।

अनुसूची

"क्या न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट मंगलोर के प्रबंधन द्वारा अनुरक्षणी प्रभाग, में लगे कर्मकारों जैसे माली-एवं-मजदूर, हैल्पर, मकई वाला और वाटर सप्लायर, बर्हगिरि, राजगिरि, चित्रकारी आदि कामों में लगे अन्य कर्मकारों को रेत फोट बी सप्लायर बन्द करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[न एल-45011/17/83-डी-4 (ए)]

एन के. वर्मा, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 30th June, 1984

S.O. 2490.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of New Mangalore Port Trust, Mangalore and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Lalage shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of New Mangalore Port Trust, Mangalore, is justified in discontinuing the supply of rain coats to the workmen engaged in the maintenance division viz. Mall-cum-Mazdoor, Helpers, Safarwala, and others, in water supply, carpentry, Masonry, Painting, etc. If not, to what relief the said workmen are entitled?"

[No 1-45011/17/83-D.IV(A)]

N. K. VERMA Desk Officer

New Delhi, the 13th July, 1984

S.O. 2491.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the Industrial dispute between the employers in relation to the Canara Bank, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th July, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 BOMBAY

Reference No. CGIT-32 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to Canara Bank,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. P. Ramaswami, Advocate.

For the Bank Staff Union—Mr. Madan Phadnis, Advocate.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay, the 30th day of March, 1984

ORAL AWARD

By this reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the action of dismissal of the workman, S. A. Kokane, of the Canara Bank is placed for adjudication. The reference is in these terms —

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Canara Bank Bombay, in relation to their Goregaon West Branch in dismissing Shri S. A. Kokane, Clerk, from the Bank's service is justified? If not, to what relief Shri S. A. Kokane is entitled?"

2. The workman, Kokane, was an employee of the Canara Bank and was employed between 1977 April to 23rd February 1978 as a Clerk-cum-Cashier at the Kirkee branch of the Canara Bank. He was then transferred to Goregaon, Bombay. While he was working as Cashier-cum-Clerk in the Kirkee branch certain acts of misconduct were noticed as having been committed by him in respect of which he was served with a chargesheet. An inquiry was held thereafter on the basis of that charge-sheet into the three misconduct said to have been committed by him, and after conclusion of the inquiry the management of the Canara Bank decided to terminate his services and accordingly dismissed him from service with effect from 19-2-1979. The said order of dismissal was challenged by the workman. Conciliation proceedings did not result in any settlement and a reference came to be made and that is how it is now before us.

3. The workman contended that the charge-sheet dated 26th April, 1978, charged the workman with three misconducts, one relating to a payment dated 13-12-1977, the second relating to a payment dated 12-2-1978. In all those the workman was charged with having retained a sum of money with him belonging to the customer and not reporting it to the bank of the same, and thus committed misconduct as contemplated within the meaning of Chapter XI Regulation 3 clause (m) of the Canara Bank Service Code which is a gross misconduct viz wilfully causing damage to the property of the customer and acting in a manner prejudicial to the interest of the bank.

4. According to the workman, the inquiry officer found the workman not guilty of the charge No. 1. He found him guilty of the charges Nos. 2 and 3 and recommended stoppage of one increment so far as the second charge was concerned and dismissal so far as the third charge was concerned. These findings so far as the second charge was concerned were characterised by the Union as being preferred. These findings so far as the second charge was concerned while in the case of third charge-sheet it was pointed out that the workman had received a message on that day his uncle had expired and that in that disturbed state of mind the alleged misconduct was possible to have occurred.

5. Besides, it was contended that the charge originally mentioned the date of the incident as 21-1-1978 and not 21-2-1978. That there were several irregularities in the framing of the charge and the conduct of the inquiry the proceedings were violative of the principles of natural justice and was a mere empty formality. The workman was not supplied with certain documents such as Canara Bank Service Code, as also a letter which was produced before the inquiry officer. Besides, there were other allegations that the inquiry officer was biased and prejudiced and acted more as a prosecutor than as an inquiry officer and that the principles of natural justice were not followed. He heard the workman on the question of punishment also though he had no power to do so and also imposed the punishment.

6 On the other hand, the bank contended in its written statement that the workman was given a charge-sheet and was called upon to submit his explanation. The workman failed to give any explanation to any charges. The inquiry, therefore, was held from 12th September, 1978, after giving him full opportunity. The workman participated in the inquiry and was presented by a Union representative. That he had cross-examined the witnesses and has given his own evidence. That the inquiry officer had recommended the punishment which should be given and had not imposed the punishment or effected the punishment himself. That he had found him not guilty of charge No. 1 and in respect of charge No. 2 suggested that his increment should be stopped for a period of six months and in regard to the third charge being of a grave type that the workman should be dismissed. The management accepted the findings of the inquiry officer and dismissed the workman. That there was no error or violation of any principles of law or natural justice during the inquiry and looking to the serious and grave misconduct committed by the workman the punishment awarded to him was proper.

7. Since a contention was raised that the inquiry was not fair and proper and that the principles of natural justice has been violated that was considered as a preliminary question by my learned predecessor. By his order dated 3rd August, 1983 he overruled the contentions urged on behalf of the workman, including that relating to non-supply of documents and copy of letter dated 8-3-1978. He held finally that the inquiry was fair and proper and in conformity with the principles of natural justice. What remains, therefore, thereafter is to see whether the action of dismissal was justified.

8. Mr. Phadnis appearing for the workman did not seriously controvert the facts which were established in the inquiry. His contention was that on the facts established the conclusion reached by the inquiry officer that the workman was guilty of gross misconduct viz., wilfully causing damage to the property of the customer and was not clearly and beyond a reasonable doubt established. He contended that with regard to charge No. 1 the workman had been exonerated. With regard to charge No. 2 the punishment proposed was only stoppage of increment for a period of six months and cannot be any stretch of imagination be considered as gross misconduct. Besides, he submitted that the bank did not indicate that a sum of Rs. 5 had been temporarily misappropriated by the workman.

9. With regard to the third charge Mr. Phadnis' contention was that considering the circumstances which had been established and which are not in dispute, the workman was and must have agitated in an agitated state of mind on 21st February, 1978. He was to leave immediately for the funeral of his uncle and left the bank in a hurry and he may not have remembered to report the excess of Rs. 200 received. That the amount had been made good by him immediately and directly to the party concerned. Under the circumstances, wilful loss of the property of the customer is not caused and in any event the punishment of dismissal is harsh.

10. For the bank Mr. Ramaswami contended that the incident of the 21st February, 1978, should not be looked at in isolation. There was an earlier incident on 31st December, 1977, though in respect of that the workman had been exonerated. This was followed with the second incident of the 12th February, 1978, and the third on the 21st February, 1978. He pointed out that the incident of 13-12-1977 came to light only later. That though the workman has been exonerated, the modus operandi seems to be familiar and similar. There also a sum of Rs. 100 was received by him in excess even as admitted by the employee. He reported, however, excess cash of Rs. 49.50 only it was only at a late stage when the customer complained in February that he made good the amount of Rs. 50.50. He stated that the bank did not challenge the fact that the workman had a call on account of the death of his uncle and left the bank on 21st. It was, however, submitted that if the workman was honest the cash of Rs. 200 would have remained in the cash-box or could have been then and there, in the circumstances which are brought out, returned to the customer by the workman. He also urged that the bank is handling the money of the customers, the workman could not be trusted and had lost the confidence of the bank. If he could not be trusted with money which was what the bank

dealt in then the workman was hazardous risk to the organisation and was properly got rid of him.

11. Considering all the facts of the case it may be mentioned that on the 21-2-1978 the workman had received a paying-in-slip from Ammunition Factory Canteen which showed a remittance of Rs. 679. However, that was on account of a mistake in totalling which is also admitted by the workman. The denomination of notes in the paying-in-slip is four notes of rupees 100, eight notes of rupees 50, one note of rupee 10, four notes of rupees 5, six notes of rupees 2 and 37 notes of rupees 1. The total should be Rs. 879. But it was shown as Rs. 679 because the eight notes of rupees 50 were totalled as 200 only. The workman admittedly corrected it from 8 to 4 so as to bring it in conformity with the total of Rs. 679 but admitted having received Rs. 200 more i.e. Rs. 879.

12. It is true that the workman made good that amount to the Canteen. But it is not correct that he made it good directly even before any complaint was received. The letter dated 8-3-1978 which was produced during the inquiry, if it is perused it will be seen that the incident of the 21st February, 1978 in connection with the amount of Canteen was also brought up to the bank on the 23rd. Mr. Srinivas Rao in his letter dated 8th March, 1978, says "that on 23-2-1978 when the Manager brought the slip of the canteen in question he (Kokane) denied having received any excess cash". When it was pointed out that the workman had altered the number of notes of Rs. 50 from 8 to 4 in order totally he had no explanation to offer. The complaint of the Ammunition Factory was also made on the 23-2-1978. Therefore, whatever payment was made directly by the Ammunition Factory Canteen authorities was made only on the 23rd February and not before. Kokane's statement before the inquiry officer is as follows :-

"Q.—Was there any excess cash received by you on 21-2-1978 ?

Ans.—Yes, Rs. 200 was received by me.

Q.—On 23-2-1978 anybody came claiming Rs. 200 excess paid on 21-2-1978 ?

Ans.—Yes, I paid Rs. 200 on 23-2-1978.

Q.—Did you admit your guilt of Rs. 200 with DM ?

Ans.—Is it true that you altered the denomination in the slip dated 21-2-1978 ?

Ans.—Yes, I altered."

13. It is, therefore, quite clear that the workman had Rs. 200 with him which was the customer's amount which he kept with him for two days, and it was only on the 23rd February, 1978, when the customer came claiming this amount of Rs. 200 and when probably he was confronted with his own alteration in the paying-in-slip that the workman paid Rs. 200 directly to the concerned customer.

14. This conduct of the Clerk-cum-Cashier is clearly dishonest. It was a conduct with regard to the customer's property and has caused damage to the customer. The other two instances of the 13-12-1977 and 12-2-1978 viewed in this light disclose a similarity of operation. There also a wrong total is allowed to remain pocketing the excess amount though the excess was tendered. The workman was not honest to return that excess amount. Even with regard to the first incident of 13-12-1977 he reported the excess cash only of Rs. 49.50 in the evening. The payment admittedly was made and the fact was not disclosed in the morning session at which time he should have reported the excess cash of Rs. 100 when he tallied the cash. After all what was the intention of the workman in keeping the cash and not reporting it cannot be demonstrated. It has only to be inferred from the express conduct of not reporting the excess cash to the Manager and making good the loss only when he was found. I do not think that in the circumstances it can be said that the findings of the inquiry officer were in any way erroneous or were not fully justified on the facts established. In the circumstances also and particularly since the payment of Rs. 200 was made only on the 23rd February, 1978, after the complaint, I am not inclined to interfere even under Section II-A with the punishment meted out to the workman. The reference must be answered in the affir-

mative and against the workman, and it must be held that the action of the bank in dismissing the workman is justified.

15. Accordingly. No order as to costs.

R. D. TULPULE, Presiding Officer
[No. L-12012/47/80-D II (A)]

New Delhi, the 20th July, 1984

S.O. 2492.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Bangalore in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India, Bangalore-1 and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th July, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated : This the 29th day of June 1984

Central Reference No. 6 of 1984

I-Party

The Secretary, Union Bank of India Employees Association, C/o Union Bank of India, No. 582; Avenue Road, Bangalore-2.

Vs.

II-Party

The Assistant Superintendent (Personnel), Union Bank of India, Zonal Office, South II ; 'Chandrakiran'; 10-A, Kasturba Road, Bangalore-1.

APPEARANCES

For the I-Party—Sri N. Sampath Kumar, Advocate, Bangalore.

For the II-Party.—Sri S. N. Murthy, Advocate, Bangalore.

AWARD

The Government of India, by its order No. L-12012/202/83-D.II(A), dated 2nd February 1984, has made the present reference on the following points of dispute :—

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Bangalore in relation to their Zonal Office, South Zone II, Bangalore in terminating the services of Shri S. Muniyappa, Peon-cum-Watchman, with effect from 19-8-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled".

2. Thereupon the parties were called upon to file their pleadings. The I-Party union had filed its claim statement and the matter was called today for the filing of the counter statement by the II-Party.

3. A joint memorandum of settlement has been filed by both the parties. It has been signed by the Secretary of the I-Party union and also by the concerned workman Shri S. Muniyappa on the one hand and for the management, it has been signed by the Superintendent (Personnel) of the II-Party and also by their Advocate.

4. By the settlement, the workman has been reinstated with continuity of service and the only disadvantage is that, he is not getting his back wages. Since the workman has been reinstated, I find that the settlement is beneficial to the workman. It is accepted.

5. An award is passed in terms of the settlement. The said settlement shall form part of the award.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

B N. LAI AGE, Presiding Officer
[No. L-12012/202/83-D.II(A)]
N. K. VERMA, Dsk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL BANGALORE

Central Reference No. 6 of 1984

I PARTY :

The Secretary,
Union Bank of India Employees'
Association,
C/o Union Bank of India,
No. 582, Avenue Road,
Bangalore.

Vs.

II PARTY :

The Asst. Superintendent (Personnel),
Union Bank of India,
Zonal Office,
Bangalore.

JOINT MEMORANDUM OF SETTLEMENT

The parties to the above dispute have discussed the issues arising out of the dispute and have settled the dispute on the following terms and conditions :

TERMS AND CONDITIONS

1. The second party has agreed to take back the first party Sri S. Muniyappa into its service on the last basic pay drawn by him at the time of his abandoning of service.

2. The first party shall not be entitled to any back wages, consequential benefits and/or any other monetary benefits for the period between 13th July 1981 and till the day he reports for duty consequent to this settlement.

3. The period between his voluntarily abandoning employment and the date he reports for work which shall not be later than 8 days from the date of this settlement shall be treated as extra-ordinary leave on loss of pay.

4. The first party workman shall be bound by the rules and regulations of the Bank applicable to the workmen from time to time.

5. This settlement has been entered into in view of the special request made by the Union and shall not constitute a precedent for any future Industrial Disputes.

6. The parties pray that this Hon'ble Court may be pleased to pass a consent award in terms of this Settlement in the interest of justice.

Sd/-
(Superintendent (P)
Second Party
Sd/-
Advocate for
Second Party
Sd/-
(Secretary)
First Party
Sd/-
(S. MUNIYAPPA)

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1984

आदेश

का० आ० 2493.—बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धनत्व से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन बम्बई और जनरल सेक्रेटरी बी०पी०टी० ईम्प्लॉईज यूनियन बम्बई करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थ्य के लिए

निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को जो उसे 2 जुलाई 1984 को मिला था एतद्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)
पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री आर० यू० पाई०, सेक्रेटरी
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री एस० आर० कुलकर्णी, सेक्रेटरी
ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स
यूनियन बम्बई।
2. श्री एस० के० शेट्यु, जनरल सेक्रेटरी
बी०पी०टी० इम्प्लोईज यूनियन
बम्बई।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एफ०एच० लाला 102 सप्तफलावर 99कुफे पैरेय रेक्लेमेशन कोलाबा बम्बई-400005 के माध्यस्थता के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(1) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय क्या बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लोको ग्राइवर्स और लोको फायरमैन की यह मांग कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे आप-रेशनल क्षेत्रों की सुरक्षा उक्त क्षेत्रों में अप्राधिकृत हॉपडियों के कारण इतनी बिगड़ गई है कि प्रत्येक कनेडियन और हेन्सचेल लोकों में एक अतिरिक्त कर्मकार की जरूरत है न्योचित है और क्या इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए? यदि हाँ तो वह अतिरिक्त कर्मकार किस श्रेणी में होना चाहिए?

(2) विवाद के पक्षकारों का बम्बई पोर्ट का न्यासी बोर्ड, विवरण जिसमें अंतर्बलित पोर्ट ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापन या उपक्रम का नाम आफिस धूरजी बल्लभदास और पता भी सम्मिलित है। मार्ग बम्बई-400038 ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन पी०डी० मेलो

भवन, पी० डी० मेलो रोड
बम्बई-400 038 बी०
पी० टी० इम्प्लोईज यूनियन
पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन
नवाब टैन्क रोड मजागांव
बम्बई-400010
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मेकेनिकल
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के
लोकोशेड प्रतिष्ठान के
लोको ग्राइवर्स और लोको
फायरमैन की ओर से।

- (3) यदि कोई संघ प्रश्नागत कर्म- ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स
कारों का प्रतिनिधित्व करता यूनियन पी० डी० मेलो रोड
हो तो उसका नाम बम्बई-400 038 बी०पी०
टी० इम्प्लोईज यूनियन
पोर्ट ट्रस्ट कामगार यूनियन
नवाब टैन्क रोड मजागांव
बम्बई-400 010
- (4) प्रभावित उपक्रम में नियो- 31 000
जित कर्मकारों की कुल
संख्या
- (5) विवाद द्वारा प्रभावित या 115
सम्भाव्यतः प्रभावित होने
वाले कर्मकारों की प्राक्क-
लित संख्या

माध्यस्थ अपना पंचाट सरकार द्वारा इस करार को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर देगा जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थता के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थता के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
ह०/- (आर० यू० पाई) सेक्रेटरी बम्बई पोर्ट ट्रस्ट यूनियन।	ह०/- एस० आर० कुलकर्णी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन ह०/- एस० के० शेट्यु, जनरल सेक्रेटरी बी०पी०टी० इम्प्लोईज यूनियन।

साक्षी

1. ह०/- एस० आर० मसुरकर
2. ह०/- श्रीमती एस०पी० चनकर

मध्यस्थ की सहमति

मुझे प्रसन्नता है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और उनके रेलवे कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) II बम्बई के समक्ष सराफन कार्यवाहियों में 29 नवम्बर, 1983 को हुए समझौते के अनुसार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स यूनियन और बी०पी०टी० इम्प्लोईज यूनियन ने मुझे मध्यस्थ के रूप में स्वीकार

किया है और उन्होंने उक्त विवाद को भेरे माध्यस्थ के लिए भेजने का करार किया है।

मैं मध्यस्थ का कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ह०/—(एफ० एच० लाला), मध्यस्थ
[स० एल-31013/3/84-डी-4(ए)]
एस० एस० पराशर डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 7th July, 1984

S O. 2493 —Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen represented by Secretary, Transport & Dock Workers' Union, Bombay and General Secretary, B.P.T. Employees' Union, Bombay.

And Whereas, the said employers and their workmen have by written agreements under sub-section (1) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement,

Now Therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 2nd July, 1984

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)
Between

Names of the parties :
Representing employers
Representing workmen

Shri R. U. Pai, Secretary, Bombay Port Trust
Shri S. R. Kulkarni, Secretary, Transport & Dock Workers' Union, Bombay.
Shri S. K. Shetye, General Secretary, B.P.T. Employees' Union, Bombay.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri F.H. Lala, 102, Sunflower, 99, Cuffe Parade Reclamation, Colaba, Bombay-400005

(i) Specific matters in dispute.

"Whether the demand of the Loco Drivers and Loco Firemen of the Bombay Port Trust that security of the Bombay Port Trust Railway operational areas has so much deteriorated as a result of unauthorised hutments in the said areas that there is a need for an additional workman on every Canadian and Henschel Loco is justified and should be implemented? If so, in which category should that additional workman be?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

Board of Trustees of the Port of Bombay, Port Trust, Administrative Offices, Shri Vallabhdas Marg, Bombay-400038.

Transport & Dock Workers' Union P.D., Mello Bhavan, P.D. Mello Bhavan, Bombay-400038.

B.P.T. Employees' Union, Port Trust Kamgar Sadan, Nawab Tank Road, Mazagaon, Bombay-400010.

on behalf of Loco Drivers and Loco Firemen of the Loco Shed establishment of the Mechanical Engineering Department of the Bombay Port Trust

(iii) The name of the Union, if any, representing the workman or workmen.

Transport & Dock Workers' Union, P.D. Mello Bhavan, P.D. Mello Road, Bombay-400038.

B.P.T. Employee's Union, Port Trust Kamgar Sadan, Nawab Tank Road, Mazagaon, Bombay-400010.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.

31,000

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute

115.

The arbitrator shall make his award within a period of three months from the date of publication of this agreement in the official Gazette by the Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signatures of the parties.

Representing employer :

(R.U. PAI)
Secretary, Bombay Port Trust.

Representing workmen :

(S.R. KULKARNI)
Secretary, Transport & Dock Workers' Union.
(S.K. SHETYE)
GENERAL SECRETARY, B.P.T.
Employees' Union.

Witnesses :

- (1) S.R. Masurekar
(2) Smt. S.P. Chankar.

Consent of the Arbitrator

I am glad that pursuant to the settlement arrived at on 29th November 1983 in the Conciliation proceedings before the Asstt. Labour Commissioner (Central)-II, Bombay, in the industrial dispute between the B.P.T. and their Railway workmen, the B.P.T., the T. & D. Workers' Union and the B.P.T. Employees' Union have accepted me as an Arbitrator and agreed to refer the said dispute for my arbitration.

I am agreeable to undertake the arbitration work.

(F.H. LALA)
Arbitrator.

[No. L-31013/3/84-D-IV(A.)]
S.S. PRASHER, Desk Officer,

नई दिल्ली 11 जुलाई 1984

का०आ० 2494.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम 1957 के विनियम के 11 उपविनियम (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1589 तारीख 5 मई 1981 को अधिकांत करते हुए खनन परीक्षा बोर्ड गठित करती है जिसके अध्यक्ष मुख्य खान निरीक्षक होंगे और निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उस बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. मुख्य खान निरीक्षक (पदेन) अध्यक्ष

2. श्री एस० एन० सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड
सेक्टरिया डा० घ० डिसेर-
गढ़ जिला बर्दवान।

3. श्री डी०वी० लक्ष्मणन्
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक
वैस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड
कोल एस्टेट सिविल लाइन्स
नागपुर-440001

4. श्री आर० के० गुप्ता सदस्य
अध्यक्ष सह-प्रबंध
निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि०,
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय
श्रम विभाग

5. श्री डी० वी० परमंजो
कार्यपालक निदेशक
सिंगरेजी कोलियरीज कम्पनी
लिमिटेड
बेलम्पल्ली-504251

6. प्रो० जी० एस० मरवाहा सदस्य
निदेशक भारतीय खान
विद्यालय
धनबाद-626004

[सं० वी० 23012/1/84-एम आई]
एल० के० नारायणन अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 1984.

S.O. 2494.—In exercise of the powers conferred by sub regulations (1), (2) and (3) of regulation 11 of the Coal Mines Regulations 1957 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 1589 dated the 5th May, 1981 the Central Government hereby constitutes the Board of Mining Examinations with the Chief Inspector of Mines as its Chairman and appoints the following persons as members of that Board for a period of three years namely :—

- | | |
|--|----------|
| 1. Chief Inspector of Mines
(ex-officio) | Chairman |
| 2. Shri S.N. Singh,
Chairman-cum-Managing Director,
Eastern Coalfields Limited,
Santoria, P.O. Disergarh,
District Burdwan. | Member |
| 3. Shri T.V. Lakshmanan,
Chairman-cum-Managing Director,
Western Coalfields Limited
Coal Estate, Civil Lines,
Nagpur-440001. | |
| 4. Shri R.K. Gupta.
Chairman-cum-Managing Director
Bharat Coking Coal Limited
Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad. | |
| 5. Shri D.V. Pranjpe
Executive Director,
The Singareni Collieries Company
Limited,
Belampalli-54251. | |

6. Pro. G.S. Marwaha,
Director,
Indian School of Mines,
Dhanbad-626004.

Member

के वर्तमान कार्यभार भी निभाने के लिए नियुक्त करती है जब तक कि नियमित पदधारी की नियुक्ति नहीं हो जाती।

[संख्या ए-1202/61/84-एच. आई. (पार्ट)]

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

[No. V-23012/1/84-M-I]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 13th July, 1984

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

का.प्रा. 2495—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 16 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वित्तीय सहायक और मुख्य लेखा अधिकारी, श्री एम. एम. माथुर को, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, 2 जुलाई, 1984 के पूर्वार्द्ध से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के पद

S.O. 2495.—In pursuance of section 16 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government appoints Shri M. M. Mathur, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Employees' State Insurance Corporation to look after the current duties of the post of Director General, Employees' State Insurance Corporation with effect from the forenoon of 2nd July, 1984 in addition to his own charge pending appointment of a regular incumbent.

[No. A-12026/1/84-HI (Part)]

CHITRA CHOPRA, Director